चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 21 दिसंबर–27 दिसंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सरकार और भाजपा से नाराज़ है आरएसएस

फोटो : प्रभात पाण्डेय

“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ लोग इन दिनों थोड़ा दुखी हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार उनके मन मुताबिक नहीं चल रही है. सरकार कुछ अलग तरह से चल रही है और संघ के लोग इसे कुछ अलग तरह से चलते देखना चाहते थे. उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस आशा में जी-जान लगाकर सरकार बनाई, सरकार उससे कुछ अलग दिशा पकड़ चुकी है. सरकार ही नहीं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी दिशा पकड़ चुकी है जहां संघ का रास्ता कभी नहीं मिलता. संघ के लोग महसूस करते हैं कि जहां सारी दुनिया संघ को विश्व का सबसे बड़ा अनुशासित संगठन मानती है, वहीं कुछ लोग इसे आईएसआईएस का हिंदू स्वरूप भी कहने लगे हैं. लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं है. उन्हें इस बात का गर्व है कि जब भी राष्ट्रीय आपदा आती है, तब उनके स्वयंसेवक वहां खड़े दिखाई देते हैं. उदाहरण के रूप में वे चेन्नई की बाढ़ को बताते हैं. जहां सबसे पहले उनके स्वयंसेवक लोगों को बचाते या सहायता पहुंचाते दिखाई दिए. उन्हें इस बात का भी गर्व है कि जहां एक तरफ उनके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय आपदा के समय उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना स्वरूप 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं आमंत्रित किया था. संघ के लोगों को इस बात का भी गर्व है कि उनकी सरकार कहीं रहे या न रहे, वे राष्ट्रीय आपदा के समय हर जगह मुस्तैद रहते हैं. उन्हें इस बात का गर्व है कि सभी धर्मों और पथों को मानने वालों ने कभी न कभी उनकी प्रशंसा की है.”

संतोष भारतीय

संघ के आदि सरसंघचालक श्री हेडगेवार माने जाते हैं. श्री हेडगेवार संघ के निर्माता भी हैं, इसीलिए उन्हें आदि सरसंघचालक कहते हैं. अपनी मृत्यु से पहले श्री हेडगेवार, गुरु गोलवलकर जी को संघ का सरसंघचालक नियुक्त कर गए थे. गुरु गोलवलकर को आमतौर पर संघ में गुरुजी का आदर सूचक विश्लेषण मिला हुआ है. संघ के लोग गुरुजी को संन्यासी या ऋषि मुनि की श्रेणी का मानते हैं. आज देश भर में संघ के जितने भी प्रकल्प चल रहे हैं, वे गुरुजी की संघ को देन हैं. चाहे वह विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम या भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबके पीछे गुरुजी का दिमाग और कल्पना थी. आज की भारतीय जनता पार्टी का गुरुजी का संस्करण जनसंघ के रूप में शुरू हुआ था. जनसंघ बनाने की पहली बैठक में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री दीन दयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी उपस्थित थे. श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा अन्य सभी संघ के प्रचारक थे. पहली बैठक में गुरुजी ने कहा, आप सब अच्छी तरह समझिए कि हम राष्ट्रवादी संगठन हैं. हमारे राष्ट्र की जड़ें मजबूत हों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक राष्ट्र का स्वरूप तैयार हो. हमारा देश पुन: अपने वैभवशाली स्वरूप को प्राप्त करे. इसके लिए मान्यताएं बनाना और कोई हमें गलत न समझे, इसके लिए राजनीति में हमारा हस्तक्षेप अति आवश्यक है. इसी हस्तक्षेप को आधार बनाकर गुरुजी ने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया. भारतीय जनसंघ सन 1967 तक बहुत प्रभावशाली ढंग से चला. भारतीय जनसंघ में संघ ने अपने महत्वपूर्ण लोगों को भेजा और उन्होंने भी जी–जान लगाकर भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाया. उदाहरण के रूप में भैरो सिंह शेखावत का नाम लिया जा सकता है. वह राजे–रजवाड़े परिवार से संबंधित थे. लेकिन संघ ने जब भूमि सुधार की बात स्वीकार की तो भैरो सिंह शेखावत ने अपनी सारी जमीन दान कर दी थी.

संघ का दर्द

यहीं से संघ के वरिष्ठ लोगों का दर्द शुरू होता है. उन्हें याद है कि जब–जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सत्ता मिली, तब–तब भारतीय जनता पार्टी भटकी. भाजपा में भेजे गए संघ के लोग जान–बूझकर भटके, अनजाने में भटके, मजबूरी में भटके, लेकिन जब भी भटके उनका चरित्र देश के लोगों को अचानक कांग्रेस के मूलभूत चरित्र के समान दिखाई दिया. संघ के लोग याद करते हैं कि भारतीय राजनीति के सबसे प्रमाणिक और ज्ञानवान राजनीतिक चिंतक आचार्य विष्णु गुप्त (चाणक्य) थे. चाणक्य स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त के पास वेश्याओं को भेजते थे. उनका मानना था कि राजनीति में जो व्यक्ति जाते हैं वे तामसिक होते हैं, यदि उनकी वह तामसिक वृत्ति बाहर न निकले तो वे सत्ता पर बोझ बन जाते हैं. इन्हीं मान्यताओं के कारण चाणक्य चंद्रगुप्त के पास वेश्याओं को भेजते थे. संघ के लोग कहते हैं कि अब हम भाजपा नेताओं के पास वेश्याओं को तो भेजने से रहे, लेकिन हमने एक दूसरा रास्ता निकाला है. हम जिन्हें भी भाजपा में भेजते हैं, उन्हें वापस संघ में नहीं लेते. जब हमने इसका संपूर्ण आकलन किया, तब हमें लगा कि यह तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. संघ ने अपने पूर्णकालिक उद्देश्यों को कई बार परिभाषित किया है, जैसे धारा 370 हटनी चाहिए, अयोध्या का राम मंदिर बनना चाहिए, गो–हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगना चाहिए. संघ की मान्यता है कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो हर एक व्यक्ति को, पेड़–पौधों को, प्राकृतिक संसाधनों को पूर्ण रूप से जीना चाहिए.

संघ के उद्देश्यों के विपरीत काम

संघ के लोग याद करते हैं कि संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर केंद्र में अब तक दो सरकारें आईं. पहली श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसे वे अस्सी प्रतिशत अपनी मानते हैं, क्योंकि वह गठबंधन सरकार थी.

संघ के लोग कहते हैं कि मोदी ने देश में बने उत्पादों को सहारा देने और स्वदेशी माल को संरक्षण देने की जगह 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश(एफडीआई) के रास्ते खोल दिए. उन्होंने देश में यूरोपीय देशों सहित संपूर्ण पश्चिमी देशों के लोगों के आने के सारे दरवाजे खोल दिए. संघ के लोगों को इस बात का दुःख है कि जो काम कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाई या मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां सन 1990 से 2014 तक जिस चीज को करने में हिचकती रहीं और नहीं कर पाईं, उसे नरेन्द्र मोदी और अरुण जेटली की सरकार ने डेढ़ साल में आसानी से कर दिया.

दूसरी श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है, जो सौ प्रतिशत संघ की कोशिशों की वजह से सत्ता में आई और जिसके पास पूर्ण बहुमत है. संघ के लोग आपस में ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये दोनों सरकारें, जिन्हें हमारी सरकार माना जाता है, हमारे उद्देश्यों को पूरा कर पाईं या उनकी स्थिति चिराग तले अंधेरे वाली हो गई है. संघ जलता रहे, दिये की तरह उजाला करता रहे और उसके नीचे लोग उसके उद्देश्यों के विपरीत सारे उल्टे काम करते रहें. नरेन्द्र मोदी के डेढ़ साल के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान को गालियां देने से लेकर पाकिस्तान से हाथ मिलाने तक, वो सभी काम हुए, जो संघ की परिभाषा और मान्यता के विपरीत थे. संघ का उद्देश्य था कि भारतीय समाज जो वस्तुएं बनाता है, उन्हें संरक्षण मिले, जिससे जनता को काम या रोजगार मिले. संघ का उद्देश्य था कि सभी लोग सामाजिक समरसता से चलें, हिंदू विचार चिंतन आगे बढ़े, अयोध्या का राम मंदिर बने, पूरा देश एक हो और कॉमन सिविल कोड हो. धारा 370 हटे और कश्मीर देश की मुख्य धारा में आए. विस्थापित कश्मीरी पंडितों को पुन: स्थापित किया जाए, लेकिन मोदी सरकार इनके विपरीत काम कर रही है. संघ के लोग कहते हैं कि मोदी ने देश में बने उत्पादों को सहारा देने और स्वदेशी माल को संरक्षण देने की जगह 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश (एफडीआई) के रास्ते खोल दिए. उन्होंने देश में यूरोपीय देशों सहित संपूर्ण पश्चिमी देशों के लोगों के आने के सारे दरवाजे खोल दिए. संघ के लोगों को इस बात का दुःख है कि जो काम कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाई या मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां सन 1990 से 2014 तक जिस चीज को करने में हिचकती रहीं और नहीं कर पाईं, उसे नरेन्द्र मोदी और अरुण जेटली की सरकार ने डेढ़ साल में आसानी से कर दिया. 15 क्षेत्रों में एफडीआई खोलने को लेकर संघ काफी परेशान है. वह रेलवे में विदेशी निवेश खोलने से और अधिक परेशान है. फ्रांस की कंपनी देश में लोकोमोटिव कोचेज बनाएगी. संघ के लोग कहते हैं कि आखिर रेलवे कोच बनाने के लिए ऐसी कौन सी महान तकनीक की आवश्यकता है, जो हमारे देश के लोग नहीं बना सकते. इन्होंने (मोदी सरकार) ऐसी कौन सी तकनीकी विशेषज्ञता विदेशियों में देखी कि उन्होंने रेलवे को उनके हाथों में सौंपने का मन बना लिया. इसी तरह मकान

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकार का यह निर्णय गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देगा | P-3

बिहार के गांव ऐसे स्मार्ट बनेंगे | P-4

बीज कंपनियां बाल श्रम को बढ़ावा दे रही हैं | P-6

सरकार और भाजपा से नाराज़ है आरएसएस

पृष्ठ 1 का शेष

बनाने के लिए किस विशेष तकनीक की आवश्यकता थी जिसके लिए विदेशी धन, विदेशी कंपनियों और विदेशी तकनीक बुला ली. संघ के लोग कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी इमारतें बनी हुई हैं, जिनकी संरचना आज तक विश्व नहीं समझ पाया है. हमारे यहां ऐसे मंदिर हैं जिनके खंभे के नीचे से कपड़ा निकाल लीजिए, बिना जमीन को छुए पिलर (स्तंभ) खड़े हैं और मंदिर खड़ा है. हमारे यहां ऐसे भवन हैं जिनमें एक दीवार हिलाने पर दूसरी दीवार हिलती है, लेकिन भवन खड़े हैं. इस तकनीक को विश्व आज तक समझ नहीं पाया और हम अपनी तकनीक को बढ़ाने के बजाय विदेशी तकनीक को अपनाते जा रहे हैं. संघ के लोगों को इस बात का दु:ख है कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट हो गई है. आप कैसे भी भवन बनाएं, विज्ञापित करें, उन्हें बेचें और चले जाएं. भले ही उनमें गुणवत्ता हो या न हो. संघ के लोग मोदी सरकार की इस लूटो और भागो नीति को विदेशियों के लिए दी गई सुविधा बता रहे हैं.

संघ के लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि मोदी की सरकार उनके परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप काम नहीं कर रही है. पूरा संघ इससे असंतुष्ट है. संघ के लोग इसके उदाहरण के रूप में संघ प्रमुख के बयानों को बताते हैं. वे कहते हैं कि संघ प्रमुख ने सिलेसिलेवार बयान अपने मन की व्यथा प्रकट करने के लिए दिए. बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई. संघ के लोग कहते हैं कि क्या संघ प्रमुख बच्चे थे, जो उन्होंने बिहार चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर बयान दिया? संघ प्रमुख को सारी राजनीति की समझ है, वह बच्चे नहीं हैं. संघ के लोगों का साफ कहना है कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यक्ति होता है, वह राजनीति से अप्रभावित नहीं रहता. वह राजनीति को अच्छी तरह समझता है. हमारे देश में राजनीति हर क्षेत्र में दखल रखती है और संघ प्रमुख को इस राजनीति की बहुत अच्छी समझ है. आखिर उन्होंने ऐसा उद्‌बोधन क्यों दिया कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, और अब वह कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए. संघ के लोगों का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों संघ प्रमुख ये बयान दे रहे हैं? वे इसका कारण बताते हैं कि चूंकि सरकार अपने उद्देश्यों और अपने रास्ते से फिसल रही है, इसलिए संघ प्रमुख को ये बयान देने पड़ रहे हैं, और सरकार को इशारे से बताना पड़ रहा है कि उसका रास्ता कौन सा है या कौन सा होना चाहिए.

संघ सरकार से असहयोग की मुद्रा में आ गया है इसलिए पिछले 15 साल से गुजरात जो कि अभेद्य गढ़ बना हुआ है, इस बार वहां भाजपा चुनाव हारने की अवस्था में पहुंच गई है. दूसरा उदाहरण संघ के लोग मध्य प्रदेश को बताते हैं, जहां शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा लोकसभा उप–चुनाव हारी. संघ के लोग इस बात से चिंतित हैं कि बिहार चुनाव से भाजपा ने कोई सीख नहीं ली. उन्हें लगता है कि भाजपा और संघ के ये अंदरूनी मतभेद कहीं युद्ध की शक्ल न ले लें और कांग्रेस दोबारा सत्ता में न आ जाए.

जेटली सरकार पर हावी

संघ के लोग यह बात भी रेखांकित करते हैं कि मोदी ऐसे नेता हैं, जो अपने विरोधियों को कभी माफ नहीं करते. उनके कई मंत्री इसी काम में लगे हैं कि जिसने कभी भी मोदी से असहमति जाहिर की हो, उसे कैसे उसकी औकात में लाना है. इसका पहला उदाहरण संघ के लोग राजनाथ सिंह का देते हैं कि राजनाथ सिंह के पुत्र को लेकर ऐसी देशव्यापी अफवाह फैली कि राजनाथ सिंह ने परेशान होकर सबसे पहले आत्मसमर्पण किया. राजनाथ सिंह को फेसबुक में साजिशी मंत्री भी करार दे दिया गया. उनके हर कदम को इस तरह सोशल मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया, मानो उनके ऊपर आज तलवार गिरने वाली है या कल तलवार गिरने वाली है. राजनाथ सिंह इस क्रम में पूर्णत: नियंत्रित हो गए. अरुण जेटली इस पूरे घटनाक्रम में सरकार के ऊपर हावी हो गए. अरुण जेटली ने ललित

मोदी को बांधने की रणनीति बनाते–बनाते वसुंधरा राजे सिंधिया को बांध दिया. अरुण जेटली ने ही व्यापमं घोटाले में शिवराज सिंह चौहान को बांध दिया. संघ के लोगों का कहना कि मोदी को एक शिखंडी मिला हुआ है और वह उसकी आड़ में अपने एक–एक दुश्मन का शिकार कर रहे हैं. संघ के वरिष्ठ लोग परेशान हैं, क्योंकि वे व्यक्ति आधारित व्यवस्था नहीं चाहते, वे विचार आधारित व्यवस्था चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार व्यक्ति आधारित सरकार में बदल रही है.

सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्व अरुण जेटली का है. अरुण जेटली क्या करना चाहते हैं, नरेन्द्र मोदी को किस तरह की तस्वीर दिखाकर उनसे किन–किन कामों को पूरा करने की हामी भरवा रहे हैं, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है. संघ को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, देश में कोई खुश नहीं है. उनके समर्थक और संपूर्ण व्यापारी वर्ग रो रहा है. व्यापार का कोई भी अंग खुश नहीं है. जनता भी दुखी है जो चुनाव परिणामों से सामने आ रहा है, लेकिन अरुण जेटली हर वह काम कर रहे हैं, जिसका रिश्ता वित्त मंत्रालय से नहीं है. बस वह वित्त मंत्रालय का काम नहीं कर रहे हैं. क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति कहीं भी सुधरती दिखाई नहीं दे रही है. संघ के लोग कई फैसलों के पीछे अरुण जेटली का दिमाग बताते हैं. हमें पाकिस्तान से बात करनी है या नहीं, यह फैसला भी नहीं हो पाता. हम कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद से समझौता कर लेते हैं और सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय मुफ्ती मोहम्मद सईद को दे देते हैं. कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों के पास ऐसे विभाग हैं जिन्हें संघ किसी मतलब का नहीं मानता और संघ ने इसी क्षोभ या गुस्से की वजह से देश में चली टॉलरेंस(सहिष्णुता) या इनटॉलरेंस(असहिष्णुता) की बहस में कहीं भी भाजपा का समर्थन नहीं किया. संपूर्ण संघ टॉलरेंस की बहस में तटस्थ रहा.

संघ के लोग सवाल पूछते हैं, क्या इन सभी घटनाओं से आपको लगता है कि संघ और भाजपा में सब कुछ ठीक है, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं, सबकुछ ठीक नहीं है. संघ के लोगों ने मुझसे साफ कहा कि संघ एक परिवार की तरह काम करता है. इशारों–इशारों में समझाता है. आप समझिए तो ठीक, नहीं तो संघ सरकार को या पार्टी को अपने हाल पर छोड़ देता है. संघ के लोग उदाहरण देते हैं कि भाजपा जब अपने आप चली तो बिहार हार गई, गुजरात हार गई(पंचायत चुनाव). संघ के लोग कहते हैं कि अभी देखना चाहिए कि भाजपा का आने वाले चुनावों में क्या हाल होगा? सारी रणनीति अमित शाह बना रहे हैं. अब देखना है कि अमित शाह रहेंगे या जाएंगे.

अमित शाह और संघ

अमित शाह को लेकर संघ की धारणा साफ है कि अमित शाह एक ऑटोक्रेटिक (तानाशाह) बनकर भाजपा में उभरे हैं. वह न किसी से चर्चा करते हैं और न बात करते हैं. संघ के लोग बहुत दु:ख से बताते हैं कि जो भाजपा स्वदेशी की इतनी बात करती है वह अपने ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए सालाना दस लाख रुपये देती थी. उसे हटाकर अमित शाह ने ई एंड वाई (अर्नेस्ट एंड यंग) को अप्वाइंट कर दिया और उसकी फीस दस करोड़ तय कर दी. ई एंड वाई विदेशी कंपनी है. संघ के लोगों ने मुझसे हंसते हुए कहा कि जो पार्टी स्वदेशी की बात करती है, वह स्वदेशी चार्टर्ड एकाउंटेंट को हटाकर विदेशी कंपनी को अप्वाइंट कर रही है. वह दस लाख की जगह दस करोड़ फीस दे रही है. वह किस दिशा में जा रही है, क्या यह अब भी बताने की जरूरत है. संघ के लोग कहते हैं कि अमित शाह किसी से मिलते नहीं हैं. दिल्ली के चुनावों में बिना किसी से बात किए वह किरण बेदी को ले आए. यहां सबसे मजेदार बात यह है कि दिल्ली चुनाव से 20 दिन पहले दिल्ली कैंटोन्मेंट का चुनाव भाजपा जीती थी. सतीश उपाध्याय, जो नीचे से ऊपर पहुंचे थे, को रातों–रात हटा दिया गया. बिना किसी से पूछे अमित शाह किरण बेदी को ले आए और किरण बेदी ने पहले सात दिन ऐसे वक्तव्य दिए जैसे वह भाजपा की भाग्य विधाता हों और उसकी सर्वोच्च नेता हों. परिणाम स्वरूप भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई. संघ इसे पूरी तरह अमित शाह द्वारा किया काम मानता है.

अमित शाह ने भाजपा में ऐसे–ऐसे महासचिव बनाए हैं, जो सबसे जूनियर हैं. जिन्हें कोई अनुभव नहीं है. संघ के लोगों का यह भी कहना है कि अमित शाह ने ऐसे लोगों को इसलिए अपना महामंत्री बनाया क्योंकि वह गंभीर लोगों को तो महामंत्री बना नहीं सकते क्योंकि सारे गंभीर लोग उनसे वरिष्ठ हैं. संघ का कहना है कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि पार्टी दोयम दर्जे के लोगों के हाथों में आ गई है. चूंकि ये दोयम दर्जे के हैं इसलिए पार्टी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं. इसी वजह से बिहार में टिकट बांटने में इतनी गड़बड़ियां हुईं. अब जब भाजपा के टिकट बटवारे में खामी हो, टिकट बेचने के आरोप लगें, तो ऐसी स्थिति में पार्टी कब तक सही चलेगी? इतना ही नहीं, संघ का मानना है कि पार्टी इससे विखंडित होने की दिशा में चल पड़ती है. पार्टी के अंदर विरोध के स्वर सुने नहीं जाते.

वरिष्ठों के लिए जगह नहीं

संघ के लोग कहते हैं कि हमारे यहां कहा जाता है कि बुजुर्गों की बात हमेशा सुननी चाहिए. लेकिन भाजपा ने तो अपने बुजुर्गों को रिटायर कर दिया. बुजुर्गों की एक समिति बनाई गई जिसमें आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी हैं. लेकिन उनसे कोई बात नहीं करता, सलाह नहीं लेता. उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का कोई इस्तेमाल भाजपा नहीं करती, बल्कि उन्हें अपमानित करने के किसी भी मौके का उपयोग करने से नहीं चूकती. अमित शाह ने पार्टी में वन मैन शो लागू कर दिया है. संघ के लोगों का मानना है कि जिस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने संघ को गुजरात में समाप्त किया ठीक उसी तरह दिल्ली में यानी केंद्र में वह उन सारे लोगों को किनारे कर रहे हैं जिनसे उन्हें थोड़ी भी अपनी राय से अगल सलाह की आशंका है. जो विपरीत राय रखे, वह बाहर. संजय जोशी इसका सबसे सटीक उदाहरण हैं.

अभी फारुख़ अब्दुल्लाह ने एक बयान दिया कि वाजपेयी सरकार के समय कश्मीर का समझौता लगभग हो गया था और हम कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने वाले थे. इसकी सच्चाई संघ के वरिष्ठ लोगों ने मुझे बताई. उन्होंने कहा यह बिल्कुल सच है. संघ के लोग कहते हैं कि इस सच की सजा गोविंदाचार्य आज तक भुगत रहे हैं.भारत–पाकिस्तान के बीच समझौता होने जा रहा था हम अपना एक हिस्सा पाकिस्तान को दे रहे थे. गोविंदाचार्य ने इसमें टांग अड़ा दी. गोविंदाचार्य ने अपनी बुद्धि से उस ब्लंडर को होने से रोक दिया. संघ का कहना है कि अगर गोविंदाचार्य उस ब्लंडर को हो जाने देते तो भाजपा कभी, कहीं पर कोई चुनाव जीतकर नहीं आ सकती थी. गोविंदाचार्य पंद्रह सालों से सजा भुगत रहे हैं और उनका कहीं अता–पता नहीं है.

संघ के वरिष्ठ लोग चाहते हैं और मानते हैं कि संजय जोशी या गोविंदाचार्य जैसे लोग और आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे लोग उपेक्षित नहीं होने चाहिए, और इनकी सलाह से सरकार चलनी चाहिए. इन लोगों ने बहुत त्याग किया है. संघ के लोग यह भी मानते हैं कि मोदी से देश की जो अपेक्षाएं हैं वे अभी टूटी नहीं हैं लेकिन भाजपा की चल रही सरकार अपने कदम नहीं सुधारती है तो वह बहुत जल्दी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी.

संघ के लोगों का साफ मानना है कि अभी सिर्फ क़ाग़ज़ी बातें आगे बढ़ रही हैं. यदि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है और पेट्रोल–डीजल के दाम घट रहे हैं तो इसका श्रेय सरकार क्यों ले रही है? इसमें सरकार ने क्या किया है? पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम हुए, इसलिए आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया. फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से फिस्कल डेफिसिट कम हो गया. यह तो कांग्रेस सरकार रहती तब भी होता. इस पूरी कहानी में जो मजेदार तथ्य सामने आया वह यह कि जिस प्रचारक को संघ ने भाजपा में भेजा उसे कभी वापस नहीं लिया और जिस प्रचारक ने भाजपा के मन की बात नहीं की उसे भाजपा ने किनारे लगा दिया. इसीलिए आज रामलाल जिन्हें भाजपा में संघ में भेजा था सबसे निष्प्रभावी महामंत्री हैं और अमित शाह उनकी बात नहीं सुनते.

आशंकाएं और अपेक्षाएं

संघ के लोगों का साफ मानना है कि यदि अमित शाह ने अपनी कार्य पद्धत्ति को नहीं बदला तो आगे आने वाले चुनाव जिनमें असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब प्रमुख हैं, इनमें भाजपा जीत की संभावनाओं से दूर होती जाएंगी. अमित शाह की आक्रामक नीति की वजह से भाजपा के सारे विरोधी एक होने के रास्ते पर चल पड़े हैं. उनका साफ कहना है कि भाजपा को तीस प्रतिशत वोट मिले हैं और यही उसका वोट का आधार है, यदि सत्तर प्रतिशत उसके खिलाफ हो जाएंगे तो उसका हारना तय है. इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. इस संभावित हार की वजह से राज्य सभा में सरकार का कभी बहुमत नहीं हो पाएगा और सरकार कभी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी. आज सरकार का कोई बिल संसद में पास नहीं हो पा रहा है. संघ के लोगों का कहना है कि कांग्रेस की जड़ें पिछले 65 साल में जितनी गहराई से जम चुकी हैं उसे उखाड़ना इतना आसान नहीं है. संघ के लोगों का साफ कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं आए कि हम भाजपा को बीच में छोड़ दें और उस स्थिति में भाजपा चल पाएगी इसमें बहुत बड़ा संदेह है. इसलिए भाजपा को संघ के साथ मिलकर चलना चाहिए. संघ के लोग खुद की भी एक कमी बताते हैं कि हमें भी यह आदत छोड़नी होगी कि यदि बेटा बाप की बात नहीं मानता है तो बेटे को मझधार में छोड़ दो. हमें भी भाजपा के ऊपर सख्ती के साथ अपने निर्देश लागू करने होंगे. संघ के लोगों का यह भी मानना है कि हम उन सभी लोगों की बात सुनेंगे जिन्हें भाजपा ने उपेक्षित कर रखा है. देश सबका है. संघ का साफ मानना है कि न कांग्रेस देशद्रोही है, न समाजवादी देशद्रोही हैं, न कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं, न मुसलमान देशद्रोही हैं. देश सबका है. देश रहेगा, सब रहेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 42
दिल्ली, 21 दिसंबर–27 दिसंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीफ निर्यात में हो रहे इजाफे को पिंक रिवॉल्यूशन का नाम देते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार की सख्त आलोचना की थी. जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है. आज से 32 वर्ष पहले वनस्पति घी में बीफ टैलो की मिलावट होने की बात पर देश की संसद में और बाहर बहुत हो–हल्ला मचा था. इस मुद्दे को उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने जोर–शोर से उठाया था. उनका सवाल था कि वनस्पति घी बनाने वाली कम्पनी को बीफ टैलो आयात करने की अनुमति कैसे दी गई? विपक्ष ने इस मुद्दे को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया था. इस दबाव को महसूस करते हुए इंदिरा गांधी को कहना पड़ा कि हमारी नीति साफ़ है. हमने बीफ टैलो के निर्यात की इजाजत न दी है और न ही भविष्य में ऐसा करेंगे.

बीफ चर्बी निर्यात में ढील

सरकार का यह निर्णय गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देगा

सवाल यह उठता है कि कि मीट के निर्यात में हर साल इजाफा क्यों हो रहा है? क्या निर्यात से होने वाली कमाई इतनी ज्यादा हो गई है कि उस पर रोक लगाना अब मुमकिन नहीं है? चूंकि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज़ से पिंक रिवोल्यूशन की बात की थी, उससे यह लगा था कि उनके सत्ता में आने के बाद कम से कम मीट निर्यात पर पूरी तरह से पाबन्दी नहीं भी लगाई जाती है तो भी इसमें कमी ज़रूर आएगी, क्योंकि पूर्व में भी भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मीट निर्यात पर लगाम लगाना तो दूर मौजूदा सरकार के बफैलो टैलो के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध में ढील जैसे कदम से व्यापार को एक नई उर्जा दे दी है.

शफीक आलम

भारत में बीफ टैलो/चर्बी एक बार फिर सुर्ख़ियों में है. भारत में बीफ टैलो का विवादों से बहुत पुराना रिश्ता है. स्पिरिंगफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह की वजह से 1857 का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, जिसे बाद में भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया. समय–समय पर खाने–पीने की वस्तुओं में इन जानवरों की चर्बी की मिलावट की ख़बरें अक्सर आती रहती हैं. कई मामलों में गिरफ्तारियां भी होती हैं. वर्तमान समय में बीफ टैलो से सम्बंधित सबसे प्रसिद्ध मामला 1983 में सामने आया था, जब वनस्पति घी बनाने वाली कंपनी पर वनस्पति घी में आयातित बीफ टैलो की मिलावट का आरोप लगा था. इस मुद्दे को एक राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की गई और पक्ष एवं विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप के तीर भी बरसाए थे. हालिया दिनों में बीफ को लेकर देश में काफी विवाद रहा और सत्ताधारी दल भाजपा ने इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे की तरह भुनाने की कोशिश की. लेकिन बीफ टैलो से जुड़ी हालिया खबर एक दूसरी ही कहानी बयां करती नज़र आ रही है.

ख़बर के मुताबिक, मोदी सरकार ने बड़ी ख़ामोशी से बीफ टैलो के निर्यात पर लगे 32 वर्ष पुराने प्रतिबंध में ढील दे दी है, जिसकी वजह से बीफ टैलो व्यापार में महीने–दर–महीने लगातार वृद्धि हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से लेकर मार्च 2015 तक 29.85 लाख की 74 हजार किलो चर्बी का निर्यात किया गया था, जो इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक तकरीबन 36 गुना बढ़कर 10.95 करोड़ रुपये हो गया. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने बीफ की चर्बी निर्यात में छूट पर 31 दिसंबर, 2014 को स्वीकृति दे दी थी. इसकी आधिकारिक अधिसूचना डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने आदेश संख्या 104 (आरई–2013)/2009–2014 द्वारा जारी की थी. डीजीएफटी के आदेश के मुताबिक, बफैलो टैलो का निर्यात एपीईडीए (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) रजिस्टर्ड एकीकृत मीट प्लांट से एपीईडीए द्वारा स्वीकृत लेबोरेटरीज से बायो–केमिकल टेस्ट के बाद ही किया जा सकता है.

इसमें कोई शक नहीं कि बफैलो टैलो के निर्यात पर 32 वर्ष पुराने प्रतिबन्ध में छूट देने से बीफ निर्यात में हो रही लगातार वृद्धि में और इजाफा होगा. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है (अमेरिका भैंस के मांस को बीफ के दर्जे में रखता है). इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि निर्यात परमिट दिए जाने के बाद पिछले कुछ महीनों में बफैलो टैलो की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया. हालांकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि बफैलो टैलो का निर्यात भारत सरकार के मीट निर्यात नीति के अनुरूप किया जा रहा है, लेकिन हकीक़त यह भी है कि जब टैलो के निर्यात में इजाफा होगा तो जानवरों के स्लॉटर (कत्ल) में भी इजाफा होगा. देश में अक्सर देशी घी और वनस्पति घी में बीफ टैलो की मिलावट जे जुड़ी ख़बरें आती रहती हैं. हालिया दिनों में ऐसे मामलों नें गिरफ्तारियां भी हुई हैं. अब बीफ टैलो के उत्पादन में वृद्धि इस मिलावट के बाजार को और गर्म करेगा.

बीफ का मुद्दा भारत में अक्सर राजनीतिक मुद्दा बनता रहा है. हालिया दिनों में महाराष्ट्र और हरियाणा में गौ हत्या पर प्रतिबन्ध का मुद्दा और दादरी में महज़ बीफ रखने के अरोप में एक व्यक्ति की हत्या का मामला विवादों में घिरा रहा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीफ निर्यात में हो रहे इजाफे को पिंक रिवॉल्यूशन का नाम देते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार की सख्त आलोचना की थी. जैसा कि ऊपर ज़िक्र किया जा चुका है. आज से 32 वर्ष पहले वनस्पति घी में बीफ टैलो की मिलावट होने की बात पर देश की संसद में और बाहर बहुत हो–हल्ला मचा था. इस मुद्दे को उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने जोर–शोर से उठाया था. उनका सवाल था कि वनस्पति घी बनाने वाली कम्पनी को बीफ टैलो आयात करने की अनुमति कैसे दी गई? विपक्ष ने इस मुद्दे को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया था. इस दबाव को महसूस करते हुए इंदिरा गांधी को कहना पड़ा कि हमारी नीति साफ़ है. हमने बीफ टैलो के निर्यात की इजाजत न दी है और न ही भविष्य में ऐसा करेंगे. कांग्रेस ने तत्काल जनता सरकार पर इसका आरोप मढ़ दिया था और विवाद शांत करने के लिए टैलो आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. बाद में इस मामले में सीबीआई की जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुईं और कई वर्षों बाद कुछ लोगों को सजा भी हुई.

अब सवाल यह उठता है कि कि मीट के निर्यात में हर साल इजाफा क्यों हो रहा है? क्या निर्यात से होने वाली कमाई इतनी ज्यादा हो गई है कि उस पर रोक लगाना अब मुमकिन नहीं है? चूंकि सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज़ से पिंक रिवोल्यूशन की बात की थी, उससे यह लगा था कि उनके सत्ता में आने के बाद कम से कम मीट निर्यात पर पूरी तरह से पाबन्दी नहीं भी लगाई जाती है तो भी इसमें कमी ज़रूर आएगी, क्योंकि पूर्व में भी भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मीट निर्यात पर लगाम लगाना तो दूर मौजूदा सरकार के बफैलो टैलो के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध में ढील जैसे कदम से व्यापार को एक नई उर्जा दे दी है. अब सवाल उठना लाज़मी है कि क्या राजनीतिक दल जनता की भावनाओं से खेल कर वोट हासिल करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं? क्या उनकी नज़र में जनता मुर्ख है? क्या उनको यह नहीं लगता कि टैलो निर्यात पर पाबन्दी हटाने से जानवरों के स्लॉटर में इजाफा होगा? सवाल कई हैं, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार के रवैये से लगता नहीं कि वह इन सवालों पर गंभीर है. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या है टैलो?

भेड़–बकरी या किसी अन्य पशु की चर्बी को गर्म करके ठोस चर्बी को अलग कर लिया जाता है, जिसे टैलो कहते हैं. साधारणत: बीफ या मटन चर्बी से हासिल किये गए ठोस चर्बी को ही टैलो कहा जाता है, लेकिन व्यवसायिक टैलो की श्रेणी में दूसरे जानवरों की चर्बी से हासिल किये गए टैलो भी शामिल होते हैं. टैलो का लाभ यह होता है कि यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है और एयर–टाइट डब्बे में बंद करके इसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. टैलो का इस्तेमाल खाना बनाने, साबुन बनाने, कॉस्मेटिक तैयार करने, लुब्रीकेंट्स बनाने, कैंडल बनाने, बायो–डीजल बनाने, जानवरों की खुराक इत्यादि के रूप में होता है. कुछ टैलोज दवा बनाने में भी काम आते हैं. चूंकि भारत या दुनिया के कई अन्य हिस्सों में खाने–पीने का मामला आस्था से भी जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां अपनी वस्तुओं पर वेजन (शाकाहारी) मार्क के साथ जारी करती हैं. उसी तरह फूड ज्वॉइंट्स अब अपने फ्राइड प्रोडक्ट्स के लिए वेजिटेरियन–फ्रेंडली का टैग लगा रहे हैं. ■

माध्यमिक शिक्षा से दूर होते बच्चे

फिर कैसे बन पाएगा स्किल इंडिया

भारत में 12 साल तक की उम्र के लाखों बच्चे हैं, जो रोज़ाना तीन–चार घंटे का समय घरेलू कामकाज में व्यतीत करते हैं. डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डीआईएसई) एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यंग लिव्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ऐसे 70 प्रतिशत बच्चे शायद ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं. वहीं दूसरी तरफ़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (स्किल इंडिया मिशन) के तहत शामिल होने के लिए तय मापदंड अलग कहानी कहते हैं. इस योजना के अंतर्गत कुल 29 कोर्स हैं, जिनमें से पांच ऐसे हैं, जिनके लिए अभ्यर्थी को 12वीं और सबसे कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. ऐसे में सवाल यह है कि जब ज़्यादातर बच्चे अपनी माध्यमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी महत्वपूर्ण योजना कैसे कामयाब हो पाएगी?

आदित्य नारायण पांडेय

सवा अरब से ज़्यादा की आबादी वाले भारत में शिक्षितों का आंकड़ा भले ही तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन एक सच यह भी है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चे रोज़ाना तीन–चार घंटे घरेलू कामकाज में व्यतीत करते हैं और उनमें से 70 प्रतिशत शायद ही अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं. शिक्षा का अधिकार क़ानून के तहत देश में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए बहुत–सी कार्ययोजनाएं बनीं, लेकिन उनके सुखद परिणाम हासिल नहीं हो सके. यदि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डीआईएसई) एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यंग लिव्स एसोसिएशन द्वारा किए गए शोध के आंकड़े बताते हैं कि देश के लाखों बच्चे अपनी माध्यमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते. ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी महत्वपूर्ण योजना कैसे कामयाब हो पाएगी, जिसके तहत 29 कोर्स रखे गए हैं, जिनके लिए अभ्यर्थी का माध्यमिक स्तर शिक्षित होना ज़रूरी है. चार कोर्स ऐसे हैं, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडियट उत्तीर्ण निर्धारित है. वहीं आठवीं एवं 10वीं कक्षा तक शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए तीन और उससे कम शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए पांच कोर्स हैं.

डीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में प्राइमरी स्तर पर 100 प्रतिशत दाखिला होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ़ 78 प्रतिशत बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा के लिए दाखिला ले पाते हैं. यानी प्राइमरी स्तर पर दाखिला लेने वाले बच्चों में से 22 प्रतिशत, जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, माध्यमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. दूसरी तरफ़ देश के प्रत्येक 10 प्राथमिक स्कूलों के मुक़ाबले माध्यमिक स्कूलों की संख्या सिर्फ चार है. यानी स्कूल भी पर्याप्त संख्या में नहीं है. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में दाखिले का अनुपात देखें, तो दोनों ही स्तर पर अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं. छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में माध्यमिक स्कूलों में दाखिले का अनुपात सबसे अधिक है, साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी सबसे ज़्यादा यानी 23 प्रतिशत है. वहीं उत्तर प्रदेश में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम है, लेकिन एक सच यह भी है कि वहां कुल दाखिले का प्रतिशत भी कम है.

डीआईएसई ने अपने अध्ययन में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा का भी जिक्र किया है. उसके मुताबिक, 77 प्रतिशत लड़कों के मुक़ाबले सिर्फ़ 66 प्रतिशत लड़कियां ही माध्यमिक शिक्षा पूरी करती हैं. साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 4.4 मिलियन यानी 44 लाख बच्चे ऐसे हैं, जिनकी उम्र पांच से 14 साल के बीच है और वे मज़दूरी कर रहे हैं. डीआईएसई की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऐसे बच्चे, जो पढ़ाई के बजाय बहुत कम उम्र में मज़दूरी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं या किसी मजबूरी वश अकुशल रोज़गार से जुड़ जाते हैं, वे न सिर्फ़ पढ़ाई के प्रति रुचि खो बैठते हैं, बल्कि साथ ही प्रशिक्षण और कौशल विकास से भी वंचित रह जाते हैं.

- 12 साल के बच्चे, जो रोज़ाना तीन–चार घंटे घरेलू कामकाज में बिताते हैं, उनमें से 70 प्रतिशत अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते.
- नामांकन 100 प्रतिशत, लेकिन 22 प्रतिशत बच्चे, जिनकी उम्र 15 से 16 साल तक है, माध्यमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं.
- पांच से 14 साल तक के 4.4 मिलियन बच्चे मज़दूरी कर रहे हैं.

देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हासिल है. सभी के लिए प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान है. यह प्रावधान सिर्फ़ शासकीय नहीं, बल्कि अशासकीय विद्यालयों पर भी लागू है. भारत सरकार के सिटीजन चॉर्टर के अंतर्गत सीबीएसई एवं आईसीएसई काउंसिल की नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि देश के हर बच्चे को किसी भी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है. कोई भी संस्था जाति, धर्म, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को कारक मानकर किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती. यानी प्रत्येक संस्था को यह शैक्षिक दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत वह किसी भी बच्चे को उसके अभिभावक की आर्थिक स्थिति–वार्षिक आय आदि कारकों के चलते प्रवेश देने से इंकार नहीं सकती. इसके अलावा सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए मिड डे मील समेत कई योजनाएं चलाई गई हैं. बावजूद इसके देश में शिक्षा की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं आया. मुफ्त में कपड़े, किताबें और मिड डे मील जैसी योजनाओं के चलते स्कूलों में नामांकन में तो खासी बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन असल लक्ष्य हासिल नहीं हो सका. सवाल यह उठता है कि जिस देश में बच्चे अपनी माध्यमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री का हर हाथ को रोज़गार देने का सपना भला कैसे पूरा होगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

बड़े उद्योग लगाने के लिए सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के बावजूद निवेशक आकर्षित नहीं हो रहे. वहीं दूसरी तरफ़ उपजाऊ या कृषि योग्य भूमि पर कल–कारख़ाने लगाना उन किसानों के प्रति अन्याय होगा, जिनसे ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा. सवाल यह है कि बिहार जैसे राज्यों में रोज़गार पैदा करने के लिए बड़े कल–कारख़ानों में निवेश को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है या कृषि के नए तौर–तरीके अपनाना.

बिहार के गांव ऐसे स्मार्ट बनेंगे

सामूहिक या सहकारी खेती के प्रोत्साहन से गांवों में ही रोज़गार के साधन–अवसर बढ़ जाएंगे. आज गांवों से लोगों का पलायन पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि मज़दूर के रूप में ही ज़्यादा होता है, जो ख़त्म हो जाएगा. इससे कृषि की नई तकनीक और ज्ञान की जानकारी का आदान–प्रदान होगा.

बिहार

सरकार गांवों में पक्की नालियों, बिजली, सड़क एवं पेयजल आदि की उचित व्यवस्था कर दे, तो हमारे गांव वाकई स्मार्ट गांव हो जाएंगे. इस सबके लिए सरकार को पहल करते हुए सामूहिक या सहकारी खेती करने के इच्छुक किसानों को बैंकों के ज़रिये कृषि ऋण उपलब्ध कराना चाहिए. साथ ही सोलर पंपसेट, स्प्रिंकलर, बीज, खाद एवं ट्रैक्टर आदि के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए.

राजीव कुमार

आज बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत है, गांवों के समग्र विकास और लोगों में एक नई सोच एवं नई ऊर्जा सृजित करने की. शहरों में रोज़गार के अवसर–साधन उपलब्ध हैं, लेकिन गांवों में नहीं. जबकि बिहार की बड़ी आबादी मुख्यत: गांवों में ही बसती है. सवाल यह है कि गांवों में रोज़गार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कैसे हो, जिससे बेरोज़गारी दूर हो और पलायन भी रुक जाए. इस संदर्भ में मोतिहारी के एक निजी स्कूल की नौवीं कक्षा के छात्रों ने एक गांव के संबंध में दो विषयों को आधार बनाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की. पहला यह कि गांव की बुनियादी ज़रूरतें जैसे सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय, पक्की नालियां, स्वच्छता आदि की वर्तमान स्थिति का आकलन. दूसरा विषय था, गांव की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का गहन विश्लेषण. अध्ययन का निष्कर्ष यह निकला कि गांव की 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है. गांव की कुल आबादी के एक चौथाई से अधिक हिस्से का पलायन रोज़गार के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में हुआ है, जिसमें 16 से 45 साल की आयु के लोग अधिक हैं. छात्रों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि 90 प्रतिशत से भी अधिक आबादी के पास कृषि के अलावा आय या रोज़गार का कोई साधन नहीं है. बुनियादी संरचनाओं, जैसे पक्की नालियों, शुद्ध पेयजल व्यवस्था, बिजली और अधिकांश घरों में शौचालयों का घोर अभाव देखा गया.

छात्रों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि सरकार पूंजी निवेश और बड़े कल–कारख़ाने लगाने पर ज़ोर देती है, जिससे न सिर्फ़ हमारी बुनियादी और कृषि अर्थव्यवस्था पीछे छूट रही है, बल्कि ग्रामीण मानव संसाधनों का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा. नतीजतन, गांवों से युवाओं का पलायन लगातार जारी है. बड़े उद्योग लगाने के लिए सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के बावजूद निवेशक आकर्षित नहीं हो रहे. वहीं दूसरी तरफ़ उपजाऊ या कृषि योग्य भूमि पर कल–कारख़ाने लगाना उन किसानों के प्रति अन्याय होगा, जिनसे ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा. सवाल यह है कि बिहार जैसे राज्यों में रोज़गार पैदा करने के लिए बड़े कल–कारख़ानों में निवेश को प्रोत्साहित करना ज़रूरी है या कृषि के नए तौर–तरीके अपनाना. बिहार की भूमि अत्यंत उपजाऊ है. यहां जल संसाधन और मानव संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं. यहां की लगभग 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि आज आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं है. कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक एवं दूरदर्शिता का अभाव है और जोत के आकार भी निरंतर छोटे होते जा रहे हैं, जिसके चलते आधुनिक एवं उन्नत कृषि नहीं अपनाई जा सकती. यही वजह है कि कृषि शिक्षित नौजवानों को आकर्षित नहीं कर रही. इसलिए कृषि व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है. अब किसानों को सामूहिक या सहकारी खेती के लिए न सिर्फ़ प्रेरित करना होगा, बल्कि उन्हें खेती के नए प्रयोगों एवं तौर–तरीकों से भी अवगत कराना होगा. स्कूली बच्चों को भी आधुनिक कृषि, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी–मत्स्य पालन, फल–फूल एवं सब्जी उत्पादन आदि के संबंध में ज्ञान, प्रबंधन और मार्केटिंग का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए.

सामूहिक या सहकारी खेती के प्रोत्साहन से गांवों में ही रोज़गार के साधन–अवसर बढ़ जाएंगे. आज गांवों से लोगों का पलायन पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि मज़दूर के रूप में ही ज़्यादा होता है, जो ख़त्म हो जाएगा. इससे कृषि की नई तकनीक और ज्ञान की जानकारी का आदान–प्रदान होगा, साथ ही जोत के आकार बड़े हो जाएंगे और परंपरागत कृषि के अलावा बड़े पैमाने पर मत्स्य–मुर्गी–बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन एवं कृषि वानिकी का विकास होगा. कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश शुरू हो जाएगा. यही नहीं, विस्तृत क्षेत्र में स्प्रिंकल या टपक सिंचाई के साधन विकसित हो जाने से पानी का उचित प्रबंधन भी होगा यानी विकास के साथ कृषि उत्पादन और उत्पादकता में कई गुना इजाफ़ा होगा. गांव के मज़दूर एवं किसान आपसी सामंजस्य के ज़रिये उत्पादन का वितरण और मार्केटिंग कर सकेंगे. गांव एक कृषि उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित होगा. कृषि से संबंधित कई चीजों के एक साथ उत्पादन से गांव के लोग द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कारोबार के ज़रिये शहरों से जुड़ जाएंगे. गांव से दूसरे शहरों या राज्यों में पलायन भी रुक जाएगा. इसके अतिरिक्त यदि सरकार गांवों में पक्की नालियों, बिजली, सड़क एवं पेयजल आदि की उचित व्यवस्था कर दे, तो हमारे गांव वाकई स्मार्ट गांव हो जाएंगे. इस सबके लिए सरकार को पहल करते हुए सामूहिक या सहकारी खेती करने के इच्छुक किसानों को बैंकों के ज़रिये कृषि ऋण उपलब्ध कराना चाहिए. साथ ही सोलर पंपसेट, स्प्रिंकलर, बीज, खाद एवं ट्रैक्टर आदि के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए. गांव में ग्रामीण सचिवालय की स्थापना हो, जहां ज़मीनों के रिकॉर्ड कंप्यूटर पर अपडेट हों, इससे गांव का एक लैंड बैंक बन जाएगा और ज़मीनों के दस्तावेजों का रखरखाव भी सुधर जाएगा. यही नहीं, गांव की श्रम शक्ति का एक डाटा तैयार हो जाएगा, साथ ही ज़मीन संबंधी विवादों में भी कमी आएगी. बिहार में चल रही इंद्रधनुषी योजना के ज़रिये किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

अगर सरकार प्रयास करे, तो वह गांवों में ही अनाज भंडारण केंद्र स्थापित करके खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बना सकती है. अब समय आ गया है कि गांव के लोग अपनी सोच एवं दृष्टि को बदलें, साथ ही सरकार भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए. उसे सामूहिक खेती के लिए प्रायोगिक तौर पर एक गांव का चयन कर अथवा गोद लेकर किसानों को प्रेरित करना चाहिए. इसका सकारात्मक असर हमारे सामाजिक ताने–बाने पर पड़ेगा. प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी और क़ानून का राज अपने आप स्थापित हो जाएगा. सरकार के पास कृषि एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए इससे बेहतर विकल्प दूसरा कोई नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

कच्चा तेल सस्ता, फिर पेट्रोल महंगा क्यों

चौथी दुनिया ब्यूरो

दिसंबर महीने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की क़ीमत 40 डॉलर प्रति बैरल से भी कम हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कच्चे तेल की क़ीमत इतनी कम होने के बाद भी आम आदमी को उसका फ़ायदा मिल रहा है? क्या कच्चे तेल की क़ीमत के मुक़ाबले पेट्रोल–डीजल के दाम उतने कम हुए हैं, जितने होने चाहिए? अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत इसलिए इतनी कम हुई है, क्योंकि ओपेक देशों ने अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए जबरदस्त तेल उत्पादन किया. जितनी मांग है, उससे कहीं अधिक यानी हर दिन हज़ारों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है. लेकिन, इस सबका फ़ायदा आम आदमी को नहीं पहुंच रहा है.

फरवरी, 2007 में कच्चे तेल की क़ीमत 55 डॉलर प्रति बैरल थी, तब भारत में पेट्रोल 42 और डीजल 30 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा था. आज कच्चा तेल 39 डॉलर प्रति बैरल है, फिर भी पेट्रोल दिल्ली में 61 और मुंबई में 68 रुपये प्रति लीटर की दर से आम आदमी को मिल रहा है. ग़ौरतलब है कि सरकार और तेल कंपनियां कच्चे तेल की क़ीमत में गिरावट का सीधे तौर पर फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन उपभोक्ता यानी आम जनता उससे वंचित है.

वित्तीय वर्ष 2014–15 के पहले छह महीनों के लिए अंडर–रिकवरी 51,110 करोड़ रुपये रही है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के पूरे वर्ष के लिए यह धनराशि 1,39,869 करोड़ रुपये रही थी. इधर मौजूदा केंद्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल पर दो रुपये उत्पाद शुल्क भी बढ़ा दिया है. सरकार ने कहा है कि यह बढ़ोत्तरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की गई है. केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने चाहिए थे, जो नहीं हुआ. उल्टे पेट्रोल का दाम बढ़ाने के अजीबोग़रीब तर्क दिए जाते हैं. मसलन, पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों की हानि की पूर्ति करना. जबकि सच्चाई यह है कि सरकार ज़्यादातर रकम टैक्स के रूप में अपने पास रख लेती है और तेल कंपनियां अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नया निवेश नहीं कर पातीं, वे तेल के नए स्रोतों की खोज भी नहीं कर पातीं. एक तर्क सब्सिडी का भी दिया जाता है. सवाल यह है कि 30 से 35 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल 68 रुपये प्रति लीटर की दर तक क्यों बेचा जाता है? जब बेसिक पेट्रोल प्राइस पर सरकार अच्छा–खासा टैक्स वसूल लेती है, तो फिर सब्सिडी का तर्क कहां शेष बचता है? ज़ाहिर है, इस सबका बोझ आम आदमी पर ही पड़ता है.

सवाल यह है कि आख़िर पेट्रोल–डीजल की वास्तविक और सही क़ीमत क्या होनी चाहिए? इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 112 डॉलर प्रति बैरल थी, उस समय पेट्रोल की क्या क़ीमत होनी चाहिए थी? कच्चे तेल की क़ीमत 112 डॉलर प्रति बैरल होने की स्थिति में एक लीटर पेट्रोल की क़ीमत होती है 32 रुपये. तेल कंपनियों के मुताबिक़, कच्चा तेल रिफाइन करने का खर्च 52 पैसे प्रति लीटर आता है. अगर इसमें रिफाइनरी की कैपिटल कॉस्ट जोड़ दी जाए, तो क़रीब छह रुपये और जोड़ने पड़ेंगे. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्च ज़्यादा से ज़्यादा छह रुपये और डीलरों का कमीशन 1.05 रुपये प्रति लीटर है. अगर इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए, तो भी एक लीटर पेट्रोल की क़ीमत 45.57 रुपये होती है. लेकिन, दिल्ली में तब पेट्रोल 63.4 रुपये, मुंबई में 68.3 रुपये और बंगलुरू में 71 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा था. ऐसे में सवाल उठता है कि यह सारा पैसा आख़िर कहां जा रहा है? ज़ाहिर है, क़ीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल पर क़रीब 50 प्रतिशत तक टैक्स लेती हैं, जो बेसिक पेट्रोल प्राइस पर लगता है. इसका मतलब यह है कि पेट्रोल–डीजल के दाम बढ़ने से सरकार को फ़ायदा होता है. तो फिर सरकार यह क्यों कहती है कि तेल कंपनियों को नुक़सान हो रहा है? ज़ाहिर है, इस टैक्स को तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो साफ़ समझा जाना चाहिए कि सरकार निजी कंपनियों को लूट मचाने की खुली छूट दे रही है.

आज जबकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 40 डॉलर प्रति बैरल से भी कम है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी से पेट्रोल की क्या क़ीमत वसूली जानी चाहिए. मई, 2011 में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत 112 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब घटकर 40 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हो गई है. आने वाले दिनों में इसकी क़ीमत में और भी गिरावट की संभावना है. लेकिन, देश में पेट्रोल की क़ीमत उस अनुपात में गिरने वाली नहीं है. क्या भारत सरकार तेल कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन गई है?■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त, 2015 तक उच्चतम न्यायालय में 28 और उच्च न्यायालयों में 633 जज कार्यरत हैं. उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत 1,017 पदों में से 384 पद यानी 38 प्रतिशत रिक्त पड़े हैं. 31 दिसंबर, 2014 को निचली अदालतों में कुल स्वीकृत 20,214 पदों में से 4,580 पद रिक्त थे. इसका मतलब निचली अदालतों में 23 प्रतिशत पद रिक्त थे. यदि संख्या के आधार पर देखें तो देश के 24 उच्च न्यायालयों में से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत 160 पदों में से 84 पद रिक्त हैं. रिक्तियों के मामले में दूसरे स्थान पर हरियाणा है,

दो करोड़ लंबित मुक़दमे

देर से मिला न्याय, अन्याय है

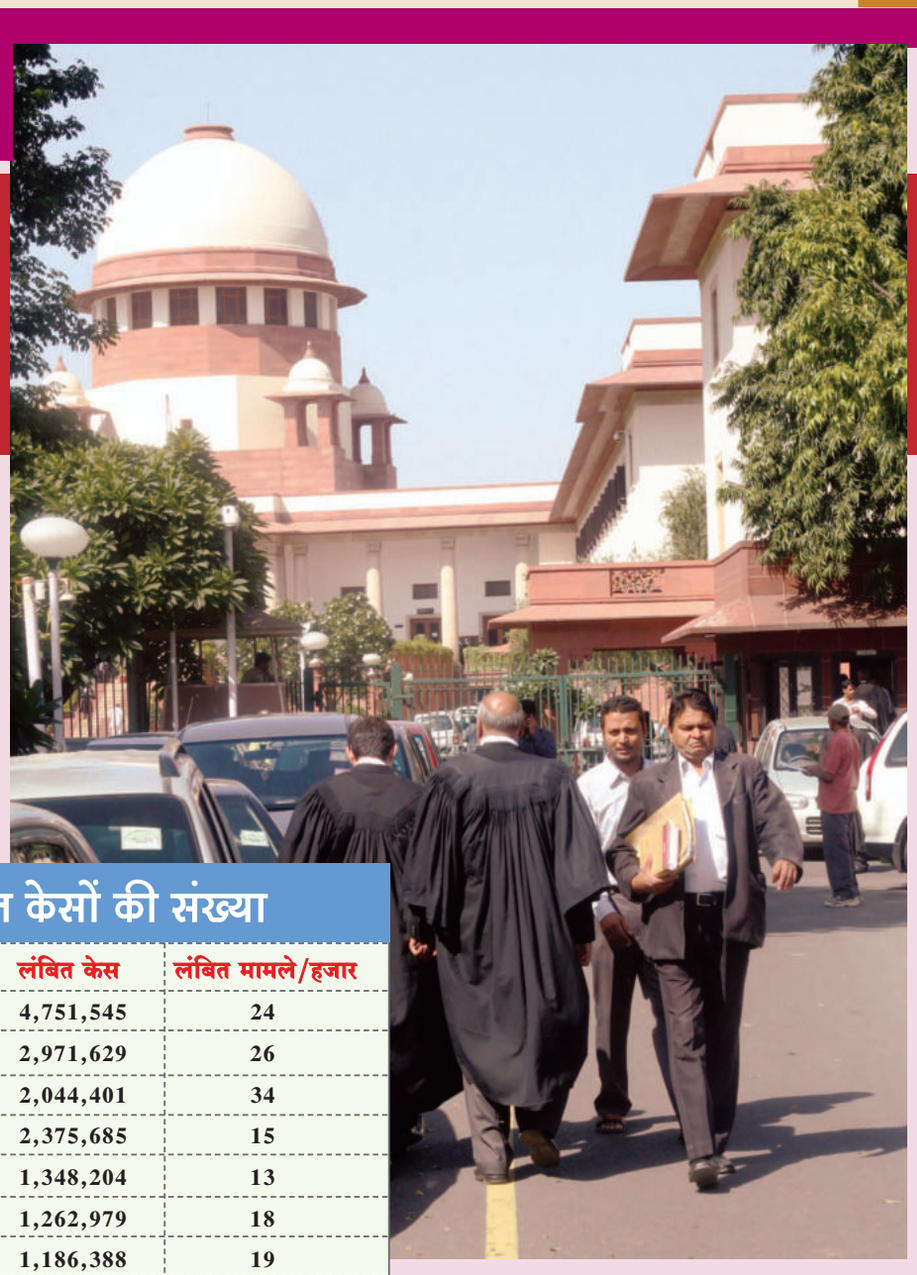

न्याय मिलने में देरी का कारण केवल जज और सुविधाओं की कमी नहीं है. कई बार वकील अपने आर्थिक फायदे के लिए मुकदमों को बेवजह लंबा खींचते हैं. न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी, जल्दी स्थानांतरण और प्रभावशाली लोगों के कारण भी इंसाफ मिलने में देरी होती है. जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने तो अदालतों को जज-अंकल सिंड्रोम से प्रभावित होने की बात आधिकारिक रूप से कही थी. निचली अदालत केवकील भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट छोड़िए, ग़रीब तो निचली अदालत में भी मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह जानता है कि कोर्ट-कचहरी में न जाने कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए वह दोहरे नुक़सान से बचना चाहता है.

नवीन चौहान

भारत में देर से न्याय मिलने की कहानियां बहुत पुरानी हैं. देश भर की अदालतों में लगभग सवा दो करोड़ मामले लंबित हैं. 2.1 करोड़ मुक़दमे तो केवल जिला और सत्र न्यायालयों में लंबित हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि इनमें से 20 लाख मामले तो एक दशक या उससे ज्यादा समय से लंबित हैं. इन मामलों में से 13 लाख फौजदारी (क्रिमिनल) मुकदमे हैं. अभी भी अदालतों में मामलों की सुनवाई में घिसे-पिटे तरीके से हो रही है. किसी तरह का व्यवस्थात्मक परिवर्तन अदालतों में दिखाई नहीं दे रहा है. वर्तमान में जिस गति से मामलों की सुनवाई हो रही है, उस हिसाब से इन मामलों का पटाक्षेप होने में आठ से नौ साल का वक्त लगेगा, जिसका भार सरकारी खजाने पर पड़ने के साथ-साथ न्याय की आस लगाए बैठे करोड़ों लोगों की जेब पर भी पड़ेगा.

पिछले साल सितंबर में देर से फैसला सुनाने की सारी हदें तब पार हो गईं थीं, जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही हाईकोर्ट से न्याय पाने के लिए 39 साल लंबा इंतजार करना पड़ा. आलम देखिए कि जब फैसला आया, तब वह इस दुनिया में ही नहीं थे. मामला भी कोई ऐसा-वैसा नहीं था, तीन युवकों ने उनकी कार पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया था. हालांकि, दोनों ही ग्रेनेड नहीं फटे और कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ था. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. इसी तरह न्याय मिलने में हुई देरी का एक अन्य उदाहरण बहुचर्चित सूर्यानेल्ली दुष्कर्म मामला है. इस मामले में केरल हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में 18 साल लगा दिए. घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. उसे आरोपी केरल एवं तमिलनाडु की विभिन्न जगहों पर ले गए थे और 3000 किमी की यात्रा के दौरान चालीस दिनों में 36 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. निचली अदालत ने साल 1996 में आरोपियों को बरी कर दिया था. इसके बाद मामला हाइकोर्ट पहुंचा. मुक़दमे की सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई. इस मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए बनाई गई पीठ ने सात आरोपियों को बरी कर दिया और शेष आरोपियों को 5 से 13 साल तक की सजा सुनाई.

कई बार केस न्यायाधीशों, राजनीतिक दखल और वकीलों की आपसी तनातनी की वजह से लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं. बिहार का चारा घोटाला इसका उदाहरण है. राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और 55 अन्य आरोपियों के खिलाफ साल 1997 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हुए थे. इस मामले में सीबीआई को लालू प्रसाद यादव को आरोपी साबित करने में 16 साल लग गए. इसी तरह का एक और उदाहरण इसी साल अगस्त में सबके सामने आया. तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में 20 साल तक एक गैर-जमानती वारंट पर कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट ने एसपी को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने राहत दे दी. इसी तरह बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद का मुकदमा भी 50 साल तक सत्र न्यायालय में चला. इसके बाद यह मामला उच्च न्यायालय और अब उच्चचम न्यायालय में लंबित है.

क्रिमिनल (फौजदारी) और सिविल (दीवानी) मुकदमों का अनुपात बिहार में सबसे ज्यादा है. यहां 83 प्रतिशत फौजदारी मामले लंबित पड़े हैं. इस मामले में तमिलनाडु की स्थिति में सबसे बेहतर है. यहां केवल 37 प्रतिशत फौजदारी मामले लंबित हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. इन राज्यों में अपराध का स्तर हमेशा से ज्यादा रहा है और यह सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है. देश भर में 20 लाख मामले दस साल या उससे ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं. 30 अक्टूबर, 2015 तक 27 राज्यों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश 10 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़े मामलों की सूची में पहले पायदान पर है. यहां 5,75,604 मुक़दमे 10 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं, जो कि कुल लंबित मामलों का 27.4 प्रतिशत है. लंबित मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज संतोष हेगड़े का कहना है कि हमारे देश में कई फोरम और प्रक्रिया संबंधी कानून हैं, ये सभी न्याय प्रक्रिया को बाधित करते हैं. इस तरह की बाधाओं को चिन्हित कर हमें उन्हें दूर करना चाहिए. सुनवाई में हो रही बेवजह देरी के लिए जजों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए. हर नवगठित सरकार एक नए तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहती है, लेकिन पहले से काम कर रही प्रणाली में सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं, ताकि वक्त और पैसों की बर्बादी को रोका जा सके.

एक अध्ययन के मुताबिक, यदि भारत में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश हों तो लंबित मामलों की संख्या में 83 प्रतिशत की कमी आ सकती है. साल 2009-2013 के बीच पांच सालों में देश भर के जिला और सत्र न्यायालयों में नतीजे तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई थी. सुनवाई के बाद नतीजे तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या 8.89 करोड़ से बढ़कर 11.15 करोड़ तक पहुंच गई. यदि इसी समयसीमा में पर्याप्त या स्वीकृत संख्या के बराबर न्यायाधीश मुकदमों की सुनवाई करते तो सभी अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या 2.25 करोड़ से घटकर 45.7 लाख तक पहुंच जाती. वर्तमान में देश में सभी न्यायालयों में 23 प्रतिशत जजों की कमी है. इंडिया स्पेंड ने अपने आकलन में पाया कि देश की निचली अदालतों में 4,580 न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं, यह मामलों के लंबित होने के प्रमुख कारणों में से एक है. न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियों के मामले में गुजरात देश में सबसे आगे है. यहां जजों के 1963 स्वीकृत पदों में से 747 पद रिक्त पड़े हैं और जिस गति से ये जज केसों को निपटा रहे हैं, उस लिहाज से 1096 जजों को लंबित पड़े 2,045,261 मामलों को निपटाने में 287 साल का वक्त लगेगा. गुजरात में जजों द्वारा केसों के निपटारे की गति भी राष्ट्रीय औसत से कम है. राष्ट्रीय औसत 43 है, जबकि गुजरात का औसत 19 है. लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, साल 2013 में देश के सभी जजों के समक्ष सुनवाई के लिए आए मामलों की औसत संख्या 1,625 थी. भारत में दस लाख की आबादी के लिए 17 जज हैं, जबकि आवश्यकता 50 जजों की है. वर्तमान में न्यायाधीश और जनसंख्या का अनुपात 17 प्रति दस लाख आबादी है. लॉ कमीशन ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में इस अनुपात को 50 तक लाने की अनुशंसा की है. न्याय व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए मुकदमों के निपटारे की एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए और जजों की इस बात की जवाबदेही होनी चाहिए कि वे एक निश्चित समय में मुकदमों का निपटारा करें. यदि वह ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए.

राज्यसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 अगस्त, 2015 तक उच्चतम न्यायालय में 28 और उच्च न्यायालयों में 633 जज कार्यरत हैं. उच्च न्यायालयों में कुल स्वीकृत 1,017 पदों में से 384 पद यानी 38 प्रतिशत रिक्त पड़े हैं. 31 दिसंबर, 2014 को निचली अदालतों में कुल स्वीकृत 20,214 पदों में से 4,580 पद रिक्त थे. इसका मतलब निचली अदालतों में 23 प्रतिशत पद रिक्त थे. यदि संख्या के आधार पर देखें तो देश के 24 उच्च न्यायालयों में से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत 160 पदों में से 84 पद रिक्त हैं. रिक्तियों के मामले में दूसरे स्थान पर हरियाणा है, जहां 31 रिक्तियां हैं. इसके बाद मुंबई(30), कर्नाटक(30) और गुजरात(23) का स्थान आता है. यदि प्रतिशत के आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ में 59 प्रतिशत, इलाहाबाद में 53 प्रतिशत, कर्नाटक में 48 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 46 प्रतिशत और उत्तराखंड में 45 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं. केरल, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा हाइकोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए हैं.

न्याय मिलने में देरी का कारण केवल जज और सुविधाओं की कमी नहीं है. कई बार वकील अपने आर्थिक फायदे के लिए मुकदमों को बेवजह लंबा खींचते हैं. न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी, जल्दी स्थानांतरण और प्रभावशाली लोगों के कारण भी इंसाफ मिलने में देरी होती है. जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने तो अदालतों को जज-अंकल सिंड्रोम से प्रभावित होने की बात आधिकारिक रूप से कही थी. निचली अदालत के वकील भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट छोड़िए, ग़रीब तो निचली अदालत में भी मुकदमा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह जानता है कि कोर्ट-कचहरी में न जाने कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए वह दोहरे नुक़सान से बचना चाहता है. संपत्ति विवाद के मुकदमों का फैसला आने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं. यदि कोई व्यक्ति अदालत में मुकदमा लड़ने की हिम्मत कर भी ले, तो सालों तारीख पर तारीख, वकील की फीस के साथ जगह-जगह रिश्वत देने के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है. निचली अदालत के बाद लोगों की हिम्मत दम तोड़ देती है. ज़मीन बंटवारे, किरायेदारी और ऐसे ही न जाने कितने मुकदमे लोग सालों से लड़ रहे हैं. वकील अपनी फीस के चक्कर में भी लोगों को चक्कर कटवाते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने कहा था कि आधारभूत ढांचे की कमी के कारण ही मुकदमों की संख्या बढ़ रही है. जजों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अदालतों को सुविधाएं दिलाने की तरफ़ भी उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया था. जजों एवं सुविधाओं की कमी, ग़रीब आदमी की अदालत से दूर होती पहुंच और इंसाफ में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी से आम आदमी में भी निराशा पैदा होती है. बड़े-बड़े वकील अपने मुवक्किल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सुनवाई को लंबे समय तक टलवाते रहते हैं. यह बात अदालत की जानकारी में होने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाता. सरकार को पुराने मामले वर्गीकृत कर मध्यस्थता के आधार पर ख़त्म कराने के लिए पहल करनी चाहिए. हर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर करके लोगों को राहत देनी चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास कम से कम अदालत के प्रति तो बना रहे. अन्यथा सरकारी व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है. ■

navinonline2003@gmail.com

राज्यवार लंबित केसों की संख्या

क्रमांक	राज्य	लंबित केस	लंबित मामले/हजार
1	उत्तर प्रदेश	4,751,545	24
2	महाराष्ट्र	2,971,629	26
3	गुजरात	2,044,401	34
4	पश्चिम बंगाल	2,375,685	15
5	बिहार	1,348,204	13
6	राजस्थान	1,262,979	18
7	कर्नाटक	1,186,388	19
8	तमिलनाडु	877,930	12
9	केरल	662,843	20
10	हरियाणा	520,063	21
11	पंजाब	504,702	18
12	आंध्र-तेलंगाना	761,322	09
14	झारखंड	281,989	09
15	असम	181,441	06
16	छत्तीसगढ़	171,127	07
17	हिमाचल प्रदेश	162,497	24
18	उत्तराखंड	162,404	16
19	जम्मू और कश्मीर	48,470	04
20	चंडीगढ़	32,901	31
21	त्रिपुरा	26,219	07
22	अंडमान और निकोबार	10,251	27
23	मणिपुर	7,922	03
24	मेघालय	4,831	02
25	मिज़ोरम	1,777	02
26	सिक्किम	1,346	02
कुल लंबित मामले		20,188,584	18

जजों की राज्यवार रिक्तियां

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्तियां
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1034	884	150
अरुणाचल प्रदेश	16	15	1
असम	403	312	91
बिहार	1670	1027	643
चंड़ीगढ़	30	30	0
छत्तीसगढ़	354	302	52
दिल्ली	793	476	317
दमन दीव और सिलवासा	7	6	1
गोवा	52	40	12
गुजरात	1963	1216	747
हरियाणा	644	485	159
हिमाचल प्रदेश	146	128	18
जम्मू और कश्मीर	244	221	23
झारखंड	578	382	196
कर्नाटक	1085	832	253
केरल और लक्षद्वीप	447	431	16
मध्य प्रदेश	1460	1243	217
महाराष्ट्र	2072	1784	288
मणिपुर	40	30	10
मेघालय	55	30	25
मिजोरम	67	31	36
नगालैंड	27	25	2
ओडिशा	690	569	121
पुदुचेरी	21	10	11
पंजाब	672	505	167
राजस्थान	1145	831	314
सिक्किम	18	15	3
तमिलनाडु	997	876	121
त्रिपुरा	104	78	26
उत्तर प्रदेश	2097	1761	336
उत्तराखंड	289	191	98
पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	994	868	126
कुल	20214	15634	4580

देश के सबसे ज्यादा लंबित मामले वाले पांच जिले

जिला	लंबित मामले
कोलकाता(प. बंगाल)	454,197
बड़ौदा(गुजरात)	436,680
सूरत(गुजरात)	331,2860
मुंबई(महाराष्ट्र)	328,769
उत्तर 24 परगना(प. बंगाल)	270,503

देश के सबसे कम लंबित मामले वाले पांच जिले

जिला	लंबित मामले
मंगन(सिक्किम)	018
सेनापति (मणिपुर)	025
ग्यालशिंग(सिक्किम)	034
नामची(सिक्किम)	158
उदलगुड़ी(असम)	416

बीज कंपनियां बाल श्रम को बढ़ावा दे रही हैं

आपने दुकानों और घरों में बच्चों को काम करते देखा होगा, लेकिन आपको शायद ही यह मालूम हो कि सब्जियों के बीज उत्पादन में भी बालश्रम का इस्तेमाल होता है. जिन मासूम बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, उन हाथों को औज़ार थमा दिए जाते हैं. अफ़सोस यह कि देश में बालश्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं के लाख प्रयासों के बावजूद इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उल्टे स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं. बचपन ख़त्म किया जा रहा है, मासूमों के सपने कुचले और बिखेरे जा रहे हैं.

तरुण फोर

हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित ग्लोबल रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के निदेशक डॉ. देवुलुरी वेंकटेश्वरलू द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विभिन्न बीज कंपनियों में बड़े पैमाने पर बालश्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है. रिपोर्ट बताती है कि उक्त बीज कंपनियों में बच्चों से बिना वेतन घंटों काम कराया जाता है. बीज उत्पादन से संबद्ध बाल मज़दूरों की संख्या लगभग 1.56 लाख है, जिनमें से 50,000 बच्चों की उम्र 14 साल या उसके आसपास है. यही नहीं, ज़्यादातर बाल श्रमिक दलित परिवारों के हैं, जिनकी संख्या लगभग 37,000 है. बालश्रम का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों में कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं.

एक नज़र इधर भी

माना जाता है कि भारत में 14 साल तक के बच्चों की तादाद पूरे अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा है. भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 प्रतिशत हिस्सा 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का है. यही नहीं, भारत में हर दस बच्चों में से नौ बच्चे किसी न किसी काम से संबद्ध हैं. इनमें से 85 प्रतिशत बच्चे पारंपरिक पेशे-कृषि कार्य में सहयोग करते हैं, नौ प्रतिशत बच्चे उत्पादन, सेवा एवं मरम्मत आदि कार्यों से जुड़े हैं और 0.8 प्रतिशत बच्चे कल-कारखानों में काम करते हैं.

लिमिग्रेन (फ्रांस), सकाटा (जापान) एवं अडवंटा (फ्रांस) जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों में बीज उत्पादन के काम में लगे मज़दूरों में बच्चों की भागीदारी 10 से 16 प्रतिशत है, जिनकी उम्र 14 साल या उससे कम है. यह अध्ययन महाराष्ट्र और कर्नाटक पर आधारित है, जहां देश में सबसे ज़्यादा यानी 80 प्रतिशत सब्जियों के बीजों का उत्पादन होता है.

रिपोर्ट के अनुसार, बीज कंपनियों में काम करने वालों में ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम मज़दूरी भी नहीं दी जाती. यही नहीं, महिलाओं को ज़्यादातर उन कार्यों में लगाया जाता है, जिनमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है, जैसे बीज रोपण और कटाई आदि कार्य. जबकि पुरुष मज़दूरों से लेकर उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव का काम लिया जाता है. महिला मज़दूरों को पुरुष मजदूरों के मुक़ाबले 11 से 47 प्रतिशत कम भुगतान किया जाता है. रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, दोनों ही राज्यों में बाल मज़दूरी के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस बाबत कोई क़दम नहीं उठाए गए. बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं, जैसे नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम और बैक टू स्कूल प्रोग्राम भी बाल मज़दूरी रोक पाने में ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाईं. बालश्रम उन्मूलन के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी हैं. राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के तहत 1.50 लाख बच्चे शामिल करने के लिए 76 योजनाएं मंजूर की गई हैं. तक़रीबन 1.05 लाख बच्चों को विशेष स्कूलों में नामांकित किया जा चुका है. श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना में देश के सभी 600 ज़िले शामिल करने के लिए योजना आयोग से 1,500 करोड़ रुपये की मांग की है. इस परियोजना के तहत 57 ख़तरनाक उद्योगों, ढाबों एवं घरों में काम करने वाले बच्चों (नौ से 14 साल तक) को शामिल किया जाएगा. सर्वशिक्षा अभियान इसी दिशा में उठाया एक महत्वपूर्ण क़दम है. बालश्रम किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल मज़दूरों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है. कुल बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत हिस्सा खेतिहर मज़दूर है, जबकि 30-35 प्रतिशत बाल श्रमिक कल-कारखानों में कार्यरत हैं. शेष खदानों, दुकानों, ढाबों एवं घरों में काम कर रहे हैं और नारकीय जीवन जीने को विवश हैं.

कृषि क्षेत्र में बालश्रम पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि खेतों में विषैले कीटनाशकों एवं रसायनों की मौजूदगी की वजह से उनके स्वास्थ्य को खासा नुक़सान पहुंचता है. पश्चिम बंगाल के डोआर क्षेत्र में सवा लाख से ज़्यादा बाल मज़दूर काम करते हैं. बगानों में काम करने वाले इन बच्चों में से 70 प्रतिशत अनियमित हैं. बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर वह बच्चा, जो स्कूल नहीं जाता, किन्हीं अर्थों में बाल श्रमिक ही है, क्योंकि उसे कई छोटे-मोटे काम करते हुए अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता करनी पड़ती है. यदि आंकड़ों पर नज़र डालें, तो 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में उस समय लगभग एक करोड़ 26 लाख बाल श्रमिक थे. जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2010 में देश के 21 राज्यों में किए गए सर्वे के 66वें चक्र तक बाल श्रमिकों की संख्या 49 लाख 84 हज़ार पाई गई. इस सर्वेक्षण के अनुसार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड के शहरी इलाकों में पांच से 14 साल तक की एक भी लड़की काम नहीं करती, जबकि सच यह है कि घर-घर जाकर काम करने वाली अधिकतर लड़कियां इसी आयु वर्ग की हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा*

● वर्ल्ड डिग्निटी डे के मौक़े पर ज़मीन एवं अन्य संसाधनों पर अपना हक़ जताने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकत्र दलित समुदाय लोग.

● इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्स्पो में शिरकत करते केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन.

● बेघर लोगों के लिए यमुना नदी के किनारे गीता घाट पर बने शेल्टर होम के लोकार्पण से पहले निरीक्षण करते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.

● छह दिसंबर को बाबरी विध्वंस के 23 साल पूरे होने पर नई दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करते मुस्लिम समुदाय के लोग. दूसरी ओर प्रदर्शन करते सीपीआई (एम) के कार्यकर्ता.

● दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मॉक ड्रिल करते एनडीआरएफ टीम के सदस्य.

बीते सालों में अन्नाद्रमुक के सरकार में रहने के दौरान द्रमुक पार्टी ने कई बार तमिल अस्मिता मामले को लेकर प्रदर्शन किए हैं. इस बार के चुनाव में भी यह उम्मीद की जा रही है कि एंटी एन्कम्बैंसी फैक्टर लागू रहेगा. हालांकि इतने प्रदर्शनों के बावजूद भी यह माना जा रहा है कि जयललिता बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं पहुंचेंगी. बीते साल हुए लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए चुनाव पूर्व ही कई और पार्टियों को साथ लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस संदर्भ में पार्टी के महासचिव और राज्य प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि हम कुछ नए गठजोड़ बनाकर राज्य चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं.

विधानसभा चुनाव 2016

दिग्गजों की साख दांव पर है

बीते कई वर्षों में हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव सर्वाधिक चर्चा में रहा, जिसके नतीजे भी आ चुके हैं. लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की खुमारी उतर चुकी है. पहले दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दी. उसके बाद बिहार चुनाव के नतीजे तो आश्चर्यजनक रूप से भाजपा के विपक्ष में रहे. अब 2016 में चार राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, और केरल जैसे प्रमुख राज्यों के साथ-साथ संघशासित प्रदेश पॉन्डीचेरी भी शामिल है.

अरुण तिवारी

हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं. इस चुनाव ने देश में राजनीतिक परिदृश्य को उलटने वाला काम किया है. हालांकि दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद यह कहा जा रहा था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और वहां पर भाजपा की हार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. बिहार के चुनाव को ज्यादा महत्व दिया गया और इसे जीवन और मरण का प्रश्न बना लिया गया. बिहार चुनाव में महागठबंधन ने फिर से भाजपा और उसके सहयोगी दलों को जबरदस्त पटखनी दी.

अब साल 2016 में भी कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अलावा असम, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पॉन्डीचेरी है. साल 2011 में तकरीबन 34 वर्षों के अखंड वाम शासन के बाद ममता बनर्जी ने इस राज्य में चुनावी जीत दर्ज कर सीपीआईएम को हाशिये पर ढकेल दिया था. ममता बनर्जी अब भी राज्य की सबसे प्रख्यात नेता हैं और उनकी धुरविरोधी सीपीआईएम एक अदद जननेता की आवश्यकता महसूस कर रही है. तमिलनाडु में जयललिता ने करुणानिधि की द्रमुक को सत्ता से बेदखल कर सरकार बनाई थी. इस राज्य में बीते कई बार इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सत्ता की अदला-बदली चल रही है. इस लिहाज से यह देखना दिलचस्प होगा कि जयललिता अपनी सरकार बचा पाती हैं या पुरानी गाथा फिर दोहराई जाएगी.

इससे उलट असम में साल 2001 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने के बाद तरुण गोगोई के लिए ये चुनाव किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं साबित होने वाले हैं. इसके पीछे यह भी वजह बताई जा रही है कि राज्य में कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं एंटी इनकमबैंसी फैक्टर भी उनके साथ चिपका हुआ है. केरल में कांग्रेस के ओमान चांडी ने सत्ता पर मजबूती पैर जमाए सीपीआईएम को उखाड़ फेंका था. पांच साल के भीतर राज्य के हालात काफी बदले हैं. वहां वाम दल ने फिर से खुद को मजबूत किया है, वहीं भाजपा ने भी हाल में राजधानी के निकाय चुनाव में जीत हासिल कर अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में तेजी ला दी है. पॉन्डीचेरी में कांग्रेस अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बनने वाले एनआर रंगासामी की सरकार है. इस समय उनकी पार्टी एनआर कांग्रेस एनडीए का हिस्सा है.

पश्चिम बंगाल

बिहार चुनाव में जीत के बाद जब नीतीश कुमार की जीत का मंच सजा तो जो नेता उसमें सबसे प्रमुखता से नजर आ रही थीं, वो थीं ममता बनर्जी. हालांकि उस मंच पर सीपीआईएम के नेता भी मौजूद थे, लेकिन जितनी गर्मजोशी के साथ नीतीश और लालू ममता बनर्जी के साथ मिले, वैसा पश्चिम बंगाल के शायद किसी दूसरे नेता के साथ मिले हों. ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन को निर्णायक जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के आगामी चुनाव में प्रचार की कमान थाम सकते हैं.

अगर बीते चुनाव के लिहाज से सीटों का जायजा लिया जाए तो विधानसभा की कुल 294 सीटों में 191 तृणमूल कांग्रेस के पास हैं. 60 सीटें सीपीआईएम, 35 कांग्रेस, 3 गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, 1 भाजपा, 1 सोशलिस्टू यूनिटी इन इंडिया-मार्क्स वादी व अन्य के पास 3 सीटे हैं. बीते चुनाव में सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए तत्पर नजर आ रही है, लेकिन उसे इसका कोई विशेष फायदा होता नहीं दिख रहा है. ज्योति बसु जैसे बड़े नेताओं ने राज्य में पार्टी में जो जान फूंकी थी, उसकी बदौलत उसने राज्य में लंबे समय तक शासन किया, लेकिन वर्तमान समय में ममता बनर्जी राज्य की जनता को यह बताने में कामयाब मानी जा रही हैं कि गरीबों के सवाल पर वामदलों से भी ज्यादा सक्रियता दिखाएंगी. वहीं एक दूसरा फैक्टर अल्पसंख्यक मतों का भी है. दरअसल, राज्य में मुसलमानों का मत प्रतिशत तकरीबन 27 प्रतिशत है. मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तीर दिनाजपुर, बीरभूम जैसे जिलों में अल्पसंख्यक ही तय करेंगे कि जीत किसकी हो. मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम के विधानसभा क्षेत्र में नेता सूर्यकांत मिश्र राज्य में बीते कई दशकों से सक्रिय हैं और वाम सरकारों में मंत्री भी रहे. लेकिन उनकी मौजूदगी भी जनता को ममता दीदी के करीब जाने से रोक नहीं पा रही है. ममता बनर्जी ने जनसरोकारों की राजनीति में वामदलों को ऐसा झटका दिया था, जिससे उनकी पार्टी उबर नहीं पा रही है. हालांकि एक बात है, जो तृणमूल नेताओं की छवि को थोड़ा धक्का पहुंचाती है और वह है समय-समय पर की गई असंतुलित बयानबाजी. इससे तृणमूल नेताओं को बचकर रहना होगा.

राज्य में कांग्रेस के पास 35 सीटे हैं. हालांकि बीते कई दशकों से वह राज्य की सत्ता से दूर है, लेकिन पार्टी में कई बड़े नाम पश्चिम बंगाल से रहे हैं. पार्टी के सामने यह चुनौती होगी कि वह देश की सबसे पुरानी पार्टी होने की अपनी साख को कायम रख सके. बिहार में हुए महागठबंधन के कारण कांग्रेस ने राज्य में जबरदस्त वापसी की है. ममता बनर्जी भी महागठबंधन का समर्थन कर रही हैं. इसके पहले वह यूपीए में भी रह चुकी हैं. अगर कांग्रेस राज्य में तृणमूल के साथ तालमेल बैठा लेने में कामयाब हो जाती है तो यह उसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. वहीं भाजपा के लिए राज्य में अच्छी बात यह है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है. नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में काबिज होने की वजह से पार्टी पर भारी दबाव रहेगा कि वह अपने धुर प्रतिद्वंद्वी वाम दल और ममता बनर्जी के समक्ष कैसा प्रदर्शन करती है.

तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य के बारे में एक कहावत है कि यहां सत्ता का दो दलों के बीच अदल-बदल चलता रहता है. कभी द्रमुक तो कभी अन्नाद्रमुक के बीच ही सत्ता की कहानी सिमटी हुई है.यहां पर विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के लिए उतना स्पेस नहीं होता, जितना की दूसरे राज्यों में. क्षेत्रीय मुद्दे चुनावों में बुरी तरह प्रभावी होते हैं, जिन पर इन दो क्षेत्रीय पार्टियों का एकाधिकार सरीखा बन गया है. साल 2005 में तमिल फिल्म स्टार विजयकांत ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी डीएमडीके बनाई थी. इस पार्टी ने साल 2011 के चुनाव में 29 सीटें जीत कर द्रमुक से ज्यादा सीटें हासिल की थीं. डीएमडीके बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए में शामिल हो गई थी. द्रमुक के खाते में कुल 23 सीटें आईं थीं, जबकि अन्नाद्रमुक ने 152 सीटें जीत कर प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल की थी. वामपंथी पार्टियों ने भी राज्य में 18 सीटों पर कब्जा जमाया था. वहीं कांग्रेस को पांच सीटें आईं थीं.

बीते सालों में अन्नाद्रमुक के सरकार में रहने के दौरान द्रमुक पार्टी ने कई बार तमिल अस्मिता मामले को लेकर प्रदर्शन किए हैं. इस बार के चुनाव में भी यह उम्मीद की जा रही है कि एंटी एन्कम्बैंसी फैक्टर लागू रहेगा. हालांकि इतने प्रदर्शनों के बावजूद भी यह माना जा रहा है कि जयललिता बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में नहीं पहुंचेंगी. बीते साल हुए लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने राज्य में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए चुनाव पूर्व ही कई और पार्टियों को साथ लेने की कवायद शुरू कर दी है. इस संदर्भ में पार्टी के महासचिव और राज्य प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि हम कुछ नए गठजोड़ बनाकर राज्य चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा सभी जातियों को विकास के मुद्दे पर एक करने का प्रयास करेगी, लेकिन यह कितना कारगर होगा, कहना मुश्किल है. वहीं द्रमुक के प्रवक्ता टीकेएस इलागोवन ने कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में कम से कम 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि हालांकि उनकी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के साथ अभी तक कोई चर्चा तो नहीं की है, लेकिन वे कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ गठजोड़ पर विचार कर सकते हैं.

आगामी साल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें असम अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है. यहां बीते 15 सालों से कांग्रेस की सरकार है और तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हैं. लेकिन बीते आम चुनाव के बाद राज्य में सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. हेमंत विश्वशर्मा, जयंतमल्ल बरुआ, पियूष हजारिका, पल्लबलोचन दास, बोलिन चेतिया, कृपानाथ मल्ल, बिनान्दा सैकिया, प्रदन बरुआ, राजेन बोर्थकर, अबु ताहेर बेपारी जैसे नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. राज्य में बीते कई सालों से शासन करने के कारण कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं लग रही है.

असम

आगामी साल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें असम अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है. यहां बीते 15 सालों से कांग्रेस की सरकार है और तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हैं. लेकिन बीते आम चुनाव के बाद राज्य में सत्तारूढ़ दल के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. हेमंत विश्वशर्मा, जयंतमल्ल बरुआ, पियूष हजारिका, पल्लबलोचन दास, बोलिन चेतिया, कृपानाथ मल्ल, बिनान्दा सैकिया, प्रदन बरुआ, राजेन बोर्थकर, अबु ताहेर बेपारी जैसे नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. राज्य में बीते कई सालों से शासन करने के कारण कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं लग रही है. बीते चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की कुल 126 सीटों में कांग्रेस ने 59 सीटें हासिल कर सहयोग लेकर सरकार बनाई थी. वहीं बदरुदीन अजमल की ऑल इंडिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी इन चुनावों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. हग्रामा मोहिलारी की बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने बीते चुनाव 12 सीटें जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था. बिहार चुनाव में हार से संभवत: सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले वहां की अपनी इकाई का अध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया. पार्टी ने ऐसा कर संकेत दे दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं. यह घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हाल ही में कई कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए प्रदेश के पूर्व दिग्गज कांग्रेस नेता हिमंत विश्वशर्मा समिति के संयोजक होंगे.

केरल

केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं. बीते चुनाव में यहां पर कांग्रेस नीत गठबंधन ने 72 सीटें हासिल कर सत्ता हासिल करने में कामयाबी पाई थी. इस गठबंधन का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है. सीपीआईएम की अगुवाई वाले एलडीएफ ने 68 सीटें हासिल की थीं. यानी एलडीएफ भले ही सरकार बनाने से चूक गई हो, लेकिन वह चुनाव में बुरी तरह नहीं परास्त हुई थी. लड़ाई मुकाबले की थी. कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने ओमान चांडी वहां लोकप्रिय नेता हैं. हालांकि अपने शासनकाल के दौरान चांडी ने कुछ ऐसे निर्णय भी लिए, जिसकी आलोचना हुई. उन्होंने शराबबंदी का निर्णय लिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ राज्य के राजस्व में कमी आई, बल्कि पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ा था, जो राज्य की आर्थिक तौर पर नींव माना जाता है. आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2011 के चुनाव में यूडीएफ को 45.83 फीसदी मत मिले, जबकि एलडीएफ को 44.9 फीसदी. यूडीएफ को 72 सीटों पर जीत मिली, जबकि एलडीएफ को 68 पर. भाजपा की मत हिस्सेदारी 6.03 फीसदी रही. तकरीबन 35 सीटों पर अंतर 5,000 से कम मतों का रहा. ये सीटें उलटफेर की वजह बन सकती हैं. वर्ष 2006 में महज 6 फीसदी मतों के अंतर के बावजूद एलडीएफ 140 सीटों वाली विधानसभा में 100 सीटें जीतने में कामयाब रही. ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं? वाम दलों के दो सबसे बड़े नेताओं अच्युतानंदन और पिनराई विजयन के बीच परस्पर नुकसानदायक झगड़ा है. पंचायत चुनाव में मिली आंशिक सफलता से भाजपा भी उत्साहित है, लेकिन सबसे अधिक लाभ यूडीएफ को हो सकता है.

पॉन्डीचेरी

पॉन्डीचेरी दिल्ली की तरह ही केंद्रशासित प्रदेश है. यहां एनआर कांग्रेस की सरकार है. यहां के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हैं. इस पार्टी के पास 30 सीटों वाली विधानसभा में 15 सीटें हैं. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जिसके वी वैथिलिंगम पूर्व मुख्यमंत्री हैं. ये दोनों ही नेता जनता के बीच लोकप्रिय हैं, इस वजह से इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है कि राज्य का चुनाव बहुत रोचक होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

संविधान के अनुपालन की बेहद ज़रूरत है

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक समाजवादी और लोकतांत्रिक देश है. अब यह बेहद जरूरी है कि सरकार संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे. सरकार को गरीबों के हित में सोचना होगा. छात्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचना होगा. कॉर्पोरेट तरीके से चलकर यह हासिल नहीं हो पाएगा. गरीबी के बारे में जो आंकड़े आ रहे हैं, वे मुझ जैसे व्यक्ति को शर्म से सिर झुकाने को मजबूर कर रहे हैं. आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं, जरूरी यह है कि हमें गरीबों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए.

वास्तव में स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? यह हम सभी को, फिर चाहे वे राजनेता हों, अन्य लोग हों, औद्योगिक घरानों के मुखिया हों, या सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी को एक बार फिर से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए. क्या हम उसी राह पर चल रहे हैं, जैसा कि संविधान में उल्लिखित है या 1952 से लेकर आज तक संविधान के सभी भाग को धीरे-धीरे विकृत कर रहे हैं? विकृत इस रूप में कि कागजों पर तो हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है. उदाहरण के लिए, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार का चुनाव कैसे होता है और उसके कर्तव्य क्या हैं. सरकार की भूमिका क्या है. यह भी स्पष्ट है कि चुनी हुई सरकार नीतियां बनाए, वह चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, लेकिन उनका क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा व दूसरी सेवाओं के अधिकारी हैं, जो एक कठिन प्रक्रिया के बाद चयनित होते हैं. इन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कुशल लोगों का चयन होता है. इसलिए इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ये अधिकारी सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है?

नहीं! दुर्भाग्य से जो भी राजनीतिक दल चुनकर आए, उन्होंने छोटे-छोटे मुद्दों पर ही अपनी रुचि दिखाई, न कि बड़े व जरूरी विषयों पर. कोई भी राजनीतिक दल उन आधारभूत विसंगतियों को बदलना नहीं चाहता, जो समूचे देश में व्याप्त हैं. उदाहरण के तौर पर, जब विभाजन हुआ, तो दुर्भाग्य से जिन्ना ने विभाजन धर्म के आधार पर किया और पाकिस्तान का निर्माण भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए हुआ, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से विभाजन हुआ, यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में उससे ज्यादा मुस्लिम रह गए, जितने कि विभाजन के बाद पाकिस्तान गए. यह क्या दर्शाता है? और जो मुस्लिम भारत में ही रह गए, उन्होंने यहीं पर रहने को क्यों तरजीह दी? क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा और सरकार देश के नागरिकों के लिए धर्म को कभी आधार नहीं बनाएगी. धर्म एक व्यक्तिगत मसला है. इसका केवल इतना-सा मतलब है कि आप ईश्वर को बस किसी और नाम से याद कर रहे हैं. आप कहीं इसे भगवान कह सकते हैं, कहीं अल्लाह, कहीं जीसस क्राइस्ट, तो कहीं वाहे गुरु. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम से बुला रहे हैं, लेकिन क्या हम उस भावना के साथ चल रहे हैं? अगर मैं मुसलमान होता (जो कि मैं नहीं हूं) और भारत में रह रहा होता, तो निराश होता, क्योंकि देश के महान नेताओं ने जो वायदा किया था, उसे बाद की सरकारों ने निभाया नहीं. हां, यह सही है कि सबने हमें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया. इस देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिमों का है, लेकिन उनकी सहभागिता क्या है, यह बड़ा सवाल है.

> **उदाहरण के तौर पर, जब विभाजन हुआ, तो दुर्भाग्य से जिन्ना ने विभाजन धर्म के आधार पर किया और पाकिस्तान का निर्माण भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए हुआ, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से विभाजन हुआ, यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में उससे ज्यादा मुस्लिम रह गए, जितने कि विभाजन के बाद पाकिस्तान गए. यह क्या दर्शाता है? और जो मुस्लिम भारत में ही रह गए, उन्होंने यहीं पर रहने को क्यों तरजीह दी? क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा**

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में दो प्रतिशत, भारतीय पुलिस सेवा में दो प्रतिशत और कॉर्पोरेट जगत में तो बमुश्किल एक या दो प्रतिशत. फिर उन्हें क्या हासिल हुआ? साफ है कि मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ. उन्हें बराबर के अवसर नहीं मिले. उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई. ज्यादातर मुसलमान आज भी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं.

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक समाजवादी और लोकतांत्रिक देश है. अब यह बेहद जरूरी है कि सरकार संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे. सरकार को गरीबों के हित में सोचना होगा. छात्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचना होगा. कॉर्पोरेट तरीके से चलकर यह हासिल नहीं हो पाएगा. गरीबी के बारे में जो आंकड़े आ रहे हैं, वे मुझ जैसे व्यक्ति को शर्म से सिर झुकाने को मजबूर कर रहे हैं. आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं, जरूरी यह है कि हमें गरीबों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए. कॉर्पोरेट तरीके से चलकर यह हासिल नहीं हो पाएगा. गरीबी के बारे में जो आंकड़े आ रहे हैं, वे मुझ जैसे व्यक्ति को शर्म से सिर झुकाने को मजबूर कर रहे हैं. आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं, जरूरी यह है कि हमें गरीबों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए.

यह भी सोचना होगा कि हम किस तरह से सबसे निचले तबके या गरीब तबके को मध्यम वर्ग की श्रेणी में ले आएं. अमीर और अमीर हो रहे हैं, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन गरीब अभी भी वहीं है, जहां पहले था. देश का मध्यम वर्ग बेहतरी के रास्ते पर है और आपके इर्द-गिर्द मॉल, मोटर गाड़ी, अच्छी सड़कों व विदेशी ब्रान्ड की चमक-दमक है, लेकिन ये उस आदमी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकतीं, जिसके पास जमीन नहीं है. भूमिहीन श्रमिक अभी भी भूमिहीन श्रमिक ही है और गांव का गरीब व्यक्ति अभी भी गरीब है. वह केवल टीवी पर उभरती हुई तस्वीरों के माध्यम से ही इस चमक को देख सकता है और वह उसके भीतर टीस पैदा करती हैं. इस दौर में संविधान के अनुपालन की बेहद जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी करो या मरो का सवाल है

उस दिन आधे घंटे पहले बिल गेट्स नीतीश कुमार से मिलकर निकले थे. अचानक मेरा पटना जाना हुआ और नीतीश कुमार से मेरी मुलाकात हो गई. मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे यह मेरी संभवत: पहली मुलाकात थी. मैं सोचकर गया था कि मुझसे चिंतित, परेशान और बिहार के भविष्य को लेकर गुत्थियों से उलझ रहे नीतीश कुमार की मुलाकात होगी. लेकिन, मुझे नीतीश कुमार बिल्कुल सहज, सरल और निश्चिंत नीतीश कुमार मिले.

मेरे सामने सवाल था. कोई भी पत्रकार अपने मन के सवालों को दबा नहीं सकता. वह सवालों को पूछता ही है. मैंने बिना सवाल पूछे आम पत्रकारों से अलग कुछ जानने की कोशिश की. अगर सामान्य पत्रकार होते, तो लालू प्रसाद यादव से उनके रिश्ते के बारे में पूछते, नरेन्द्र मोदी से रिश्तों के बारे में पूछते, आने वाली परेशानियों के बारे में पूछते, लेकिन मुझे लगा कि नीतीश कुमार से शराबबंदी के ऊपर सवाल पूछना चाहिए. ऐसा इसलिए, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर यह आरोप था कि जिस बिहार में गांवों में पानी नहीं है, वहां ठंडी बीयर उनके शासनकाल में ही सर्वसुलभ हुई. यह वह दौर था, जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार चला रहे थे. अचानक नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले शराबबंदी की घोषणा कर दी थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद, पिछले मद्यनिषेध दिवस पर नीतीश कुमार ने घोषणा भी कर दी कि एक अप्रैल से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी. नीतीश कुमार इस काम को कैसे करेंगे? यह सवाल मेरे दिमाग में था. क्या नीतीश कुमार रोलबैक करेंगे? यू-टर्न लेंगे या इसमें कुछ संशोधन करेंगे. इस पर मैंने कुछ दाएं से, बाएं से नीतीश कुमार से जानना चाहा. जो मुझे पता चला, उससे मुझे थोड़ा अचम्भा हुआ.

नीतीश कुमार सौ प्रतिशत शराबबंदी लागू करने की मन:स्थिति में मुझे दिखाई दिए. उन्होंने अपने विभाग को बोल दिया है, संबंधित मंत्री से भी बोल दिया है कि योजना बनाई जाए कि किस तरह यह शराबबंदी लागू हो. आमतौर पर उच्च-मध्य वर्ग का तबका और उच्च वर्ग के लोग महंगी शराब पीते हैं, जिसे हम अंग्रेजी शराब कहते हैं और देहात जगह महिला संगठनों ने मुझे कहा कि उनका घर बर्बाद हो रहा है. उनके पति जितना पैसा कमाते हैं, वो शराब में उड़ा देते हैं. इसलिए मैं इसके बारे में कुछ सोचूं. मुझे लगा कि इन महिलाओं का साथ देना चाहिए. तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो पूर्ण मद्यनिषेध बिहार में लागू होगा. इसकी घोषणा की वजह से 50 प्रतिशत महिलाओं ने उन्हें खुलकर वोट दिए. नीतीश कुमार ने बताया कि मैं महिलाओं की एक सभा में गया और जब भाषण के बाद बैठ गया, तो पीछे से तीन महिलाओं ने आवाज लगाई कि शराबबंदी के बारे में कुछ बोलिए. महिलाओं की मांग थी कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए. मैं फौरन दोबारा उठकर मंच पर गया और कहा कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो मैं शराबबंदी करूंगा. उन्होंने कहा कि उस दिन की सबसे बड़ी खबर यही थी, जिसे देश के समाचार पत्रों और टेलीविजन पर दिखाई गई. यह खबर इस तरीके से दिखाई गई कि जैसे मैंने एक ऐसा वादा कर लिया है, जिसे मैं कभी पूरा नहीं करूंगा. इसीलिए, मद्यनिषेध के अवसर पर मुझे एक अप्रैल से शराबबंदी की घोषणा करने में अपार हर्ष का अनुभव हुआ. नीतीश कुमार गरीबों को लेकर ज्यादा संवेदनशील दिखाई दिए. उनका पहला सरोकार बिहार में गांवों में शराब को लेकर हो रहे आर्थिक नुकसान, मौत और बीमारी को लेकर है. इसलिए, उनके सारे विभाग पूरे तौर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे एक अप्रैल से बिहार के गांवों में शराब न पहुंचे. अमीर लोग शराब पीते हैं. यह नीतीश कुमार की दूसरी चिंता है. उनका मानना है कि ऐसी शराब के ऊपर अगर तत्काल सकारात्मक ढंग से रोक नहीं भी लग पाई, तो उस पर बाद में वो रोक लगा लेंगे. चोरी-छिपे जितनी शराब आएगी, अमीरों को उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. लेकिन गरीब की जेब से ज्यादा पैसा निकलना शराबबंदी के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा. इसलिए, वो शराबबंदी और खासकर अवैध ढंग से शराब आने के रास्तों को रोकने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं. जब मैंने सवाल पूछा कि आपको नहीं लगता कि सरकारी अमले के जरिए शराबबंदी लागू करना मुश्किल है. तब मुझे नीतीश कुमार का वो चेहरा दिखाई दिया, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर रहा था. नीतीश कुमार ने कहा कि मैं शराबबंदी महिलाओं के सहयोग से रोकूंगा. मैं पूरे बिहार में शराबबंदी को लेकर महिलाओं से कहूंगा कि वो आगे आएं, आंदोलन करें, गांव-गांव में खड़ी हो जाएं और जहां पर भी उन्हें शराब आती हुई दिखे, बिकती हुई दिखे, उसके खिलाफ वो आंदोलन करें. पूरी सरकार उनका समर्थन करेगी. नीतीश कुमार जिस तरह पूरे महीना बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार उसकी तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं. बिहार के गांव-गांव में उनकी योजना है कि महिलाओं की समिति बने, जो शराबबंदी के लिए चट्टान की तरह गांव की सुरक्षा कवच में तब्दील हो जाए. बिहार की महिलाएं अगर नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गईं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो खड़ी होंगी, तो मैं यह भी

> **अगर बिहार में मद्यनिषेध जनता या महिलाओं की ताकत और सहयोग से लागू होती है, नीतीश कुमार इसमें सफल होते हैं, तो नीतीश कुमार देश के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे, जिन्हें लोग देश के नेता के रूप में देखना शुरू कर देंगे. समस्या कठिन है. उसका समाधान और कठिन है. नीतीश कुमार की रणनीति उन्हें देश में अद्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में पहचान देगी या नहीं देगी, इसका फैसला एक अप्रैल से होगा.**

करने में यकीन करता है. दूसरी तरफ, वो शराबबंदी या ऐसे सवालों, जिनका रिश्ता समाज की कुरीतियों से है, का मुकाबला जनता का साथ लेकर करना चाहते हैं. नीतीश कुमार इस काम में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये अप्रैल का भविष्यवाणी कर सकता हूं कि नीतीश कुमार देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, जो जनता की इच्छा के फैसले को सरकार द्वारा लागू करवाने में प्रथम स्थान पर होंगे. महिलाओं का प्रयोग शराबबंदी के लिए अगर तूफानी सफलता हासिल करता है, तो मेरा यह भी मानना है कि फिर बिहार के विकास के कामों में होने वाले भ्रष्टाचार का मुकाबला पंचायतों के द्वारा कैसे किया जा सकता है, इसकी भी योजना नीतीश कुमार बनाएंगे. नीतीश कुमार ने अपना एक दर्द मुझसे कहा और शायद इसलिए कहा कि उस दर्द का एक हिस्सा उन्हें मुझसे भी मिला है. नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में या पिछले से पिछले कार्यकाल में हमने उन्हें अहंकारी मुख्यमंत्री लिखा था. बिहार के जितने भी जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे, उनकी शिकायत थी कि नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते. नीतीश कुमार ने इस बातचीत के अंत में, जो लगभग कई घंटे चली, बताया कि अगर वो बैठकर योजनाएं नहीं बनाते और बिहार के विकास का नक्शा बिहार के अफसरों को नहीं समझाते, तो बिहार आज वहां नहीं होता, जहां पर है. उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे बहुत अपमान झेलना पड़ा और लोगों की बहुत बातें झेलनी पड़ीं. मैं समझ गया कि उनका इशारा मेरी तरफ भी है. लेकिन उन्होंने कहा कि मिलना मैं सबसे था, पर उस समय नहीं मिलता था, जब वो चाहते थे. मैं तब मिलता था, जब मेरा प्रशासनिक काम पूरा हो जाता था. तब मुझे लगा कि नीतीश कुमार के रूप में बिहार को एक ऐसा नेता मिला है, जिसे हम देश में आदर्श मुख्यमंत्री या जननेता की संज्ञा दे सकते हैं.

मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी है. साथ ही बिहार के लिए भी परीक्षा की घड़ी है. अगर बिहार में मद्यनिषेध जनता या महिलाओं की ताकत और सहयोग से लागू होती है, नीतीश कुमार इसमें सफल होते हैं, तो नीतीश कुमार देश के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएंगे, जिन्हें लोग देश के नेता के रूप में देखना शुरू कर देंगे. समस्या कठिन है. उसका समाधान और कठिन है. नीतीश कुमार की रणनीति उन्हें देश में अद्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में पहचान देगी या नहीं देगी, इसका फैसला एक अप्रैल से होगा. लेकिन जिस तेवर के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि यह मेरे लिए करो या मरो का प्रश्न है, वह बताता है कि गांधी के इस वाक्य के पीछे की प्रेरणा आज नीतीश कुमार को एक नए दायरे में ले जाने के लिए अवश्य प्रेरित करेगी और उन्हें सफल भी करेगी. ■

editor@chauthiduniya.com

बदनसीब राजस्थान-अंतिम

केंद्रीय सहयोग के बगैर समाधान असंभव

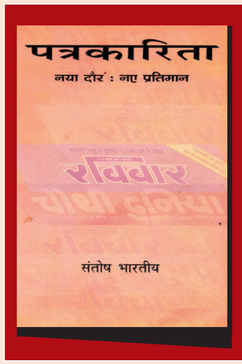

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

राजस्थान में बड़े उद्योगों की भी कमी है. यहां खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर और उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक के कारखाने लगे हैं. एचएमटी ने अजमेर में अपनी एक यूनिट लगाई है. इसके अतिरिक्त छोटे-मोटे उद्योग हैं, लेकिन राजस्थान के विकास की दृष्टि से इन उद्योगों की भूमिका नगण्य है. अगर यहां उद्योगों की स्थिति खराब है, तो खेती भी अच्छी नहीं है. आज भी यहां खेतिहरों की हैसियत में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ है. लघु उद्योगों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, बैंकों द्वारा भी राज्य के विकास के लिए बहुत ही कम पूंजी का निवेश हुआ है. देश की सुरक्षा की दृष्टि से भारत-पाक सीमा पर स्थित इस राज्य का विशिष्ट स्थान है. अस्त्र-शस्त्र बनाने का एक भी कारखाना राजस्थान में नहीं है. न जाने कितने दिनों से यहां आर्डिनेंस फैक्ट्री खोलने की मांग की जा रही है. राजस्थान में सेना सिर्फ फायरिंग रेंज बना रही है. राजस्थान में जो भी उद्योग हैं, कोटा एवं अलवर में लगे हैं. कोटा में डीसीएम और जेके की बड़ी मिलें हैं. मोदी ने अलवर में कास्टिक सोडा की फैक्ट्री लगाई है. बजाज समूह का उदयपुर में सीमेंट प्लांट है. निंबाहेड़ा में जेके समूह का सीमेंट कारखाना है. भीलवाड़ा में कुछ कपड़ा मिलें हैं. पर ये सब एक इलाके में हैं. पश्चिमी राजस्थान तो उद्योग रहित है, आधारभूत सुविधाओं के अभाव में निजी उद्योग भी यहां आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं.

राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है. इस कारण सीमावर्ती समस्याओं से भी राजस्थान सरकार को ही जूझना पड़ता है. तस्करी विरोधी निगरानी में भी अधिकतर पैसा राजस्थान सरकार का खर्च होता है. बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर जैसे सीमावर्ती ज़िलों में तस्करों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियां बढ़ गई हैं. एक समाचार के अनुसार, तस्करों एवं सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत इतनी हो गई है कि सीमा पर यदि कोई अधिकारी पर्ची देता है, तो तस्कर सीमा पार जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें या अन्य सामान ले आते हैं. जबसे राजस्थान के रास्ते उग्रवादी पंजाब में प्रवेश करने लगे हैं, सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं. एक सूचना के अनुसार, सीमा पर रखवाली करने वालों में पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाले भी कुछ लोग हैं. श्रीगंगानगर में सीमा पार से आने वाले अवैध लोग यहां अपनी संपत्ति भी बना रहे हैं, जिससे राजस्थान में भी असम जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है. राजस्थान में पानी का सीधा अर्थ जीवन से है, जबकि पंजाब में पानी का मतलब पैसा है. राजस्थान में पंजाब समझौते को लेकर चिंता पैदा हो गई है. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का कहना है कि भारत सरकार घर की सुराही तोड़कर खेतों में डालना चाहती है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर तो पीने के पानी की समस्या हल करेगी.

राजस्थान में बराबर राजनीतिक स्थिरता रही है. अब लोग मानने लगे हैं कि इस स्थिरता से प्रदेश का नुक़सान हुआ है. कुछ वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजनेताओं ने मुझसे कहा कि अगर हमारे यहां भी दंगा होता रहता, तो कोच फैक्ट्री हमारे यहां ही लग जाती. विकास की मांग को लेकर आंदोलन की प्रथा भी इस राज्य में नहीं रही है. अब लोग देख रहे हैं कि जो राज्य आंदोलन कर रहे हैं, जहां की जनता केंद्र के ख़िलाफ़ संघर्ष की आवाज़ उठा रही है, उन्हीं राज्यों को केंद्र से भरपूर मदद मिल रही है. राजस्थान का लगभग पूरा बजट सिंचाई, पीने के पानी और शिक्षा पर ही खर्च हो जाता है. फिर भी पिछले 15 वर्षों से राजस्थान में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खुला है. नई योजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकार के पास पूंजी ही नहीं होती. पिछले आठ-दस वर्षों से राजस्थान में कर नहीं बढ़ाए गए थे. न ही आय के लिए दूसरे विकल्प ढूंढे गए थे. विभिन्न मदों में खर्च काफी बढ़ा, पर केंद्र द्वारा मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोत्तरी नहीं हुई. इसी दौरान राजस्थान की आबादी भी दोगुनी हो गई है. ज़मीन के लगान की दर में भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई. केवल शराब पर प्रतिबंध हटाकर सरकार ने कुछ आमदनी बढ़ाई है. राजस्थान के तक़रीबन सभी निगम घाटे में चल रहे हैं. विकास के काम में कैसी आधारहीन कठिनाइयां आती हैं, इसका उदाहरण सवाई माधोपुर में लगने वाला गैस बेस्ड पावर हाउस है, जो बहुत दिनों तक इसी विवाद का विषय रहा कि इसका निर्माण केंद्र या राज्य, किसके स्वामित्व में हो. राज्य की मछली (जयसमंद से) दिल्ली और कलकत्ता के बाज़ारों में बिकती है. राज्य से प्रतिदिन तीन लाख अंडे दिल्ली और अहमदाबाद भेजे जाते हैं तथा दिल्ली में 80 प्रतिशत दूध की आपूर्ति राजस्थान करता है.

अकाल, पानी की समस्या, बढ़ते रेगिस्तान और भयंकर ग़रीबी से राजस्थान सरकार कैसे निबटेगी, यह अहम सवाल है. इन जटिल परिस्थितियों में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी नए सिरे से राजस्थान में विकास की लड़ाई लड़ने की योजना बना रहे हैं. प्रथम चरण में उन्होंने ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, जिन पर विभिन्न आरोप थे और जो बचते आ रहे थे. उन्होंने अक़ुशल मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी बदला है. साथ ही चेतावनी भी दी है कि नई योजनाओं में रुकावट डालने वाले किसी भी अधिकारी को तत्काल सजा दी जाएगी. केंद्र ने कभी राजस्थान पर ध्यान नहीं दिया. राजस्थान के प्रतिनिधि भी कभी केंद्र पर दबाव नहीं डाल पाए. राजस्थान के केंद्र में पहले केंद्रीय मंत्री कालू लाल श्रीमाली और राज बहादुर थे. उनके बाद किसी को भी केंद्र में केंद्रीय स्तर का दर्जा ही नहीं मिला. सुखाड़िया प्रभावशाली मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान नहर योजना मंज़ूर कराई, पर उनके जाने के बाद वह पूरी नहीं हुई. संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री सभी कमज़ोर रहे तथा केंद्र से राज्य के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाए. नाथू राम मिर्धा और राम निवास मिर्धा जैसे लोग अपनी ही राजनीति में व्यस्त रहे. इसीलिए केंद्र ने कभी राजस्थान की ओर ध्यान नहीं दिया. राजस्थान के 13 ज़िले पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं, यहां के लोग अभी भावनात्मक रूप से भारत से नहीं जुड़ पाए हैं. इन ज़िलों के बाशिंदों का विश्वास अर्जित करना अति आवश्यक है. उन्हें यह एहसास कराना होगा कि वे हिंदुस्तान के ही हिस्से हैं. इसके लिए तत्काल राहत के व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए. अकाल, प्यास, भूख, पिछड़ेपन और बढ़ते रेगिस्तान के ख़िलाफ़ केंद्र के सहयोग से ही राजस्थान निबट सकता है. ■

(20 अक्टूबर, 1985)

feedback@chauthiduniya.com

देश का धर्म लोकतंत्र होना चाहिए

संविधान सभा का चुनाव परोक्ष रूप से 1945 में सीमित मताधिकार पर चुनकर आईं प्रांतीय असेंबलियों से किया गया था. संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. उसमें संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व था. हालांकि, पाकिस्तान के हक़ीक़त बन जाने के बाद मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी. इसके बावजूद संविधान सभा के सदस्यों में मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई एवं हिंदू यानी सभी शामिल थे. संविधान सभा के सदस्यों ने तीन वर्षों तक परिश्रम किया. इस दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए और खाद्यान्न संकट एवं शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा.

मेघनाद देसाई

भारत की विशाल और विविधता पूर्ण सरज़मीं को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी एक किताब या एक आस्था (धर्म) की खोज का एक अंतहीन सिलसिला रहा है. अकबर ने धर्मों का अपना संकलन दीन-ए-इलाही के रूप में जारी करने की कोशिश की, जो अधिक समय तक नहीं चल सका. ईसाई पादरी जब भारत आए, तो उन्होंने यहां के लोगों से पूछा, तुम्हारे पास कोई पवित्र किताब है? इस सवाल का सही जवाब था, हमारे पास एक नहीं, अनेक पवित्र किताबें हैं. लेकिन, जब ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया, तो राष्ट्रवादियों ने एक किताब पर सहमति बनाने की कोशिश की. कईयों ने वेद का चयन किया, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे, जो वेद पढ़ सकते थे. बाद में विवेकानंद के कारण वेदांत (हालांकि, यह किसी एक किताब पर आधारित नहीं था) धर्म बनाने का दावा पेश किया गया. बंगाली क्रांतिकारियों के लिए गीता एक प्रतिष्ठित किताब बन गई. कई क्रांतिकारी तो इसे सीने से लगाए फांसी के फंदे पर चढ़ गए. राष्ट्रवादी अपने आंदोलन का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर करना चाहते थे, लेकिन परेशानी यह थी कि संस्कृत ग्रंथ केवल ब्राह्मण पढ़ सकते थे. शूद्रों एवं दलितों को उनके पवित्र शब्द सुनने की इजाजत नहीं थी. अंबेडकर पवित्र किताबें न पढ़ पाने का अपमान समझते थे. चूंकि अंग्रेजों ने पवित्र किताबों का अनुवाद कराना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने वेदों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था. गांधी जी ने गीता को अपनाया. साथ ही उन्होंने चुनाव के लिए दलितों को हिंदू वर्ग में शामिल करने को लेकर अनशन किया, क्योंकि वह अंग्रेजों को ग़ैर हिंदू वोट वर्ग का लाभ नहीं उठाने देना चाहते थे.

संविधान सभा का चुनाव परोक्ष रूप से 1945 में सीमित मताधिकार पर चुनकर आईं प्रांतीय असेंबलियों से किया गया था. संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. उसमें संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व था. हालांकि, पाकिस्तान के हक़ीक़त बन जाने के बाद मुस्लिम लीग उसमें शामिल नहीं हुई थी. इसके बावजूद संविधान सभा के सदस्यों में मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई एवं हिंदू यानी सभी शामिल थे. संविधान सभा के सदस्यों ने तीन वर्षों तक परिश्रम किया. इस दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए और खाद्यान्न संकट एवं शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा. साथ ही एक बड़े और ग़रीब देश का शासन भी चलाना था. लेकिन, संविधान सभा ने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया. उसे मालूम था कि ब्रिटिश शासक भारत को एक राष्ट्र के बजाय समुदायों, क्षेत्रों एवं धर्मों का एक संग्रह समझते हैं. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया (भारत) की वास्तविकता भूमध्य रेखा (काल्पनिक रेखा) की तरह है. संविधान सभा का जवाब था कि भारत के लोग देश की सीमाओं के भीतर जाति, पंथ, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव के बिना रहते हैं. एक क्रांतिकारी कार्य उसने यह किया कि सभी वयस्क भारतीयों को मतदान का अधिकार दे दिया. उसे यह भी पता था कि भारत कई धार्मिक एवं क्षेत्रीय समुदायों का एक समूह है. इसलिए उसने आम जनता के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी मान्यता दी. उसने भारत को एक संघ के रूप में परिभाषित किया और इसके राज्यों को केंद्र के साथ बराबर का भागीदार बनाया. संविधान सभा ने भाषाओं को उनका दर्जा दिया और वंचित समूहों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा.

66 वर्षों के बाद हमें यह पता चला कि संविधान सभा ने हमें एक ऐसी किताब दी, जिसने भारत को किसी अन्य किताब से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित किया. संविधान सभा के दिग्गजों ने भारत की जनता को सर्वोपरि रखा. उन्होंने किसी नए धर्म के आविष्कार की ज़रूरत महसूस नहीं की. अगर आप चाहें, तो इसे लोक राज्य धर्म कह सकते हैं या फिर अकबर की पैरवी करते हुए दीन-ए-जम्हूरियत. ■

feedback@chauthiduniya.com

जीवन का ज्ञान

अनार के पत्ते, छिलका, पुष्प, कच्चे फल तथा मूल छाल को समभाग लेकर, मोटा पीसकर, दुगना सिरका तथा चार गुना गुलाब जल में भिगोएं. चार दिन बाद इसमें सरसों का तेल मिला धीमी आंच पर पकाएं. तैल मात्र शेष रहने पर छानकर बोतल में भरकर रख लें. इस तैल की रोज स्तनों पर मालिश करें तो स्तनों की शिथिलता दूर होती है, साथ ही जिनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, मांस ढीला पड़ गया हो, उन्हें भी इस तैल की मालिश से निश्चित लाभ होता है.

अनार

20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिली लीटर पानी में उबालें. पानी 100 मिली लीटर शेष रह जाए तो इसमें गर्म दूध मिलाकर लें. इससे शारीरिक व मानसिक थकावट मिटती है और अनिद्रा रोग दूर होता है.

पिछले अंक से आगे...

गुदा रोग:

1. रक्तार्श (खूनी बवासीर)– समभाग अनार फलत्वक चूर्ण सोंठ तथा चंदन के काढ़े में गोघृत मिलाकर पीने से खूनी बवासीर के कारण बहने वाले रक्त का स्तम्भन होता है.
2. कफ–दूषित रक्तार्श में अनार के तने की छाल का काढ़ा (20–40मिली)पीने से लाभ होता है.
3. 100 मिली अनार के रस में 10 ग्राम गोघृत तथा 65 मिग्रा यवक्षार मिलाकर पीने से दर्द युक्त खूनी बवासीर का शमन होता है.
4. अनार (लगभग 20–25 ग्राम)तथा इनके द्विगुण शर्करा से बनाए कल्क को 12 गुना जल में घोलकर प्रतिदिन प्रात:काल 11 दिनों तक सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है.
5. गुदभ्रंश– अनार फल त्वक चूर्ण एवं कल्क का बाह्याभ्यन्तर प्रयोग गुदभ्रंश तथा गुदा की जलन में लाभप्रद है.
6. अनार के ताजे पत्र से निर्मित अर्धावशेष क्वाथ से गुदा का प्रक्षालन करना गुदभ्रंश में हितकर है.
7. अर्श– अनार मूल की छाल से बनाए 100 मिली काढ़े में 5 ग्राम सोंठ चूर्ण मिलाकर दिन में 2–3 बार पीने से खूनी बवासीर में लाभ होता है.
8. 5–10 मिली अनार पत्र–स्वरस के सेवन से बवासीर में लाभ होता है.
9. अनार के 8–10 पत्रों को पीसकर वटी (टिकिया) बनाकर गोघृत में भून कर सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है.
10. मीठे फल का छिलका शीतल तथा खट्टेफल का छिलका शीतल, रूक्ष होता है. अत: बवसीर के लिए विशेष उपयोगी है.

यकृतप्लीहा रोग:

1. पाण्डु/कामला– 250 मिली अनार के रस में 750 ग्राम चीनी मिलाकर चाशनी बना लें. इसी का सेवन दिन में 3 या 4 बार करें.
2. 3–6 ग्राम छाया शुष्क अनार पत्र चूर्ण को प्रात: गौ की छाछ तथा सायं उसी छाछ के पनीर के साथ पाण्डु में सेवन कराएं.

वृक्कवस्ति रोग:

1. मूत्राघात– अनार के रस में छोटी इलायची के बीज और सोंठ का चूर्ण मिलाकर पिलाएं.
2. 10 ग्राम अनार पत्र और 10 ग्राम हरा गोखरू दोनों को 150 मिली जल में पीस–छान कर पिलाएं.

प्रजनन संस्थान रोग:

1. स्तनशैथिल्य– अनार के पत्ते, छिलका, पुष्प, कच्चे फल तथा मूल छाल को समभाग लेकर, मोटा पीसकर, दुगना सिरका तथा चार गुना गुलाब जल में भिगोएं. चार दिन बाद इसमें सरसों का तैल मिला धीमी आंच पर पकाएं. तैल मात्र शेष रहने पर छानकर बोतल में भरकर रख लें. इस तैल की रोज स्तनों पर मालिश करें तो स्तनों की शिथिलता दूर होती है, साथ ही जिनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, मांस ढीला पड़ गया हो, उन्हें भी इस तैल की मालिश से निश्चित लाभ होता है.
2. अनार की छाल को पीसकर लेप करने से उपदंशज व्रण में लाभ होता है.
3. पूयमेह–25 ग्राम अनार की छाल तथा 50 ग्राम खांड को 200 मिली जल में फाण्ट बनाकर प्रतिदिन प्रात:काल पीने से तीन दिन में ही सुजाक में लाभ होने लगता है.
4. गर्भपात– पांचवें मास में यदि गर्भिणी को गर्भपात की आंशका हो तो अनार पत्र तथा चन्दनचूर्ण में दधि तथा मधु घोलकर पीना चाहिए.
5. उपदंश– प्रतिदिन अनार पत्र कल्क का लेप घावों पर करने से तथा 5–10 ग्राम पत्र चूर्ण का सेवन करने से उपदंश में लाभ होता है.
6. श्वेतप्रदर– अनार फल त्वक के काढ़े में थोड़ा हल्दी चूर्ण मिलाकर उत्तरवस्ति देने तथा योनि को धोने से श्वेत– प्रदर में अतिशय लाभ होता है.

शाखा रोग:

1. नाखून की पीड़ा– अनार फूलों के साथ धमासा और हरड़ समभाग पीसकर नख में भरने से, नाखून के भीतर की सूजन और पीड़ा में लाभ होता है.
2. हस्तपादगत दाह– 10–12 अनार के ताजे पत्तों को पीसकर हथेली और पांव के तलवों पर लेप करने से हाथ–पांव की जलन में लाभ होता है.

त्वचा रोग:

1. व्रण– फूलों की कलियां जो हवा के झोकों से नीचे गिर पड़ती हैं, इन्हें जलाकर चोट पर बुरकने से घाव शीघ्र सूख जाते हैं.
2. अनार के 50 ग्राम पत्तों का 1 ली जल के साथ चतुर्थांश क्वाथ बनाकर घावों को धोने से विशेष लाभ होता है.
3. 8–10 अनार के पत्तों का कल्क बनाकर उपदंश के घावों पर लेप करने से बहुत लाभ होता है. साथ ही साथ पत्र चूर्ण 2 से 4 ग्राम का सेवन भी करना चाहिए.

मानस रोग:

1. उन्माद– 10 ग्राम अनार के पत्ते और गुलाब के ताजे पुष्प के अभाव में 5 ग्राम सूखे फूल लेकर आधा ली जल में पकाकर 250 मिली शेष रहने पर, 10 ग्राम गाय का घी मिलाकर गर्म–गर्म सुबह–शाम पिलाने से उन्माद और मिरगी में लाभ होता है.
2. अपस्मार– 20 ग्राम अनार के पत्रों से बनाए काढ़े में 10–10 ग्राम गाय का घी और खांड़ मिलाकर पिलाने से मिरगी या अपस्मार में लाभ होता है.
3. अनिद्रा–20 ग्राम अनार के ताजे पत्ते लेकर 400 मिली पानी में उबालें, जब 100 मिली शेष रह जाएं तो इसमें गर्म दूध मिलाकर पीयें. इससे शारीरिक व मानसिक थकावट मिटती है और अनिद्रा रोग मिटता है.

सर्वशरीर रोग:

1. 250 ग्राम अनार के ताजे पत्तों को 5 ली जल में उबालें तथा चार ली जल शेष रहने पर नहाने के लिए प्रयोग करने से उष्णकाल की पित्ती शान्त होती है.
2. आन्त्रिक ज्वर– अनार पत्र के काढ़े में 500 मिग्रा सेंधानमक मिलाकर सेवन से आंन्त्रिक ज्वर (टाईफाईड) में लाभ होता है.

बाल रोग:

1. तृष्णा– समभाग अनारदाना, जीरा तथा नागकेशर के चूर्ण में शर्करा एवं मधु मिलाकर बच्चों को चटाने से तृष्णा का शमन होता है.
2. अतिसार– अनार की ताजी कलियों के साथ छोटी इलायची के बीज और मस्तगी को पीस शर्करा मिलाकर अवलेह तैयार कर चटाने से बच्चों के पुराने अतिसार और पेचिश में विशेष लाभ होता है.
3. बच्चों में सूखा रोग–20–25 ग्राम अनार की कली से पुटपाक– विधि द्वारा प्राप्त रस में थोड़ा दूध मिलाकर नित्य पिलाने से बच्चों के सूखा रोग का निवारण होता है.

दोष: सभी प्रकार के अनार शीत प्रकृति वालों के लिए अहितकर हैं.

अनारदाना: इसका दर्पनाशक जीरा है.

प्रयोज्याग: पुष्प, फल, बीज, पत्र, मूल त्वक, फल त्वक, (छिलका) तथा काण्ड त्वक

मात्रा: चूर्ण 2–4 ग्राम. स्वरस 20–40 मिली. चिकित्सक के परामर्शानुसार. ■

आचार्य बालकृष्ण

ग्राम पंचायत के खर्चे की जानकारी हासिल करें

सूचना का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

अगर आप अपने ग्राम पंचायत में किसी मद पर खर्च से सम्बंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं या अपने पंचायत में संपन्न कार्यों की सूचना चाहते हैं, उन कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार का पता लगाना चाहते हैं, अगर आपको किसी सूचना की दरकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इस योजना से सम्बंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

.....ग्राम पंचायत के संबंध में

निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

1. वर्ष.....के मध्य.....ग्राम पंचायत को किन–किन मदों/याजनाओं के तहत कितनी राशि आंवटित की गई? आवंटन का वर्षवार ब्यौरा दें.

2. उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से सम्बंधित निम्नलिखित विवरण दें:
क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया?
ट. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ठ. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ड. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे सम्बंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.
ड. उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पद बताएं, जिहोंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी.
ढ. कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर/मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष.....के दौरान कार्यों/योजनाओं पर होने वाले खर्चों की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें:
क. कार्य का नाम, जिसके लिए खर्च किया गया
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
ड. कार्य शुरू होने की तिथि
च. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ख.कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे सम्बंधित दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा /रही हूं या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम दिए गए दुर्लभ संबोधन में ओबामा ने कहा कि आईएसआईएस को नष्ट करने की उनकी रणनीति को अमेरिकी सेना के कमांडरों और आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों ने तैयार किया है. इस रणनीति को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल 65 देशों का समर्थन प्राप्त है. कैलिफोर्निया के सन बर्नार्डिनो हमले की जांच में जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि हमलावरों के तार इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कसम खा ली कि वह इस्लामिक स्टेट को नष्ट करके रहेंगे.

कितनी सार्थक होगी यह बातचीत

इस बातचीत को लेकर दोनों देशों की जनता को हैरानी है, साथ ही उत्सुकता और आशंका भी. देखना होगा कि बातचीत कितनी सार्थक होती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का यह अध्याय कोई नया नहीं है. इससे पहले भी समग्र वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह कर चुके हैं.

राजीव रंजन

पिछले दिनों भारत की विदेशमंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान दौरे पर थीं. सुषमा और पाक पीएम नवाज के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बाचतीत हुई. दोनों देशों की जनता में उत्सुकता है कि आखिर यह बातचीत क्यों शुरू हुई और क्या बातचीत हुई. सुषमा ने इस दौरान कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है. सुषमा ने एलान किया कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों पर कॉम्प्रिहेन्सिव बायलेटरल डायलॉग यानी समग्र बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा, जो 2008 के मुंबई हमलों के बाद बंद हो गया था. दोनों देशों के साझा बयान में पाकिस्तान ने मुंबई हमले की सुनवाई में तेजी लाने का भरोसा दिलाया है. इस बार के साझा बयान की खास बात यह रही कि उसमें कश्मीर शब्द का जिक्र नहीं है. इससे पहले सितंबर में एनएसए लेवल की बातचीत के एजेंडे में पाकिस्तान कश्मीर शब्द जोड़ना चाहता था, जिस पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था और बाद में बाचतीत रद्द हो गई थी. साझा बयान में दोनों देशों की ओर से आतंकवाद की निंदा और इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही गई है. कुछ दिनों पहले पेरिस में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की अचानक मुलाक़ात और उसके बाद बैंकाक में दोनों देशों के एनएसए लेवल के अधिकारियों की मुलाकात के बाद जितनी तेज़ी से दोनों देश बातचीत की राह पर आगे बढ़े हैं, उस पर हैरानी जताई जा रही है. भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरे, ये चाहत तो दोनों देशों के नागरिकों की है, लेकिन दशकों से जिस तरह से दोनों देशों के बीच तल्खियों की बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है, उससे दोनों देशों की जनता इस मुलाकात को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है. हालांकि दोनों देशों की जनता कहीं न कहीं इस पहल का स्वागत करती दिख रही है. इन मुलाकातों से जो सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं, उनमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने थक-हारकर पाकिस्तान के साथ बातचीत की मेज़ पर जाने का फ़ैसला किया है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एनएसए लेवल पर बैंकाक में अचानक और गुपचुप बातचीत हुई और वो बातचीत भी तब हुई, जब पहले एनएसए लेवल पर बातचीत से पाकिस्तान पीछे हट गया था. जिस तरह से सबकुछ इतना जल्द हुआ है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये सब पहले से फिक्स था. क्योंकि वार्ता पर दोनों देश राजी हुए हैं, कोई एक देश नहीं. मतलब साफ है कि जिन मुद्दों पर दोनों देशों में गतिरोध था, उन मुद्दों पर अचानक दोनों देशों के बीच रजामंदी यूं ही नहीं है, मतलब पाकिस्तान से इन मुद्दों पर पहले से ही बात हो रही थी या दोनों देश कहीं न कहीं कुछ खास मुद्दों पर समझौता करने की सोच चुके हैं या दोनों में से कोई एक देश किसी विवादित मुद्दे पर पीछे हटने की सोच चुका है. इस बात की पूरी आशंका है कि भारत सियाचिन और सर क्रीक जैसे मुद्दों पर भी समझौता करने पर तैयार हो गया है और उन शर्तों पर वार्ता करने को तैयार हो गया है, जिन पर शायद भारत आज तक रज़ामंद नहीं हुआ. हालांकि जब तक ज़मीन पर कुछ न दिखे, तब तक किसी बात पर भरोसा करना सही नहीं है. सही मायने में देखा जाए तो बातचीत में कुछ सहमतियां लिखित होती हैं और कुछ ज़ुबानी. ये बात और है कि पाकिस्तान जैसा देश जो लिखित में देता है, उसपर भी यूटर्न लेने से बाज नहीं आता. ऐसे में भारत-पाक के रिश्तों में ताज़ा गर्मजोशी कितना रंग लाएगी, यह यक्ष प्रश्न है. अपने दौरे के दौरान सुषमा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पाकिस्तान जाने के भी संकेत दिए. मोदी दक्षेस सम्मेलन में भाग लेने सितंबर, 2016 में पाकिस्तान जा सकते हैं. यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 12 वर्षों में पहली पाकिस्तान यात्रा होगी. मोदी से पहले पाकिस्तान यात्रा पर आने वाले अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो जनवरी 2004 में दक्षेस सम्मेलन में भाग लेने आए थे. अगर मोदी पाकिस्तान की यात्रा करते हैं तो दोनों देशों के संबंधों में मिठास घोलने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी होगी. भारत-पाक ने अपनी साझा वार्ता के दौरान जिन मामलों पर सहमति जताई, उसमें पाकिस्तान ने भारत को मुंबई हमले की सुनवाई को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे तेज करने के लिए कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया है. साथ ही इस साझा बयान में समग्र द्विपक्षीय वार्ता में परस्पर विश्वास बहाली के कदम, सियाचिन, सर क्रीक, वुलर बराज-तुलबुल नौवहन परियोजना, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी लड़ाई, मादक पदार्थों पर अंकुश, मानवीय मुद्दे, जनता के बीच परस्पर आदान-प्रदान तथा धार्मिक पर्यटन के मुद्दे भी शामिल होंगे. दोनों देशों के इस साझा बयान में आतंकवाद की निंदा की गई है और इसका खात्मा करने के लिए सहयोग का संकल्प लिया गया है. सवाल यह है कि इस तरह की बातें दोनों देशों में हमेशा से होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई या अमल के नाम पर नतीजा हमेशा ही सिफर रहा. जरूरत है, जो भी बातें या समझौता हो, उसके प्रति दोनों देशों के बीच ईमानदारी की, उन समझौतों को सख्ती के साथ लागू करने की, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की और छोटी-मोटी बातों या घटनाओं को नजरअंदाज कर विकास के रास्ते पर चलने की. अगर ऐसा होता है तो यकीनन दोनों देश अपनी नई तस्वीर पेश करेंगे, लेकिन ऐसा होगा, अभी से यह कहना मुश्किल है.■

भारत-पाक ने अपनी साझा वार्ता के दौरान जिन मामलों पर सहमति जताई, उसमें पाकिस्तान ने भारत को मुंबई हमले की सुनवाई को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे तेज करने के लिए कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया है. साथ ही इस साझा बयान में समग्र द्विपक्षीय वार्ता में परस्पर विश्वास बहाली के कदम, सियाचिन, सर क्रीक, वुलर बराज-तुलबुल नौवहन परियोजना, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी लड़ाई, मादक पदार्थों पर अंकुश, मानवीय मुद्दे, जनता के बीच परस्पर आदान-प्रदान तथा धार्मिक पर्यटन के मुद्दे भी शामिल होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

जलाने वाला दरिंदा अहमद सुराडजी

इंडोनेशिया में रहने वाला अहमद सुराडजी एक ऐसा शख्स था, जो अपने आप को डायनों का डॉक्टर कहता था, वह इंसान के रूप में एक ऐसा खूनी दरिंदा था, जिसने अपने खतरनाक मानसिकता और अलौकिक शक्तियां हासिल करने के चक्कर में 42 महिलाओं को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया. लोगों के सामने अहमद सुराडजी का भयानक और खतरनाक चेहरा तब सामने आया, जब 2 मई, 1997 को अहमद के घर से सटे गन्नों की फसलों में आधी जली हुई 3 महिलाओं की लाशें मिलीं. इंडोनेशिया की पुलिस द्वारा पूछताछ में सुराडजी ने कबूला कि उसी ने 5 सालों में 16 महिलाओं की हत्याएं की थी. लेकिन बाद में जब पुलिस अधिकारियों ने सुराडजी के घर की तलाशी ली तो उन्हें 25 लापता महिलाओं के कपड़े, घड़ियां और कई समान मिले. आगे की कार्रवाई और पुलिस द्वारा सख्ती से सवाल पूछे जाने पर 48 साल के सुराडजी, जो पेशे से पशुपालन का काम किया करता था, ने यह कबूला कि उसी ने दिव्य ताकतों को हासिल करने के चक्कर में 42 महिलाओं को बड़ी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और उसके इन अपराधों में उसकी तीन पत्नियों और बहनों ने भी उसका पूरा साथ निभाया. अपने आप को मायावी बताने वाले सुराडजी की स्थानीय निवासी इज्जत किया करते थे . स्थानीय निवासियों का यह मानना था कि सुराडजी के पास असाधारण शक्तियां हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी चिकित्सा और सलाह के लिए उसके पास जाया करते थे. पड़ोसियों की मानें तो ज्यादातर महिलाएं सुराडजी को मायावी समझती थीं, इसलिए ज्यादा अमीर बनने, स्वस्थ रहने और पुरुषों को अपने यौन आकर्षण की तरफ आकर्षित करने के लिए वह सुराडजी के पास उपायों के लिए जाया करती थीं. सीरियल किलर सुराडजी अपने मायावी और अंधविश्वास की आड़ में इस तरह की महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था. वह पहले अपने शिकारों से पैसे हड़पता और फिर उन्हें उनकी समस्या का समाधान करने का झांसा देकर उन्हें अपने घर से सटे गन्ने के मैदान में ले जाकर उन्हें बेरहमी से मार देता. वह अपने शिकारों को पहले जादुई रस्मों के अनुसार, कमर तक धरती में दफनाता, उसके बाद बिजली की केबल से बेरहमी से उनका गला घोंट देता. सुराडजी की खतरनाक मानसिकता यहीं खत्म नहीं होती. वह इसके बाद अपने शिकार का थूक पीता और उसके बाद शवों के कपड़े उतार कर शवों को जला देता, ताकि उसकी मायावी शक्तियां और बढ़ सकें. सुराडजी ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपना अपराध कबूलते हुए यह बताया कि 9 साल पहले उसे एक सपना आया था, जिसमें उसके पिता के भूत ने उसे कहा कि उसे रहस्यवादी बनने के लिए 70 महिलाओं को मारकर उनका थूक पीना पड़ेगा. अहमद सुराडजी और उसके पत्नियों और बहनों पर कानूनी कार्रवाई चली. कानूनी कार्रवाई के दौरान सुराडजी ने अपने जुर्म को कबूला. 27 अप्रैल, 1998 में इंडोनेशिया की कोर्ट ने 42 महिलाओं की मौत के आरोपी अहमद सूराडजी को मौत की सजा सुनाई. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

पाक ने रिपोर्टिंग से रोका

अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो की हमलावर तश्फीन मलिक के बारे में रिपोर्टिंग करने पाकिस्तान गए फॉरेन रिपोर्टर्स को पाकिस्तान अथॉरिटी ने मुल्तान के होटल में ही रोक दिया था. सैन बर्नार्डिनो के कम्युनिटी सेंटर पर हुए अंधाधुंध फायरिंग में 14 लोगों की मौत हो गई थी. हमलावर कपल सैयद फारुख और तश्फीन मलिक पाकिस्तानी मूल के बताए गए हैं. हमले में दोनों को ही मार गिराया गया था. फॉरेन रिपोर्टर्स के मुताबिक, पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन पर इस्लामाबाद लौट जाने के लिए दबाव डाला था. वॉशिंग्टन पोस्ट के रिपोर्टर टिम ग्रेग ने यह जानकारी एक ट्वीट में दी है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में बताया कि एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि तश्फीन की कट्टरता का मुल्तान से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं, दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि फॉरेनर्स के लिए यह इलाका बहुत खतरनाक है. मैंने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इजाजत देने के लिए तैयार नहीं हैं. टिम ग्रेग ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि कई विदेशी रिपोर्टर्स को यहां रोक दिया गया है. टिम ने अपने ट्वीट में तश्फीन के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में भी बताया है. टिम ने बताया कि तश्फीन के पिता करोर लाल इसान गांव से हैं.ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार का कट्टरवादी और सांप्रदायिक ताकतों के साथ संबंध रहा है. महिला हमलावर तश्फीन पाकिस्तान में ही जन्मी थी, लेकिन पढ़ाई उसने सऊदी अरब में की. वह 2010 में मुल्तान लौटी और बहाउद्दीन जकारिया यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रैजुएशन किया. इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद तश्फीन की इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से कोई न कोई लिंक रहा था. इसी मस्जिद को पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का गढ़ माना जाता है. हालांकि, तश्फीन जब चार साल की थी तो उसके पिता उस समय सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे. लेकिन सूत्रों के अनुसार, वे इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और लगातार यहां आते रहे हैं.मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तानी नागरिक तश्फीन मलिक और उसके पाकिस्तानी-अमेरिकी पति रिजवान फारुख के पाकिस्तान की लाल मस्जिद के धर्मगुरु मौलाना अब्दुल अजीज से संबंध थे.यूएस इंटेलीजेंस एजेंसियां इस बात पर फोकस कर रही हैं कि कहीं तश्फीन ने सैयद फारुख को फंसाया तो नहीं है.सूत्रों की मानें तो यह माना जा रहा है कि तश्फीन ने यूएस में एंट्री के लिए फारुख से शादी की थी. ■

पाकिस्तान को चाहिए कोहिनूर हीरा

लंबे समय से अब तक भारत में ही कोहिनूर हीरे की मांग चल रही थी, लेकिन अब यह मांग पाकिस्तान में भी उठने लगी है. हाल ही में पाकिस्तान में ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाने की मांग उठी है. पाकिस्तान में एक वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सरकार से कहा जाए कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा पाकिस्तान लाए. वकील जावेद इकबाल जाफरी ने पाकिस्तान की हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में जावेद इकबाल ने आरोप लगाया है कि अंग्रेज महाराज रणजीत सिंह के पोते दलीप सिंह से कोहिनूर छीन कर ब्रिटेन ले गए थे. यह हीरा 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ दिया गया था. महारानी का उस पर कोई हक नहीं है. यह हीरा 105 कैरट का है. इसकी कीमत अरबों रुपए है. यहां के नागरिक इसके असल मालिक हैं. कोर्ट पाकिस्तान सरकार को आदेश दे कि वह ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर हीरा वापस लाए.भारत की हमेशा से यह मांग रही है कि ब्रिटेन कोहिनूर हीरा और लूटे गए अन्य हीरे-जवाहरात तत्काल भारत को लौटाए. भारतवंशी ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने भी नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा से पहले कैमरन सरकार से कहा था कि कोहिनूर भारत को लौटाया जाए. अब यह देखना बाकी है कि कोहिनूर हीरे पर असली हक भारत का है या फिर पाकिस्तान का. ■

आईएसआईएस को खत्म कर के रहूंगा: ओबामा

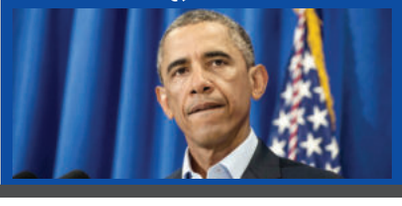

इस्लामिक स्टेट को नष्ट कर देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जो भी आतंकी संगठन अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अमेरिका उसे नष्ट कर देगा. हालांकि ओबामा ने अफगानिस्तान और इराक की तरह व्यापक स्तर पर जमीनी सेनाएं भेजने की संभावनाओं को खारिज कर दिया था. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम दिए गए दुर्लभ संबोधन में ओबामा ने कहा कि आईएसआईएस को नष्ट करने की उनकी रणनीति को अमेरिकी सेना के कमांडरों और आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों ने तैयार किया है. इस रणनीति को अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल 65 देशों का समर्थन प्राप्त है. कैलिफोर्निया के सन बर्नार्डिनो हमले की जांच में जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि हमलावरों के तार इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कसम खा ली कि वह इस्लामिक स्टेट को नष्ट करके रहेंगे. ■

मनुष्य को अपना अंत:करण शुद्ध और पवित्र अवस्था में रखना चाहिए. हमें उस स्त्रोत का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जहां से सभी भाव उत्पन्न होते हैं. वासना से मुक्त होने से अधिक आवश्यक है. वासना भाव से मुक्त होना. कुछ लोग मानसिक रूप से वासनाग्रस्त रहते हैं. उनके खून में वासना भरी है और वे छुप–छुप कर पाप करते हैं. ऐसे लोगों को सद्गुरु को साथ लेकर अपने मन को वासना से मुक्त रखना चाहिए. शरीर को उपवास क्यों कराते हो? मन को उपवास कराओ. मन को उन कारणों से मुक्त करो, जिनके कारण वासना–भवा उतपन्न होता है.

साईं वंदना

अहंकार पर नियंत्रण

मनुष्य को अपना अंत:करण शुद्ध और पवित्र अवस्था में रखना चाहिए. हमें उस स्त्रोत का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जहां से सभी भाव उत्पन्न होते हैं. वासना से मुक्त होने से अधिक आवश्यक है. वासना भाव से मुक्त होना. कुछ लोग मानसिक रूप से वासनाग्रस्त रहते हैं.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

इंसान अपने मैं पर कब और कैसे काबू पा सकता है?

मैं से मेरा और मेरा से तेरा उत्पन्न होता है, जो मैं के ऊपर पूर्ण रूस से काबू पाएगा, वह फिर जन्म नहीं लेगा. कई जन्मों के प्रयास, सत्कर्म तथा गुरु–कृपा से ही आदमी मैं के ऊपर काबू पा सकता है. अहंकार, अभिमान आदि मैं का रूप हैं. अपने अहंकार को समझना चाहिए तथा गुरु से इसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए.

जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते रहने और गुरु के प्रति समर्पण भाव रखने से मैं दूर होता रहता है.

वासना–भाव से मुक्ति

काम–वासनाओं के प्रति मनुष्य का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए?

मनुष्य को अपना अंत:करण शुद्ध और पवित्र अवस्था में रखना चाहिए. हमें उस स्त्रोत का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जहां से सभी भाव उत्पन्न होते हैं. वासना से मुक्त होने से अधिक आवश्यक है. वासना भाव से मुक्त होना. कुछ लोग मानसिक रूप से वासनाग्रस्त रहते हैं. उनके खून में वासना भरी है और वे छुप–छुप कर पाप करते हैं. ऐसे लोगों को सद्गुरु को साथ लेकर अपने मन को वासना से मुक्त रखना चाहिए. शरीर को उपवास क्यों कराते हो? मन को उपवास कराओ. मन को उन कारणों से मुक्त करो, जिनके कारण वासना–भाव उतपन्न होता है.

बाबा का ध्यान करना चाहिए

क्रोध पर नियंत्रण करना कठिन क्यों होता है?

पशु–परंपरा के तीन गुण हैं–क्षुधा, क्रोध एवं काम जो मनुष्य में आए हैं. पशु हिंसा करते हैं, इन्हें मनुष्य की पाशविक प्रवत्तियां कहा जाता है. मनुष्येतर प्राणियों में ये गुण सहजात प्रवृत्ति हैं. मानव पशुओं से एक विकसित प्राणी है, जिसको उच्चतर एवं सूक्ष्मतर बुद्धि प्राप्त हुई है. इसलिए मानव–समाज इन पाशविक प्रवृत्तियों में अपनी बुद्धि लगाकर पशु से भी ज्यादा हिंसात्मक हो जाता है. इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में चलते समय अन्य मानसिक अवगुणों के ऊपर नियंत्रण करना आसान है, पर इन पाशविक गुणों पर नियंत्रण कर पाना ज्यादा कठिन है. संत जन आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए पहले क्षुधा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, फिर क्रोध और अंत में काम–भावना को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वे नारी पुरुष के द्वंद्वात्मक भाव से मुक्त हो जाते हैं. बड़े–बड़े जोगी भी इन आध्यात्मिक विकारों से प्रभावित हो जाते हैं, पर इनसे मुक्त होने के लिए सतत प्रयासशील रहते हैं. विश्वामित्र की आध्यात्मिक साधना में इस उदाहरण को देखा जा सकता है.

क्रोध खुद को और दूसरों को जलाता है. इसके ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं?

क्रोध को जलाना एवं खत्म करना दुर्वासा ऋषि के बस में भी नहीं था. बहुत बड़े–बड़े विद्वान और संत लोग भी इसके शिकार हुए हैं. क्रोध अहंकार से आता है. अहंकार की एक बूंद भी अगर रह जाए, तो क्रोध कभी भी भड़क सकता है. जैसे सब कुछ अच्छा होने के बाद भी और माया का पूरा घर राख करके मिटा देने के बाद भी आग का एक कण अगर कोने में रह गया, तो वह कल भड़क सकता है, वैसे ही हजारों, लाखों अच्छे गुण होने के बाद भी आदमी के अंदर यदि क्रोध का एक कण भी रह जाता है, तो वह किसी न किसी समय भड़क सकता है. जब तक अहंकार की आखिरी बूंद, आखिरी कण तक मिट न जाए, तब तक क्रोध आता ही रहेगा. इसलिए जब आदमी क्रोध से मुक्ति पाने की कोशिश करता है, तो क्रोध आने के पहले क्षण में ही उसे बाबा का ध्यान करना चाहिए कि हे बाबा मेरे क्रोध को दूर करो. उस समय जिस पर क्रोध आ रहा हो, वह मौजूद है, तो उस स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, बहस, नहीं करनी चाहिए. बाबा ने कहा था कि दो आदमी जब लड़ते हैं, तो जो सहन करता है वो मेरा ज्यादा प्यारा होता है. इसी कथन को याद रखा जाए कि बाबा ने यह कहा था, इसलिए मैं यह क्रोध सहन कर लूंगा. यह सोच कर बाहर चले जाना चाहिए. यह करने पर धीरे–धीरे क्रोध पर नियंत्रण बढ़ेगा. यह बहुत शीघ्र नहीं हो सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

धर्म

दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर

जहां तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की

हनुमान जी की पूजा अगर कलयुग में की जाए तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं. ऐसी मान्यता है. हनुमान जी का पूरे देश कई प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है. अगर हम बात राजधानी दिल्ली की करें, तो यहां कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसकी काफी मान्यता है. यहां पर उपस्थित बाल भगवान हनुमान स्वयंभू हैं. यहां प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ तो लगती है, लेकिन मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं की काफी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी स्थापना पांडवों ने की थी. दिल्ली जिसका पूर्व में नाम इंद्रप्रस्थ था, उस पर पांडवों का राज था. पांडवों ने राजधानी में जिन पांच हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी यह मंदिर उनमें से एक है. इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि अपनी दिल्ली यात्रा के समय संत तुलसीदास जी भी इस मंदिर में आए थे और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की थी. यही नहीं यह भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना इसी मंदिर में की थी.

मंदिर से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि एक बार मुगल सम्राट ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाकर चमत्कार दिखाने को कहा, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के आशीर्वाद से जब चमत्कार कर दिखाया, तो सम्राट ने प्रसन्न होकर मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा सहित किरीट कलश लगवाया. यही कारण रहा कि विभिन्न आक्रमणों के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस्लामी चंद्रमा का मान रखा और कभी भी इस मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाई.

यहां गर्भ गृह की दीवार व हनुमान जी सहित अन्य देवता दक्षिण की ओर देखते हुए मिलते हैं. हनुमान जयंती के दिन यहां भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं. इस दिन मंदिर प्रशासन की ओर से झांकी भी निकाली जाती है. ■

प्रेरक कहानी

कठिन परिश्रम

वरदराज नाम का एक विद्यार्थी था. विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे. उसके गुरुजन भी उससे नाराज रहते थे, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत कमजोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था. कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने से कभी नहीं चूकते थे. उसका पढ़ने जाना तो मानो एक सजा के समान हो गया था, वह जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उस पर हंसने लगते, कोई उसे महामूर्ख तो कोई उसे बैलों का राजा कहता, यहां तक की कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते. इन सबसे परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया.

अब वह दिन भर इधर–उधर भटकता और अपना समय बर्बाद करता. एक दिन इसी तरह कहीं से जा रहा था, घूमते–घूमते उसे प्यास लग गई. वह इधर–उधर पानी खोजने लगा. अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया. वह वहां गया और कुएं से पानी खींच कर अपनी प्यास बुझाई. अब वह काफी थक चुका था, इसलिए पानी पीने के बाद वहीं बैठ गया. तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़े उस निशान पर गई जिस पर बार–बार कुएं से पानी खींचने की वजह से रस्सी का निशान बन गया था. वह मन ही मन सोचने लगा कि जब बार–बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है, तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है. उसने यह बात मन में बैठा ली और फिर से विद्यालय जाना शुरू कर दिया. कुछ दिन तक लोग उसी तरह उसका मजाक उड़ाते रहे पर धीरे–धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग करना शुरू कर दिया. उसने मन लगाकर अथक परिश्रम किया. कुछ सालों बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की.

आशय यह है कि हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं, बस ज़रुरत है कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने की. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

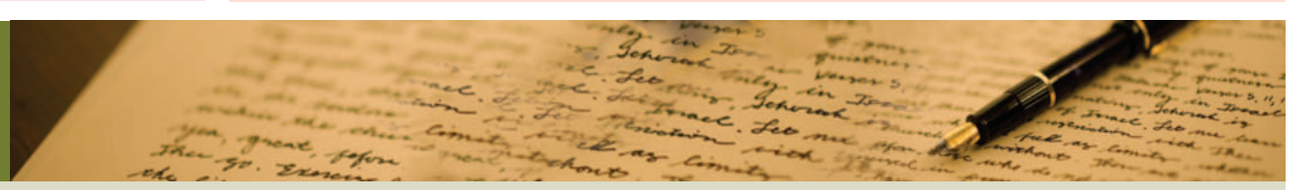

सूचना नहीं देते अधिकारी

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. मैंने कई बार सूचना के अधिकार का उपयोग किया है, लेकिन बिहार में सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं दी जाती है और बिहार में व्याप्त कुव्यवस्था, अफसर शाही एवं सूचना आयोग के दयालूपन के कारण सूचना नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों को अभयदान भी दे दिया जाता है, जिसके कारण सूचना का कानून बिहार में सफलता पाने और अपने उद्देश्य को पूरा करने विफल साबित हो रहा है. इस कानून का अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वे वर्षों तक सूचना नहीं देते हैं. कुछ समय बाद आयोग बिना सूचना उपलब्ध कराए ही केस को बंद कर देता है.

बिहार में खासकर पूर्णियां जिले में पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत प्रत्येक पंचायत में करोड़ों की राशि खर्च करने के बावजूद भी धरातल पर विकास तो दूर ग्रामीणों को मूलभूत सविधा भी नहीं मिल पाई है. प्रत्येक पंचायत में प्रतिवर्ष चार ग्राम सभा करना अनिवार्य है. ग्राम सभा में उपलब्ध राशि किस मद में खर्च की जाएगी, इसका प्रस्ताव होने के बाद ही योजनाओं का सर्वप्रथम बोर्ड लगाकर योजनाएं चालू की जानी हैं, परंतु ग्राम सभा होती ही नहीं है. इसका मुख्य कारण पंचायती राज्य पदाधिकारियों, निर्वाचित मुखिया एवं पंचायत सचिव के साठगांठ एवं स्वार्थपूर्ति हेतु ग्रामसभा का आयोजन बंद कर दिया गया है. मैंने सूचना के अधिकार के तहत भवानीपुर प्रखंड के लोकसूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी से भवानीपुर पश्चिम पंचायत में वर्षों में कितनी ग्राम सभा हुई. पर्यवेक्षक उसका पद और नाम सहित सूचना मांगी थी. उन्होंने निम्न सूचना इस प्रकार दी है.

वर्ष 2007 में कोई आम सभा नहीं हुई.
वर्ष 2008 में एक आम सभा हुई.
वर्ष 2009 में कोई आम सभा नहीं हुई.
वर्ष 2010–2011 में एक–एक आम सभा होने की सूचना दी है.

6 वर्ष में मात्र चार ग्राम सभा होना यह साबित करता है कि पंचायती राज्य व्यवस्था पॉकेट संस्था बनकर रह गई है. मेरा निजी तौर पर मानना है कि आम जनता को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुखिया पंचायत सचिव संबंधित अधिकारी जरूर करोड़पति बन गए.

विडंबना यह है कि लोकसूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आयोग के वाद संख्या 65295/11–12 के आदेश के आलोक में एक वर्ष के उपरांत आधी अधूरी ही सूचना दी है. मैंने एक शिकायत पत्र प्रखंड से लेकर जिला राज्य एवं केंद्र के विभिन्न अधिकारियों को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा है.

– मो. असलम, *भवानीपुर(पुर्णियां), बिहार.*

किसान पर दोहरी मार

उत्तर प्रदेश सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से किसान दुखी है. उसने चीनी मिलों को जो गन्ना पिछले वर्ष बेचा था, उसका पूरा भुगतान उसे अभी तक नहीं मिल पाया है. सरकार इस वर्ष के लिए गन्ना मूल्य का निर्धारण अभी तक नहीं कर पाई है. मिल मालिक तो किसान को 200 रुपये मूल्य भी देने को राजी नहीं हैं. प्रकृति की मार से वह पहले से ही करा रहा है. पर्याप्त वर्षा न होने के कारण किसान को अपनी धान की फसल की कई बार सिंचाई करनी पड़ी. इससे उसकी लागत काफी बढ़ गई. वह जब क्रय केंद्रों पर अपनी उपज को लेकर पहुंचता है, तो उसे ज्यादा नमी का बहाना बनाकर क्रय केंद्र से भगा दिया जाता है. विवश होकर उसे अपनी उपज औने–पौने दामों में बिचौलियों के हाथ बेचनी पड़ती है. खेत खाली करने के लिए वह अपना पेड़ी गन्ना बेचना चाहता है, तो उसे गुड़ बनाने वाले 120 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक मूल्य देने को राजी नहीं है. किसानों की इन समस्याओं की अनदेखी आखिर सरकारें कब करती रहेगी?

– राज किशोर पाण्डेय(प्रहरी)
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

पर्यटल स्थलों का प्रचार करें सरकार

जब तोप मुकाबिल हो–काशी में देव दीपावली देखने का सौभाग्य(07 दिसंबर–13 दिसंबर, 2015) पढ़ा. काफी प्रभावित किया है. संतोष भारतीय ने सही कहा कि अगर सरकार इस आयोजन को और गंभीरता से ले, तो पर्यटन बनारस की आर्थिक स्थिति में कमाल का काम कर सकता है. बनारस ही नहीं केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वह देश के हर एक पर्यटन स्थल का प्रचार–प्रसार करे, जिससे देश और विदेश के लोगों को भारत में स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में पता चले. भारत में कितने ऐसे सुंदर और प्रकृति को अपने में समेटे हुए पर्यटन स्थल हैं, जिसके बारे में देश के लोगों को ही नहीं पता है. दक्षिण भारत, उत्तर भारत एवं पुर्वोत्तर के कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जिनके बारे में देश के लोगों को ही जानकारी नहीं होगी.

–इन्द्रजीत सिंह,
बक्सर, बिहार.

सरकार वादा निभाए

कवर स्टोरी–मोदी सरकार के 18 महीने, देश की जनता निराश है(07 दिसंबर–13 दिसंबर, 2015)पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मनीष कुमार ने बिल्कुल सही कहा है कि देश की जनता ने बड़ी आशा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुना था. देश की जनता जिस अच्छे दिन की आश की थी वो आज तक नहीं आए. महंगाई पहले से कम होने के बजाय बढ़ गई है. मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल को देखें, तो उससे न जनता ही खुश है और न ही उद्योगपति. मोदी सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई है, उसे कम से कम उनको तो पूरा करना चाहिए.

– रमेश मिश्रा, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

उपस्थिति से बढ़ेगी साझेदारी

अनंत विजय

जब से कॉफी हाउस संस्कृति बंद हुई है तब से साहित्यिक समाचार ज्यादातर सोशल मीडिया पर ही नजर आते हैं. साहित्यक गॉसिप से लेकर विवाद तक, गंभीर टिप्पणियों से लेकर फूहड़ कमेंट तक, साहित्यक समाचार से लेकर साहित्येतर कानाफूसी तक सब–कुछ सोशल मीडिया से सामने आने लगा है. कॉफी हाउस में तो बोलकर निकल जाने की सहूलियत थी और उसका उतना विस्तार भी नहीं था लेकिन जितना कि सोशल मीडिया है. यहां आप पोस्ट कर निकल नहीं सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक और सहूलियत है कि जैसे ही आपकी पोस्ट को कोई लाइक करता है या उसपर अपनी टिप्पणी देता है तो वो टाइम लाइन पर सबसे उपर आ जाता है. इसका नतीजा यह होता है कि किसी भी तरह की खबर लंबे समय तक सोशल मीडिया पर बनी रहती है. बहुधा तो ऐसा होता है कि साल दो साल पहले की पोस्ट भी अगर किसी ने लाइक कर दी तो वो फौरन टाइम लाइन पर आ जाता है. इसके फायदे और नुकसान दोनो हैं. फायदा ये कि सकारात्मक खबरें वहां आती जाती रहती हैं और नुकसान ये कि आरोपों की शक्ल में लिखे गए पोस्ट की भी उपस्थिति बनी रहती है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर देखकर मैं चौंका. ये खबर थी पटना के लेखक रत्नेश्वर से जुड़ी. रत्नेश्वर ने अपनी वॉल पर अपनी किताब के पटना में होनेवाले लोकार्पण समारोह का कार्ड लगाया था. यह कोई अहम बात नहीं थी, हर किताब के लोकार्पण का कार्ड लोग फेसबुक आदि पर शेयर करते ही ही हैं. अब तो ये रिवाज भी हो चला है. लेकिन उस कार्ड पर प्रकाशित एक सूचना ने मुझे चौंकाया. मैजिक इन यू नाम की इस किताब की बीस हजार प्रतियों की प्री बुकिंग होने का दावा करते हुए प्रचारित किया जा रहा है. चौंका इस वजह से कि अंग्रेजी में लिखी इस किताब को छापा है किसी हिंदी के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन ने. इस लिहाज से यह एक बड़ी घटना है कि किसी किताब के लोकार्पित होने के पहले ही बीस हजार प्रतियों की बुकिंग हो जाना. भारतीय प्रकाशन जगत के लिहाज से यह एक अहम घटना है. इसके पहले चेतन भगत की किताब हॉफ गर्ल फ्रेंड की साल लाख प्रतियों की एडवांस बुकिंग हुई थी परंतु वो बुकिंग एक ऑनलाइन कारोबार करनेवाली वेबसाइट ने की थी जिसके पास उक्त किताब को एक तय समय सीमा तक बेचने का एक्सक्लूसिव अधिकार था. अंग्रेजी के कई प्रकाशकों और लेखकों से मैंने इस बारे में बात कर यह समझाने की कोशिश की कि प्रकाशन जगत के लिहाज से यह कितनी बड़ी घटना है. प्रकाशकों और लेखकों, दोनों ने बताया कि यह घटना महत्वपूर्ण है जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए. दूसरी जिस बात ने मुझे चौंकाया वह ये कि रत्नेश्वर की यह किताब मैजिक इन यू साहित्यक कृति नहीं हैं बल्कि ये किताब आपके अंदर की ताकत को पहचानने और उसको उजागर करने की बात करता है यानि कि यह व्यक्तित्व विकास की किताब है. इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किताब छपने और बाजार में आने के पहले ही उसकी बीस हजार प्रतियों की बुकिंग कैसे हो गई?

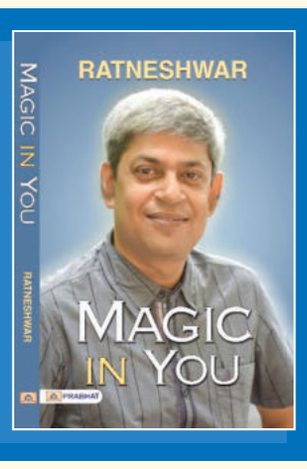

भारत में जहां किताबों की बिक्री को लेकर रोना गाना–मचा रहता है वैसे परिदृश्य में सुदूर बिहार के एक लेखक की लिखी किताब छपने के पहले इतनी लोकप्रिय हो जाए तो आश्चर्य भी होता है और इस बात का संतोष भी होता है कि भारत में किताबों की बिक्री का बड़ा बाजार है.

भारत में जहां किताबों की बिक्री को लेकर रोना–गाना मचा रहता है वैसे परिदृश्य में सुदूर बिहार के एक लेखक की लिखी किताब छपने के पहले इतनी लोकप्रिय हो जाए तो आश्चर्य भी होता है और इस बात का संतोष भी होता है कि भारत में किताबों की बिक्री का बड़ा बाजार है. रत्नेश्वर पहले हिंदी में लिखते रहे हैं. उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. पिछले साल नेशनल बुक ट्रस्ट से आई उनकी किताब मीडिया लाइव के भी कई संस्करण हो चुके हैं. एक जमाने में कहानियां लिखने वाले रत्नेश्वर कालांतर में नॉन फिक्शन की ओर मुड़े. कुछ दिनों पहले एक साक्षात्कार में रत्नेश्वर ने कहा था कि सैद्धांतिक साहित्य को पाठक पूरी तरह नकार रहे हैं क्योंकि उनमें कहानी से ज्यादा विचार प्रबल होते हैं. उन्होंने माना था कि आजकल मोटे–मोटे उपन्यासों का लेखन भी खूब हो रहा है, पर अधिकांश उपन्यास विवरणात्मक शैली में लिखे जा रहे है वो कहते हैं कि उपन्यास या कहानी किस्सागोई की चासनी में ऐसे लिपटे हों कि पाठक अंत तक बहता चला जाय, आज के अधिकांश उपन्यासों और कहानियों के विवरण शैली को पाठक झेल ही नहीं पाते और उनमें ऊब पैदा होती है. मतलब साफ़ है – शायद आज के साहित्यकार का टारगेट आलोचक और पुरस्कार होते हैं! जो साहित्य उनके लिए लिखा नहीं गया, ऐसे में भला पाठक आपको क्यों तरजीह देने लगे? वो इस बात पर भी चिंता प्रकट करते हैं कि हिन्दी पढ़ने–जानने वालों की संख्या करीब साठ सत्तर करोड़ है तो हमारे संस्करण तीन चार सौ के क्यों होते हैं? वो सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा लक्ष्य उनमें से कम–से–कम सात लाख हिंदी प्रेमियों को पाठक बनाने का नहीं होना चाहिए? उनका मानना है कि लेखक का दायित्व अच्छा साहित्य लिखना तो है ही उसे पाठकों तक पहुंचाना भी है. अभी हाल ही में रत्नेश्वर ने अपना पहला उपन्यास रेखना मेरी जान लिखकर खत्म किया है और उनका यह उपन्यास भी जल्द ही हिंदी और अंग्रेजी में छपकर बाजार में आने वाला है. देखना यह होगा कि उनके इस उपन्यास को पाठक कैसे लेते हैं. ग्लोबल वार्मिंग को केंद्र में रखकर लिखी गई इस किताब को लेकर प्रकाशक उत्साहित हैं. यह बात समझ से परे है कि किताबों के पाठकों की कमी का रोना क्यों रोया जाता है? क्यों इस बात को प्रचारित किया जाता है कि हिंदी का प्रकाशन व्यवसाय तो सरकारी खरीद की वैसाखी थामे चल रहा है, वर्ना तो ये कब का दम तोड़ चुका होता. यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी में किताबों की प्री बुकिंग हुई है लेकिन हिंदी की हालत भी बेहतर है वहां भी यह हो सकता है. दरअसल इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि हिंदी में पाठकों की कमी है. इसको निगेट करने की जरूरत है.

अभी हाल ही में मार्केट सर्वे करनेवाली एक कंपनी नीलसन इंडिया की बुक मार्केट रिपोर्ट 2015 जारी की गई है. नील्सन इंडिया की इस रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो प्रकाशन जगत के लिए आंखें खोलने वाले हैं. सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा किताबों का बाजार है. उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में किताबों का बाजार इक्कीस हजार छह सौ करोड़ रुपये का है. नील्सन के अनुमान के मुताबिक किताबों का ये बाजार सालाना करीब साढ़े उन्नीस फीसदी की दर से बढ़ेगा और 2020 तक इस बाजार का आकार तेहत्तर हजार नौ सौ करोड़ तक पहुंच जाएगा. नील्सन के इस अनुमान का आधार भारत की साक्षरता दर है. उसके मुताबिक भारत की साक्षरता दर 2020 तक नब्बे फीसदी हो जाएगी जो इस वक्त चौहत्तर फीसदी है. इस रिपोर्ट में और भी दिलचस्प आंकड़े हैं. इसके मुताबिक भारत में अंग्रेजी किताबों का बाजार पचपन फीसदी है और अंग्रेजी किताबों का विश्व में ये दूसरा सबसे बड़ा बाजार है.

किताबों के बाजार में हिंदी किताबों का शेयर पैंतीस फीसदी है और अन्य भारतीय भाषाओं की किताबों की हिस्सेदारी मात्र दस फीसदी है. नील्सन के इन आंकड़ों में अकादमिक, प्रोफेशनल, स्कूल टेक्स्ट बुक, के अलावा रचनात्मक साहित्य की किताबें भी शामिल हैं. इतना बड़ा बाजार होने के बावजूद किताबों की बिक्री नहीं होने पर छाती कूटना उचित नहीं है. जरूरत इस बात की है कि किस तरह से किताबों के बढ़ते बाजार में अपनी उपस्थिति और हिस्सेदारी को मजबूत किया जाए. नील्सन की रिपोर्ट के मुताबिक किताबों के बाजार के फैलाव में कई सारी दिक्कतें हैं. इन दिक्कतों में सबसे बड़ी बाधा तो किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन श्रृंखला को लेकर है. किताबों के वितरण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होने और पुस्तक विक्रेताओं को लंबे समय तक क्रेडिट देने से इस कारोबार में कैशफ्लो कम होता है इस वजह से पूंजीगत समस्या खड़ी हो जाती है. इस अलावा किताबों के कारोबार में जो सबसे बड़ी समस्या है वह ये कि यहां पाइरेसी बहुत ज्यादा होती है. भारत उतना विशाल देश है कि पाइरेसी को रोक पाना लगभग असंभव है. इसका बेहतरीन उदाहरण तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा है. इसके प्रकाशन का अधिकार दिल्ली के वाणी प्रकाशन के पास है लेकिन जाने कहां कहां और किन–किन भाषाओं में यह किताब प्रकाशित हुई है वो न तो लेखिका को मालूम है और न ही प्रकाशक को. पाइरेसी रोकने के लिए जो कानून हैं वह उतने सख्त नहीं हैं लिहाजा इसको मजबूत करने की जरूरत है. अंत में मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां कहना चाहूंगा– कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. किताबें बिकेंगी कोशिश तो हों. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कविता

सुशील कुमार

मुठभेड़

कंधे पर दुनाली रखते हुए
कुछ तो सोचा होगा तुमने
मां के बुझे हुए चेहरे को देखकर
पिता की पथराई आंखें देखकर
भाई के शरीर पर उभरी हड्डियों को देखकर
अत्याचारियों की हंसी देखकर
दुपट्टे को गर्दन में बांधकर झूल जाने वाली
बहन को देखकर

तुम्हारी आंखें भी तो पत्थर की नहीं
रही होंगी
उनमें तैरती होगी आशा की चमक कभी

लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं थे
दूसरों के तुम्हारे लिए तय किए गए नियम
तुम्हें खाली पेट मरना मंजूर नहीं था
इसलिए तुम आज
सरकारी फाइलों में दफन
महज़ एक मुठभेड़ हो

कैसे जान पाएगा अब कोई
क्या सोचा होगा तुमने
अपने कंधे पर दुनाली रखते हुए?

मृत्यु की तरह जीवन

सब कुछ है यहां
सब के लिए
धूप, हवा, पानी,
भोजन, वस्त्र, घर
मुस्कराहटें और कहकहे

बस, मृत्यु की तरह जीवन
बराबरी से बांटा नहीं गया

feedback@chauthiduniya.com

असहिष्णुता साहित्यिक नहीं राजनीतिक है

ऋतुराज

असहिष्णुता यानि असहनशीलता. जिसे देखो वो इस पर बात कर रहा है. चौराहों की चौपालों पर चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग हों या संकरी गलियों में बीड़ी सुलगाते लोग ,एयरकडीशन रूम में न्यूज़ चैनल देखता हुआ परिवार हो या परम सामाजिकता का नारा बुलंद करने वाले कथित बुद्धिजीवियों की जमात, सभी असहिष्णुता नामक शब्द के पीछे पड़ गए हैं. इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी इस शब्द का उच्चारण करने में सौ बार जुबान लड़खड़ाती है लेकिन फिर भी वो संकोच नहीं करते क्योकि अगर पेट का सवाल हो और सामने मीठे पकवान हो तो इंसान हाजमा ख़राब होने की परवाह नहीं करता.

कोई राजनीति चमका रहा है, कोई ज्ञान प्रदर्शित कर रहा है, कोई समाज का ठेकेदार बन रहा है और कोई अल्पसंख्यकों का मसीहा बन कर उभरा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच में भारत में असहिष्णुता बढ़ गयी है? क्या सच में राम और रहीम में इतनी नफरत पैदा हो गयी है जिसे मिटाने की कीमत केवल एक दूसरे का रक्त है? सवाल एक है लेकिन उनके जवाबों में बहुत विरोधाभास है.

कलबुर्गी की हत्या का उदहारण देकर कई साहित्यकार और फिल्मकार असहिष्णुता के नाम पर अपने पुरस्कारो को वापस कर चुके हैं. कुछ दिन पहले आमिर खान ने कहा कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है. वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करतीं. इससे पहले शाहरुख़ भी भारत को असहिष्णु बता चुके हैं. लगातार भारत के किसी न किसी कोने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं. जो भारत को असहिष्णु साबित करने की कोशिश करती हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है.

ऐसा कहा जाता है कि रामराज्य में भी लोग इसी तरह असहिष्णुता का राग अलापते रहते थे, जबकि उन्होंने अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखने का प्रयास किया. दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य में काहु न व्यापा. सीता का त्याग राम के जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी थी. प्रजा में आशंका केस्वर प्रबल न हो इसलिए उन्होंने अपनी गर्भवती महारानी का त्याग कर दिया. एक कपड़े धोने वाले धोबी का वेष बनाकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकले एक नवोदित राजा के सामने एक बड़ी चुनौती थी. अयोध्या में कोई भी पराया नहीं था. उनके सब अपने थे, फिर भी उन्हें प्रजा की असहमति का डर था यानि असहिष्णुता उस समय भी राजाओं को कटघरे में खड़ा करती थी, जबकि उस समय राजतंत्र था. राजा कुछ भी कर सकता था. परन्तु आज प्रजातंत्र है सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिल जुलकर रहते हैं.अल्प विरोधों, मतभेदों के बीच वे सामजस्य से आगे बढ़ रहे हैं देश विकास की मुख्यधारा में गतिमान है. भारत ने इमरजेंसी का

समय भी देखा है जिसमे सहिष्णुता का प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से दमन हुआ लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया को भी नियंत्रित होना पड़ा. यहां तक कि उन्हें विरोध स्वरूप अखबारों के संपादकीय कॉलम भी खाली छोड़ने पड़े.

आज इमरजेंसी का युग नहीं है लेकिन फिर से देश भर में असहिष्णुता पर बात हो रही है. कुछ लोगों को लगता है कि यह है, लेकिन अधिकतर इससे असहमत हैं. वे कहते हैं कि यह नहीं है. साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाना हो, फिल्मकारों का सम्मान लौटाना हो या शाहरुख़ और आमिर जैसे प्रजाजनों का यह कहना हो कि देश में माहौल असहिष्णु है पर अब तक मोदी सरकार की ओर से सहिष्णुता पर कोई संतुष्ट करने वाला बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है. न ही असहिष्णुता से पीड़ित लोगो की समस्याओं को सुनने के लिए कोई बुलावा ही भेजा गया है यहां मुद्दा केवल इतना ही नहीं है कि देश में असहिष्णुता है या नहीं है बल्कि मुद्दा यह भी है कि अगर आवाजें उठी हैं तो उस पर शासन का क्या रुख है, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए वो क्या कदम उठा रही है? सरकार को इसका हल निकालना ही पड़ेगा क्योकि प्रजातंत्र में अगर एक भी आवाज अनुत्तरित रह गयी तो सहिष्णुता की स्थापना संभव ही नहीं है.

मै यहां विपक्षी दलों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका मकसद सत्तारूढ़ पार्टी की बातों का हर हाल में विरोध करना होता है. रामराज्य में भी वह दिन आया था जब सीता सहित त्यागे गए पुत्रों को एक दिन उनका अधिकार मिल जाता है. राजा राम उन्हें स्वीकार करते हैं. जनता में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता रह जाता है तो केवल राम और सीता के लिए आदरभाव और अपने लिए प्रायश्चित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भी सहिष्णुता और असहिष्णुता के मुद्दे पर कुछ ऐसा ही दृश्य है. जहां इनके पक्ष और विपक्ष में कई आवाजें उठ रही हैं वहीं इनके सामने एक चुनौती यह भी है कि समाज में साम्य को कैसे स्थापित किया जाये लोग उनकी कार्य करने की क्षमता पर प्रश्न नहीं उठा रहे, लोग उनकी लोकप्रियता पर भी प्रश्न नहीं उठा रहे हो सिर्फ इतना रहा है कि लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी में सहजता का अनुभव नहीं कर रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है जिसका प्रयोग करने में लोग आज डर रहे हैं जब वरदान ही अभिशाप बन जाए तो सरकार की मंशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है. ■

feedback@chauthiduniya.com

खाना पीना

झटपट तैयार होता है टमाटर राइस

अगर आप अकेले रहते हैं और खाना बनाने का मन नहीं है या झटपट कुछ पकाने-खाने का मन है तो टमाटर राइस की रेसिपी आपको परफेक्ट लगेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि:

आवश्यक सामग्री- एक कप बासमती चावल, 4 बड़े टमाटर, दो बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच सांभर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सरसों के दाने, चुटकी भर हींग, नमक स्वादानुसार

विधि - बासमती चावल को 20 मिनट तक भीगोकर रखें. फिर पानी निकालकर 2 कप उसमें गर्म पानी डालें और अच्छे से पका लें. अब चार टमाटर को पीसकर उसका जूस निकाल लें. फिर कढ़ाई में दो चम्मच तेल गर्म करें और उसमें सरसों, हींग और करी पत्ते का तड़का दें. अब इसमें प्याज डालें और थोड़ा चलाएं. फिर हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और थोड़ा सा भूनें. इसके बाद टमाटर का जूस, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सांभर मसाला और नमक मिलाएं और अच्छे से तब तक भूनें, जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे. अब टमाटर की इस ग्रेवी में जरूरत के मुताबिक पके चावल मिलाएं. इसे धनिया पत्ती के साथ गार्निश करें. रायते के साथ सर्व करें. ■

फैशन

मुंबई में ब्लेंडर प्राइड फैशन टूर-2015 के दौरान फैशन डिजाइनर के साथ परिधानों का प्रदर्शन करती हुईं मॉडल्स.

सैर-सपाटा

विरासत की याद दिलाता है कुंभलगढ़

अगर आपको अपने इतिहास और विरासत को जानने की ललक है तो आपके लिए राजस्थान का कुंभलगढ़ बेस्ट डेस्टिनेशन है, जो न सिर्फ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, बल्कि अपने शानदार इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और रेगिस्तान के लिए भी जाना जाता है. राजसमंद जिले में अरावली पहाड़ियों पर बने कुंभलगढ़ के विशाल किला को राजस्थान के सबसे दुर्गम पहाड़ी किला के रूप में जाना जाता है. जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है इस किला का निमार्ण राणा कुंभा ने पन्द्रहवीं शताब्दी में करवाया था. इस किले के एक ओर मारवाड़ और दूसरी ओर मेवाड़ की सीमाएं लगती थीं. कुंभलगढ़, उदयपुर से मात्र 80 किमी की दूरी पर है, लेकिन कुछ घुमावदार पहाड़ी रास्तों की वजह से यहां पहुंचने में आपको करीब ढाई घंटे का समय लग जायेगा. पर यकीन मानिये रास्ते में दिखती हरियाली, नदी आपके मन को एक भव्य शांति दे जाती है. इस किले की खास पहचान है इसकी भव्य बाहरी दीवारें. ऐसा माना जाता है कि चीन की दीवार के बाद लंबाई की दृष्टि से 38 किमी तक लगातार फैलाव लिए हुई इस किले की दीवारों की गणना होती है. कुंभलगढ़ किले की बाहरी दीवारें 15 फीट चौड़ी हैं और किसी समय इसमें सैकड़ों जैन व हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर के अवशेष ही रह गए हैं. इनमें से वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, गणेश और चारभुजा मंदिर प्रमुख हैं. राणा कुंभा के महल के रास्ते में बादल महल आता है, जिसके तीन द्वारों को पार कर ही राणा कुंभा का महल आता है. हालांकि महल तो अब बिल्कुल खंडहर हो गया है, लेकिन उसकी बनावट देखकर महाराणा की सादगी का अंदाजा लगता है. राणा कुंभा के महल से अगर थोड़ा ऊपर जाएं तो आपको वह कक्ष देखने को मिलेगा, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था. पूरे किले का सबसे आलीशान महल काफी ऊंचाई पर स्थित है और इसीलिए इसे बादल महल

के नाम से जाना जाता है. महल के कमरों की दीवारों और छत पर की गई नक्काशियां मन को लुभाती हैं. कुंभलगढ़ से 48 किमी दूर ये प्रसिद्ध घाटी महाराणा प्रताप के अद्भुत शौर्य व उनके वफादार घोड़ा चेतक की बहादुरी की याद दिलाती है. यहां पर राणा प्रताप के सम्मान में एक स्मारक और संग्रहालय भी बनाया गया है. इस संग्रहालय में पूरा इतिहास दिखता है. कुंभलगढ़ से हल्दीघाटी के रास्ते में नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है. कुंभलगढ़ से इसकी दूरी करीब 64 किमी है. ये मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित है, जिसे यहां श्रीनाथजी के नाम से जाना जाता है.

कब जाएं– यहां लगभग सभी मौसम में जाया जा सकता है.

कैसे पहुंचें– उदयपुर रेल, सड़क व हवाई मार्ग से पूरे देश से जुड़ा है. उदयपुर से कुंभलगढ़ के लिए बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है. ■

करियर

राफ्टिंग में बनाएं एडवेंचरस करियर

एडवेंचर पंसद है, तो आप अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर नदियों की लहरों पर राफ्टिंग कर सकते हैं. नदी के तेज बहाव और उछलती-कूदती लहरों पर सवारी करने का अलग ही आनंद है. अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भारत आया यह रोमांचक खेल अब भारत में भी युवाओं को लुभाने लगा है. शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत युवाओं के लिए राफ्टिंग आज के दौर में भारत में उज्ज्वल करियर के रूप में उभरा है. इस फील्ड में करियर बेहतरीन तो है ही, संभावनाओं की भी कोई कमी नहीं है. साहस और जुनून इस फील्ड के लिए होना जरूरी है.

अगर आप राफ्टिंग गाइड बन कर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे कई संस्थान हैं, जहां राफ्टिंग का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है. आवेदनकर्ता की शारीरिक जांच की जाती है. आपके अंदर छिपे साहस को परखने के लिए राफ्टिंग गाइड के साथ खतरनाक राफ्टिंग ट्रैक पर भेजा जाता है. इसमें सफल होने पर उसे प्रशिक्षण के लिए चुन लिया जाता है. ट्रेनिंग के दौरान राफ्टिंग उपकरणों के प्रयोग करने के तरीकों को समझाया जाता है. चूंकि बिना उचित जानकारी के यह शौक खतरनाक हो सकता है, इसलिए नदी के बहाव, गहराई, ढलान के साथ उसके खतरों की भी विस्तार से जानकारी दी जाती है. साथ ही ओवरनाइट रिवर टिप भी दी जाती है. राफ्टिंग गाइड बनकर आप शुरूमें 10 से 15 हजार रुपये तक कमा सकते हैं.

जॉब संभवानाएं

राफ्टिंग का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप चाहें तो स्वयं का राफ्टिंग स्कूल खोल सकते हैं. गाइड बनकर पर्यटकों को राफ्टिंग का रोमांचक सफर कराकर करियर बना सकते हैं.

प्रमुख संस्थान:

हिमालयन रिवर रनर्स, नई दिल्ली.
इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, दिल्ली ■

अपना कंप्यूटर खुद फॉर्मेट करें

श्याम सुन्दर प्रसाद

क्या आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है या कंप्यूटर में वायरस आ गये हैं? क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा है या बार-बार हैंग हो रहा है? क्या कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है और आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप किसी हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाने की सोचते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप कुछ आसान से स्टेप को फॉलो कर खुद से अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं.

कंप्यूटर फॉर्मेट करने से पहले

कंप्यूटर को फॉर्मेट करने से जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें मौजूद हर तरह का डेटा डिलीट हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने आवश्यक डेटा का बैकअप बना लें. कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास विंडोज एक्सपी/ विंडोज 7 या उस ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल सीडी या डीवीडी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फॉर्मेट करते हैं तो कंप्यूटर में मौजूद सभी फाइल्स डिलीट हो जाते हैं. ऐसे में फिर से नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, इसलिए बूटेबल सीडी या फ़्लैश ड्राइव में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज फाइल रखते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. इसके साथ पेरीफेरल डिवाइस के ड्राइवर की सीडी, डीवीडी या बैकअप होनी चाहिए. साथ ही वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसका आप प्रयोग करते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, पीडीएफ रीडर, मीडिया प्लेयर इत्यादि.

फॉर्मेट करने की प्रक्रिया

स्टेप 1 : अपने कंप्यूटर की सीडी/ डीवीडी ड्राइव मे विंडो 7/ विंडो एक्सपी या जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसकी बुटेबल सीडी/डीवीडी डाल दें और अपने कंप्यूटर को री-स्टार्ट करें और जैसे ही वह स्टार्ट हो रहा हो की-बोर्ड से एफ 12 या डीलीट बटन को दबाएं. इससे बूट ऑर्डर मेन्यू खुलेगा. अगर आपके पास बूटेबल सीडी हैं तो सीडीवाला ऑप्शन चुनें या अगर आपके पास बूटेबल फ़्लैश ड्राइव हैं तो णडइ वाला ऑप्शन चुनें, और सेटिंग को सेव करने के लिए एफ 10 बटन को दबायें और फिर यस ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐसा करने से आपका कंप्यूटर री-स्टार्ट होगा और जब स्टार्ट होगा तो आपका सिस्टम सीधे डीवीडी रोम या फ़्लैश ड्राइव को रीड करेगा.

स्टेप 2 : सिस्टम जैसे ही री-स्टार्ट होगा. एक मैसेज दिखेगा प्रेस एनी की. अब आपको जल्दी से की बोर्ड का कोई भी बटन दबाना है. ऐसा करने से सिस्टम रोम से बूट करेगा.

विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए :

अगर आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक नीले रंग की स्क्रीन सामने आ जाएगी. स्क्रीन के सबसे नीचे वाले पार्ट में कई फाइल्स के नाम एक के बाद एक आते रहेंगे, क्योंकि सेटअप प्रोग्राम रोम

से सिस्टम फाइल्स को रीड कर रहा होता है.

अगर आप विन्डो एक्सपी इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक नीले रंग की स्क्रीन सामने आ जाएगी. स्क्रीन के सबसे नीचे वाले पार्ट में कई फाइल्स के नाम एक के बाद एक आते रहेंगे, क्योंकि सेटअप प्रोग्राम रोम से सिस्टम फाइल्स को रीड कर रहा होता है. उसके बाद आपको सेटअप स्क्रीन दिखेगा, जिसमें तीन ऑप्शन दिखेगा, फॉर्मेट करने के लिए एंटर दबाएं, फिर लाइसेंसिंग एग्रिमेंट की स्क्रीन आएगी, उसको भर कर आप एफ8 बटन दबाएं, जिसके बाद आपको हार्ड डिस्क का पार्टिशन दिखाई देगा, अब जिस भी पार्टिशन पर विंडोज एक्सपी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करके इंटर दबाएं (सामान्यत: सी ड्राइव में इंस्टॉल रहता है)

अगली स्क्रीन पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगी, जिसमें आप Format using NTFS सेलेक्ट करके एंटर करें, एंटर करते ही ये ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा और सेटअप हार्ड डिस्क में फाइल्स को कॉपी करना शुरू कर देगा. थोड़ी देर में कंप्यूटर री-स्टार्ट होगा, अब ध्यान दें पहले की तरह स्टार्ट होते ही आपको प्रेस एनी की का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन इस बार आपको कोई बटन नहीं दबाना है, जिससे सिस्टम खुद-ब-खुद विंडो एक्सपी ग्राफिकल इंटरफ़ेस आएगा, जिसमें आपको Regional and Language Options दिखेगा, उसको सेट कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, इसके बाद Personalize योर सॉफ्टवेयर स्क्रीन दिखेगा, जिसमें आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे और नेक्स्ट पर क्लिक करें, जिसके बाद Your Product Key ऑप्शन आएगा, जिसमें अपने सॉफ्टवेयर की सीडी के साथ मिली 25 कैरेक्टर की CD key को एंटर कर नेक्स्ट करें, फिर कंप्यूटर नाम और पासवर्ड अपने इच्छानुसार टाइप करें और Next बटन पर क्लिक करें. फिर डेट और टाइम सेट कर लें और Time Zone Combo बॉक्स में GMT +5:30 Chennai, Kolkata... ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

फिर नेक्स्ट दबाने पर विंडोज एक्सपी आपके नेटवर्क सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने लगेगा, इसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी. यहां आप डिफॉल्ट सेटिंग Typical Settings को ही सिलेक्ट रहने दें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद वर्क ग्रुप और कंप्यूटर डोमेन ऑप्शन आएगा. यहां भी आप बिना कुछ चेंज किए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें.

अब इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर री-स्टार्ट हो जाएगा और Display Settings का मैसेज आएगा, जिसमें आप ओके बटन पर क्लिक करें. इसके बाद फिर ओके दबाने के बाद विंडोज आपके डिस्प्ले कार्ड के मुताबिक स्क्रीन रेजॉल्यूशन सेट हो जायेगा हो जायेगा. फिर आपके सामने Who Will Use This Computer स्क्रीन आएगी, जहां आप 5 यूजर्स के नाम डाल सकते हैं. इसके बाद Next और अगली स्क्रीन पर फिनिश बटन दबाए. विंडोज का डेस्कटॉप आपके सामने होगा.

जारी...

smart7973@gmail.com

अपने ठेले पर मेडल्स लटकाकर रखने वाली पुष्पा को उम्मीद है कि उनके मेडल्स देखकर कोई तो उनकी मदद करेगा. पुष्पा ने एमएस यूनिवर्सिटी से बी-कॉम की डिग्री हासिल की है. स्कूलिंग के दौरान पुष्पा ने शहर और राज्य स्तर पर राइफल शूटिंग की प्रतियोगिताओं में कई मेडल्स हासिल किए. कॉलेज के दौरान राज्य स्तर पर पुष्पा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आज उन्हें सड़क पर चाउमीन बेचनी पड़ रही है.

महाबली खली से जुड़ी दस ख़ास बातें

नेशनल लेवल खिलाड़ी

चौथी दुनिया ब्यूरो

हिमाचल के जिला सिरमौर के एक छोटे से गांव के रहने वाले दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली आज भारत की शान हैं. घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. कई बार लोग उन्हें देखकर हंसने लगते थे. मगर लोगों को क्या मालूम था कि यही शख्स आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा.

1. द ग्रेट खली के नाम से मशहूर भारतीय मूल के डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर का असली नाम दिलीप सिंह राणा है. खली का सीना 56 इंच का नहीं, बल्कि 63 इंच का है. यह भारतीय रिकॉर्ड है.

2.द ग्रेट खली शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, डोपिंग के मामले में उनका रिकॉर्ड बेहद साफ-सुथरा है.

3. द ग्रेट खली रेसलिंग की दुनिया के सबसे लंबे खिलाड़ी हैं. खली की लंबाई 7 फुट 1 इंच है. खली ने प्रो-रेसलिंग में 7 अक्टूबर 2000 को पहली बार कदम रखा था.

4. खली सन 1997 और 1998 में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं. खली पंजाब पुलिस में रहते हुए बॉडी बिल्डिंग करते थे.

5.द ग्रेट खली रेसलिंग की दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी माने जाने वाले अंटरटेकर को मुक्के बरसाकर बेहोशी की हालत में लाकर जीत दर्ज कर चुके हैं. खली ने पहली बार अंडरटेकर को 7 अप्रैल 2006 को हराया था.

> प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास लेने के बाद अब खली पत्नी हरमिंदर कौर के साथ भारत में खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं. हालांकि, हाल ही में खबर आई थी कि वह फिर से रिंग में वापसी कर सकते हैं.

6.द ग्रेट खली 2007-08 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं. उन्होंने इस ताज के लिए जान सीना, अंडरटेकर और ट्रिपल एच जैसे खूंखार फाइटरों को मात दी थी.

7. द ग्रेट खली सिर्फ भारतीय टीवी चैनलों पर ही नज़र नहीं आते, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. वह एक फ्रेंच फिल्म में भी अभिनय करते नज़र आ चुके हैं.

8. द ग्रेट खली की प्रतिभा से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम बेहद प्रभावित हुए थे. डॉ कलाम ने सन 2005 में खली को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उनसे मुलाकात भी की थी.

9. प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास लेने के बाद अब खली पत्नी हरमिंदर कौर के साथ भारत में खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं. हालांकि, हाल ही में खबर आई थी कि वह फिर से रिंग में वापसी कर सकते हैं.

10. द ग्रेट खली कई ब्रांड्स को इंडोर्स कर चुके हैं. मौजूदा समय में उनका एक सीमेंट कंपनी के लिए किया गया ऐड लोगों को खूब पसंद आ रहा हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सड़क पर चाउमीन बेचने को मजबूर

राइफल शूटिंग में नेशनल लेवल पर गुजरात का नाम रोशन करने वाली शूटर पुष्पा गुप्ता परिवार का पेट पालने के लिए सड़क किनारे चाउमीन बेचने के लिए मजबूर हैं. अपने ठेले पर मेडल्स लटकाकर रखने वाली पुष्पा को उम्मीद है कि उनके मेडल्स देखकर कोई तो उनकी मदद करेगा. पुष्पा ने एमएस यूनिवर्सिटी से बी-कॉम की डिग्री हासिल की है. स्कूलिंग के दौरान पुष्पा ने शहर और राज्य स्तर पर राइफल शूटिंग की प्रतियोगिताओं में कई मेडल्स हासिल किए. कॉलेज के दौरान राज्य स्तर पर पुष्पा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आज उन्हें सड़क पर चाउमीन बेचनी पड़ रही है. पुष्पा का कहना है कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात का नाम रोशन किया, लेकिन राज्य सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की. पुष्पा ऐसी पहली खिलाड़ी नहीं हैं जिन्हें देश-राज्य का नाम रोशन करने के बावजूद दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. सरकार के पास पूर्व खिलाड़ियों के लिए कोई योजना नहीं है. सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए. ■

मैं रिकॉर्ड के पीछे नहीं, मेरे पीछे रिकॉर्ड भागते हैं

कलब रियल मेड्रिड के लिए खेलने वाले पुर्तगाल के करिश्माई फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है मैं अपना खेल बेहतर तरीके से खेलता हूं इस लिए मे कभी रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागता. 1965 के बाद यूरोपियन प्रतियोगिता में यह पहली बार हुआ कि मैड्रड के किसी खिलाडी ने एक मैच में चार गोल किए हो. एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने कहा, मैं इस बात से बुहत खुश हूं कि मैं रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागता बल्कि रिकॉर्ड मेरे पीछे भागते हैं. कुछ समय पहले खबर जोरोंपर थी कि रोनाल्डो क्लब रियल मेड्रिड छोड़ना चाहते हैं. रोनाल्डो ने इस खबर पर कहा कि मैं क्लब छोड़ कर कहीं नहीं जा रहा. अटकलें हर जगह होती हैं. इस क्लब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं इसके साथ खुश हूं. ■

यूं ना भूला पाएंगे...

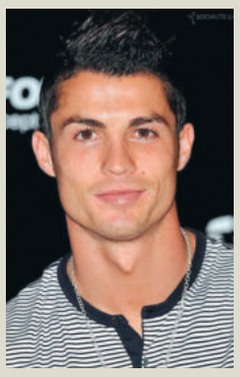

मांकड़ से बना मांकड़ आउट होना नियम

भारतीय क्रिकेट में वीनू मांकड़ को आज भी एक दिग्गज खिलाड़ी के रूप में गिना जाता है. आज भी उनका नाम विश्व के महान ऑलराउंडरों में गिना जाता है. वीनू मांकड़ का जन्म 12 अप्रैल, 1917 को गुजरात में हुआ था. उनका पूरा नाम मूलवंत राय हिम्मतलाल मांकड़ था. वीनू मांकड़ को महान ऑलराउंडरों में इसलिए गिना जाता है, क्योंकि सन् 1956 में वीनू मांकड़ ने पंकज राय के साथ मिलकर 413 रन की ओपनिंग साझेदारी की थी, उनका यह रिकॉर्ड 52 साल बाद टूटा. वीनू मांकड़ ने अपने करियर के दौर में प्रमुख टीमें जैसे भारत, बंगाल, गुजरात, हिंदुओं, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान और पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व भी किया. खेल की शैली के आधार पर देखा जाए तो वीनू दाएं हाथ के बल्लेबाज़ और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ थे. वीनू मांकड़ का भारतीय क्रिकेट में हमेशा से एक अद्भुत योगदान रहा है. उन्होंने भारत के लिए 44 टेस्ट मैचों में 31.47 की औसत 2109 रन बनाए. जिसमें पांच टेस्ट शतक और 6 अर्द्धशतक शामिल थे. इनका शीर्ष स्कोर 231 रहा. उन्होंने गेंदबाज़ी में 32.32 की औसत से 162 विकेट भी लिए. इसके अतिरिक्त उन्होंने 233 प्रथम श्रेणी मैचों में 34.70 की औसत से 26 शतक और 52 अर्द्धशतक सहित 11,591 रन और गेंदबाज़ी में 24.53 के शानदार औसत से 782 विकेट भी लिए. क्रिकेट में मांकड़ आउट होना नियम को तो हर कोई जानता है, लेकिन मांकड़ आउट होने का नियम कैसे वीनू मांकड़ से जुड़ा है शायद ही यह कोई जानता हो. ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सिडनी टेस्ट में भारतीय गेंदबाज़ वीनू मांकड़ ने विपक्षी बल्लेबाज को कुछ ऐसे आउट किया जिसे देखकर सब दंग रह गए. मांकड़ ने गेंदबाज़ी करते हुए क्रीज तक पहुंचे बिना गेंद फेंकेने वाले नॉन स्ट्राइकिंग छोर की गिल्लियां बिखेर दीं. कंगारू बल्लेबाज बिल ब्राउन गेंद डाले जाने के पूर्व ही रन लेने की जल्दबाज़ी में क्रीज छोड़ चुके थे. मांकड़ ने गिल्ली उड़ाते ही रन आउट की अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी. हालांकि मांकड़ की इस हरकत को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए आलोचना की पर दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन समेत कुछ विपक्षी खिलाड़ियों ने मांकड़ का बचाव किया. बाद में आउट करने का यह तरीक़ा क्रिकेट के नियमों में शामिल हो गया और इसका नाम मांकड़ आउट पड़ गया. क्रिकेट नियमों की धारा 42.15 के अंतर्गत मांकड़ आउट को वैधानिक करार दिया गया. वीनू मांकड़ ने अपना पहला टेस्ट मैच 22 जून, 1946 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और आख़िरी टेस्ट मैच 6 फ़रवरी 1959 वेस्टइंडीज के ख़िलाफ खेला था. वीनू मांकड़ के बेटे अशोक मांकड़ ने भी भारत क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था. वीनू मांकड़ की मृत्यु सन् 21 अगस्त 1978 मुंबई में हुई, लेकिन आज भी क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण और उनकी खेल भावना आज भी जिंदा है. ■

एक नज़र

कोच पद से हटाए गए गैरी कर्स्टन

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने गैरी कर्स्टन को टीम के कोच पद से हटा दिया है. इस बात की घोषणा दिल्ली डेयरडेविल्स फ्रेंचाइजी ने की. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज कर्स्टन को 2014 में डेयरडविल्स का कोच नियुक्त किया गया था. कर्स्टन के कोच रहते डेयरडेविल्स की टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. 2014 में टीम अंकतालिका में सबसे नीचे रही, जबकि 2015 में टीम 14 मैचों में सिर्फ पांच जीत हासिल कर आठ टीमों की अंकतालिका में सातवां स्थान हासिल कर सकी. ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग शीपर्ड अब डेयरडेविल्स टीम में कर्स्टन की जगह लेंगे. कर्स्टन के मार्गदर्शन में ही भारतीय टीम ने 2011 का विश्व कप जीता था. ■

कुश्ती लीग से जुड़े रोहित शर्मा

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी अब प्रो-कुश्ती लीग से जुड़ गए हैं. रोहित शर्मा यूपी वारियर्स के सह मालिक बन गए हैं. रोहित शर्मा ने कहा कि भारत मे कुश्ती का लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है. मुझे फक्र है कि मैं प्रो कुश्ती लीग में यूपी वारियर्स टीम का सह मालिक बना हूं. हमारे पास भारत के सबसे बड़े पहलवान सुशील कुमार समेत काफी अच्छी टीम है. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जबरदस्त प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान हासिल करें. रोहित कुश्ती लीग से जुड़ने वाले पहले क्रिकेटर हैं. लीग के आयोजक विशाल गुरनानी ने भी रोहित के कुश्ती लीग से जुड़ने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा रोहित एक नामी क्रिकेटर हैं और हम उनका कुश्ती लीग से जुड़ने पर स्वागत करते हैं. हमें यकीन है कि उनके आने से लीग को और लोकप्रियता मिलेगी. ■

आईपीएल में शामिल हुईं दो नई टीमें

INDIAN PREMIER LEAGUE

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से दो टीमों को प्रतिबंधित किए जाने के बाद दो नई टीमों को लीग में शामिल किया गया है. राजकोट और पुणे आईपीएल की नई टीमें होंगी. ये टीमें आईपीएल के साल 2016 सीजन में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स का स्थान लेंगी. इंटेक्सम ने जहां राजकोट की टीम खरीदी हैं, वहीं दूसरी तरफ संजीव गोयनका ने पुणे की टीम खरीदी है. आईपीएल संचालन परिषद की बैठक में आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने टीम के नाम का ऐलान किया. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल-6 भ्रष्टाचार मामले की जांच के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण बीसीसीआई को टी-20 लीग के लिए दो नई टीमों को टूर्नामेंट से जोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा. इसके बाद बीसीसीआई ने दो नई टीमों के लिए टेंडर जारी किया था. इन दो टीमों के लिए 10 से ज़्यादा कंपनियों ने बोली लगाई थी. इनमें स्टार इंडिया, वोडाफोन, वीडियोकॉन और एनडीटीवी जैसी कंपनियां शामिल थीं. ऐसी खबरें भी आ रहीं थीं कि महेंद्र सिंह धोनी भी आईपीएल टीम खरीदने के इच्छुक थे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

दीपिका चलीं हॉलीवुड

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के बाद अब जानी मानी अदाकारा दीपिका पादुकोण भी हॉलीवुड में कदम रखने का मन बना रही हैं. वैसे तो अमिताभ बच्चन से लेकर कई तमाम बॉलीवुड कलाकार हॉलीवुड में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं. कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि दीपिका हॉलीवुड फिल्म फास्ट एण्ड फ्यूरियस में काम करने वाली हैं. मगर, किसी वजह से उनकी हॉलीवुड में कदम रखने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन, हाल ही में उन्होंने अमेरिकन एक्टर विन डीजल के साथ ट्विटर पर तस्वीर शेयर की है. फोटो को शेयर करते हुए दीपिका ने और कुछ नहीं लिखा है. कहा जा रहा है कि दीपिका ने फोटो पोस्ट कर हॉलीवुड फिल्म में अपने काम करने की इच्छा को जाहिर कर दिया है.■

बॉलीवुड के किंग और क्वीन की जोड़ी मचाएगी धूम

पहले तो शाहरुख के साथ कटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा था, पर अब कटरीना की जगह कंगना को लिए जाने की चर्चा हो रही है. इस फिल्म में काम करने की इच्छा कंगना ने खुद निर्देशक से जताई थी.

बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अब एक साथ बड़े परदे पर नज़र आने वाले हैं. सूत्रों की माने तो निर्देशक आनंद एल रॉय की आने वाली फिल्म में शाहरुख और कंगना की जोड़ी नज़र आ सकती है. काफी समय से आनंद एल रॉय की आगामी फिल्म के स्टार कास्ट की बातें सुनाई दे रही थीं, जिसमे पहले तो शाहरुख के साथ कटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा था, पर अब कटरीना की जगह कंगना को लिए जाने की चर्चा हो रही है. इस फिल्म में काम करने की इच्छा कंगना ने खुद निर्देशक से जताई थी और यह फिल्म पहले बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान को ऑफर की गई थी, पर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और यह खबर मीडिया में लीक हो गई. जिसकी वजह से सलमान काफी नाराज हो गए और इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया.■

हॉलीवुड ख़बर

मॉलिन रूश में काम करने के दौरान निकोल ने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में देखीं और उसी दौरान निकोल को बॉलीवुड फिल्मों से प्यार हो गया.

बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं निकोल किडमैन

ऑस्कर विजेता हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहती हैं. उन्हें बॉलीवुड फिल्मों से यह प्रेम बैज़ लुहरमन की फिल्म मॉलीन रूश में काम करने के दौरान हुआ, जो की एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म से प्रेरित थी. एक इंटरव्यू के दौरान जब निकोल से पूछा गया कि क्या वह बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? तो उनका कहना था कि मॉलिन रूश में काम करने के दौरान मैंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में देखीं और उसी दौरान मुझे बॉलीवुड फिल्मों से प्यार हो गया. मॉलिन रूश में निकोल ने एक बीमार कैबेरे अभिनेत्री और तवायफ का किरदार निभाया था. निकोल का मानना है कि हॉलीवुड की नकल करने के चक्कर में बॉलीवुड को अपना अनूठापन नहीं खोना चाहिए. निकोल फिलहाल तो अभी किसी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म लायन के कुछ हिस्से कोलकाता में फिल्माए जाने हैं और इस फिल्म में निकोल के साथ देव पटेल भी नजर आएंगे.■

मुझे लोग कटरीना जैसा कहते थे, जिसका ख़ामियाजा भुगतना पड़ा...

कटरीना से ख़फ़ा ज़रीन खान

फिल्म हेट स्टोरी 3 से बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी करने वाली हॉट अदाकारा जरीन खान आज- कल कटरीना से काफी खफा हैं. जरीन का कहना है कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में कटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस की तरह दिखने का खामियाजा भुगतना पड़ा. जरीन ने अपने करियर की शुरुआत दबंग खान के फिल्म वीर से की थी. जरीन ने ये बातें अपने एक इंटरव्यू में कहा है. जरीन ने कहा कि मुझे लोग कटरीना जैसा कहते थे. क्योंकि इंडस्ट्री में एक जैसे दिखने वाले दो लोगों को ज्यादा मौका नहीं मिलता है. बॉलीवुड में सभी अपनी पहचान बनाने आए हैं. मैं भी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूं, किसी के साये में नहीं रहना चाहती. अच्छा लगता है कि लोग अब मुझे मेरे नाम से जानते हैं.■

जरीन का कहना है कि उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में कटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस की तरह दिखने का खामियाजा भुगतना पड़ा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जन्मदिन मुबारक

बजरंगी भाई जान

बॉलीवुड के दबंग खान मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं. सुपर स्टार सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर, 1965 को हुआ था. फिल्म मैंने प्यार किया से लेकर प्रेम रतन धन पायो तक में काम करने वाले सलमान खान बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक हैं. फिल्म बजरंगी भाईजान में उनके किरदार को काफी सराहा गया. सलमान हिंदी फिल्मों के मशहूर पटकथा लेखक (स्क्रिप्ट राइटर) सलीम खान के सबसे बड़े बेटे हैं. सलमान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने प्रेम संबंधों के लिए भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. कभी सोमी अली, कभी एश्वर्या राय, तो कभी कटरीना कैफ के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है. संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में एश्वर्या राय के साथ सलमान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी, जिसमें उनका एक छोटा सा रोल था. सलमान को अपनी पहली बड़ी सफलता 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया से मिली, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर (सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए) पुरस्कार भी दिया गया. फिल्म मैंने प्यार किया ने तो उन्हें नौजवानों का हीरो बना दिया. फिर अंदाज अपना अपना में उन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीता. उसके बाद उन्होंने फिल्म करन अर्जुन में एक एक्शन स्टार की तरह जलवे दिखाए. अगर बात 2015 की करें, तो सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने लगभग 200 करोड़ से भी अधिक की कमाई की है. सलमान खान की बॉयोग्राफी 27 दिसंबर को उनके जन्मदिन की 50वीं सालगिरह पर रिलीज होगी. बीइंग सलमान नाम की इस बायोग्रफी के लेखक जासिम खान हैं. इसमें उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित महत्वपूर्ण एवं रोचक घटनाओं के साथ-साथ उनके परिवार के बारे में भी जानकारी होगी. जो उनके प्रशंसकों को काफी रोमांचित करेगी.■

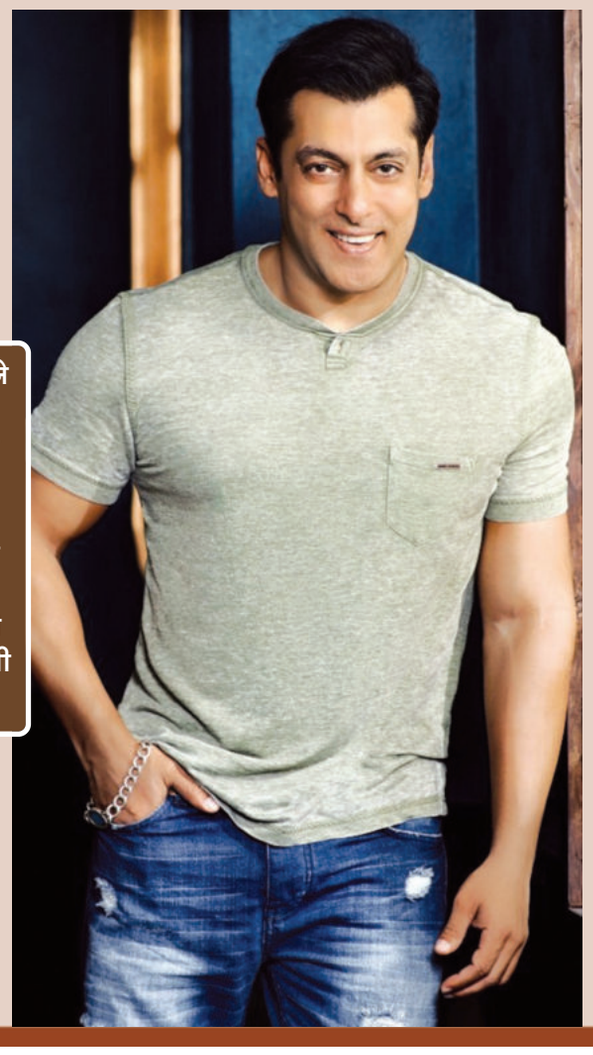

सलमान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने प्रेम संबंधों के लिए भी अक्सर चर्चा में रहते हैं. कभी सोमी अली, कभी एश्वर्या राय, तो कभी कटरीना कैफ के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है. संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में एश्वर्या राय के साथ सलमान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया. सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

21 दिसंबर-27 दिसंबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कौन होगा भाजपा का नया कमांडर

बिहार भाजपा में शीर्ष नेतृत्व की शक्ल-ओ-सूरत बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है. तलवार मंगल पांडेय पर लटक रही है. चुनाव में हुई पार्टी की हार का ठीकरा उनके सिर फूटना तय माना जा रहा है. ऐसे में कई फेरबदल जल्द ही नजर आएंगे. आशा यह की जा रही है कि पार्टी का नया अध्यक्ष किसी ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को बनाया जा सकता है जो सत्ता की दौड़ से अलग सिर्फ संगठन के प्रति समर्पित रहा हो और उसकी राजनीतिक छवि बेदाग हो...

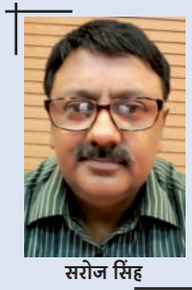

सरोज सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद भाजपा में पटना से लेकर दिल्ली तक इस बात पर मंथन तेज है कि जितनी जल्दी हो सके पुराने मठाधीशों को हटा कर उनकी जगह दूसरे नेताओं को मौका दिया जाए. तीन बड़े चेहरे यानि कि सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव और मंगल पांडेय को विराम देकर उनकी जगह पार्टी की कमान दूसरे तपे-तपाए नेताओं को देने पर आम राय बनाने का काम तेजी से जारी है. पहली कड़ी में नंदकिशोर यादव को हटकार उनकी जगह पर अतिपिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रेम कुमार को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी जा चुकी है. अब बारी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय की है. भाजपा का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर सहमत है कि मंगल पांडेय को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से अलग कर दिया जाए. करारी हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी गिरा हुआ है और ऐसे में अगर अध्यक्ष पद पर किसी तेजतर्रार नेता को नहीं बिठाया गया तो पार्टी को आगे ले जाना बेहद मुश्किल हो जाएगा. वैसे भी हार की नैतिक जिम्मेदारी तो मंगल पांडेय की बनती ही है. यह अलग बात है कि उन्होंने इसे कबूल करते हुए अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है. जानकार सूत्र बताते हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह नहीं चाहता है कि किसी हारे हुए सेनानायक के नेतृत्व में 2019 की लड़ाई की तैयारी की जाए. अगर मंगल पांडेय का अध्यक्ष पद बरकरार रखा जाता है तो इसका बुरा प्रभाव 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है. इसलिए पार्टी नेतृत्व की इच्छा है कि किसी तेजतर्रार और साफ सुथरी छवि वाले नेता को पार्टी की कमान सौंपी जाए. खोज ऐसे नेता की है जो कभी सत्ता की राजनीति में नहीं रहा हो और केवल और केवल संगठन से जुड़ा रहा हो. पार्टी नेतृत्व को लगता है कि इस तरह का व्यक्ति ही अध्यक्ष पद के लिए सर्वथा उपयुक्त होगा. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी की प्राथमिकता सही मायनों में जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर विजय का मंत्र देने की है. संगठन में रहा व्यक्ति इस काम को बखूबी अंजाम दे सकता है. इसके उलट सरकार में रहा कोई नेता कार्यकर्ताओं की बीच पूरी तरह स्वीकार हो, इसकी संभावना कम रहती है. कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ शिकायत रहती ही रहती है. इसलिए इस बार प्राथमिकता खांटी संगठन से जुड़ा नेता ही है. पार्टी नेतृत्व को लग रहा है कि बिहार में पार्टी को नए सिरे से खड़ी करने की चुनौती है. इसलिए इस बार अध्यक्ष का चयन काफी सोच विचार कर करने की जरूरत है. हालांकि मंगल पांडेय इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक मौका और दिया जाए लेकिन प्रदेश में भाजपा के अंदर इनके खिलाफ जो गुस्सा है उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि मंगल पांडेय की इच्छा पूरी हो पाएगी. इसलिए हालात को परखते हुए भाजपा के कई नेता अध्यक्ष पद पाने के लिए अपने अपने हिसाब से सक्रिय हो गए हैं. ऐसे नामों में अभी सबसे आगे सालों से संगठन से जुड़े युवा चेहरे सुधीर शर्मा हैं. सब से दिल खोल कर मिलने वाले और जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखने वाले सुधीर शर्मा के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश भाजपा के सभी नेताओं के वह प्रिय हैं और संगठन के कामों में कई दफा उन्होंने अपनी योग्यता साबित भी की है. अभी विधानसभा चुनाव में बागी के तौर पर उतरे कई भाजपाइयों को उन्होंने अपने स्तर से बातचीत कर नामांकन वापस करवा दिया. इसका परिणाम यह हुआ कि इन इलाकों में भाजपा की जीत हुई. बेदाग छवि वाले सुधीर शर्मा हालांकि अपने को इस तरह की किसी भी दौड़ से अलग बताते हैं लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि सुधीर शर्मा के नाम पर आमराय बनाने का काम तेजी से चल रहा है. भूमिहार बिरादरी से आने के कारण भी सुधीर शर्मा का दावा मजबूत लग रहा है. नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रेम कुमार के आ जाने से यह पार्टी के लिए जरूरी हो गया है कि अगड़ी जाति के ही किसी नेता को अध्यक्ष की कुर्सी दी जाए. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल सातवें आसमान पर है. कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जो अगड़ा वोट पार्टी से छिटक कर भाजपा के पास चला गया था, उसे वापस लाने का यही सुनहरा मौका है. कांग्रेस अभी सत्ता में है इसलिए अगड़ी जातियों को समझाने में मदद मिल सकती है. चुनाव में अगड़ी जाति के कई नेता कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए हैं. कांग्रेस की यही रणनीति भाजपा के डर का कारण है. भाजपा किसी भी हालत में अपने सवर्ण जनाधार को खोना नहीं चाहती है, इसलिए अगड़ी जाति के नेता को अध्यक्ष पद देना भाजपा की मजबूरी बन गई है. भाजपा की यह मजबूरी भी सुधीर शर्मा के पक्ष में माहौल बना रही है. वैसे इस जाति से सीपी ठाकुर का नाम भी धीरे से लिया जा रहा है पर उनकी बढ़ती उम्र और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिये उनके योगदान की निगेटिव मार्किंग उनको इस रेस में काफी पीछे धकेल रही है. उल्लेखनीय है कि सीपी ठाकुर ही बिहार में चुनाव अभियान समिति के अगुवा थे पर वह अपने बेटे को भी जीताकर विधानसभा नहीं भेज पाए. राजपूत बिरादरी से अध्यक्ष पद के लिए दो नामों की चर्चा है. पहला नाम राजेंद्र सिंह का है तो दूसरा नाम गोपाल नारायण सिंह का है. राजेंद्र सिंह झारखंड में संगठन का बेजोड़ काम कर चुके हैं पर हाल ही में दिनारा के चुनाव में इनकी हार ने इनका ग्राफ काफी नीचे कर दिया है. वही हाल गोपाल नारायण सिंह का भी है. गोपाल भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए. अपने पहले कार्यकाल में भी गोपाल नारायण सिंह का कार्यकाल बहुत बेहतर साबित नहीं हुआ था. इसलिए अगर राजपूत बिरादरी से ही अध्यक्ष बनाने का फैसला होता है तो राजेंद्र सिंह आगे नजर आते हैं. इसके अलावा ब्राह्मण में तीन नाम चल रहे हैं. मंगल पांडेय तो खुद अपने लिए लगे ही हुए हैं. इनके अलावा अश्विनी चौबे ओर विनोद नारायण झा का नाम चर्चा में है. यहां यह गौर करने वाली बात यह है कि अश्विनी चौबे अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जीता पाए और विनोद नारायण झा खुद अपना चुनाव हार गए.

भाजपा के सूत्र बताते हैं कि पार्टी आलाकमान किसी हारे हुए घोड़े पर दांव लगाने के मूड में कतई नहीं है. इसलिए किसी युवा और तेजतर्रार अगड़ी जाति के नेता को अध्यक्ष पद देकर इसके साथ पिछड़े और अतिपिछड़े की एक शानदार टीम देकर काम को आगे बढ़ाने का मन पार्टी नेतृत्व बना चुका है. सुशील मोदी को लेकर चर्चा है कि उन्हें केंद्र में संगठन में कोई बड़ा पद या मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जा सकती है. इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार कोटे से अभी जितने मंत्री हैं, उनमें कटौती होगी और हटाए गए मंत्रियों को संगठन में जगह दी जाएगी. कहा जाए तो बिहार भाजपा का पूरी तरह कायाकल्प करने का इरादा है और मौजूदा पूरी टीम का बदलना तय है. भाजपा अब लोकसभा चुनाव को लेकर संजीदा है इसलिए हार से सबक सीखते हुए फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है. उम्मीद की जा रही है कि नए साल में खरमास के बाद बिहार भाजपा की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी. पटना के कुछ लोग दिल्ली में और दिल्ली के कुछ लोग पटना में नजर आएंगे.■

"खोज ऐसे नेता की है जो कभी सत्ता की राजनीति में नहीं रहा हो और केवल और केवल संगठन से जुड़ा रहा हो. पार्टी नेतृत्व को लगता है कि इस तरह का व्यक्ति ही अध्यक्ष पद के लिए सर्वथा उपयुक्त होगा. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी की प्राथमिकता सही मायनों में जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर विजय का मंत्र देने की है. संगठन में रहा व्यक्ति इस काम को बखूबी अंजाम दे सकता है. इसके उलट सरकार में रहा कोई नेता कार्यकर्ताओं की बीच पूरी तरह स्वीकार हो, इसकी संभावना कम रहती है. कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ शिकायत रहती ही रहती है."

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

होम केयर का प्रशिक्षण

खगड़िया में अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग द्वारा दशरथ मांझी कौशल विकास योजना अन्तर्गत फ्रेश फाउंडेशन के द्वारा दलित एवं महादलित वर्ग के 120 लड़के एवं लड़कियों के लिए नर्सिंग होम केयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण प्राप्त किये छात्र-छात्राओं को सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग में नियोजन मिल सकेगा. उक्त बातें फ्रेश फाउंडेशन के सचिव आसिफ इकबाल ने कहीं. मौके पर प्रशिक्षक जुली कुमारी, अंकिता प्रसाद सिंह, केन्द्र प्रबंधक अभिषेक कुमार, गौरव संयोजक कृष्ण मोहन सिंह प्रशिक्षणार्थी लुटन कुमार, राहुल कुमार, खुशबू काजल आदि उपस्थित थे.

युवा चेतना शिविर

खगड़िया के जन नायक कर्पूरी ठाकुर इंटर विद्यालय के स्टेडियम में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज, हरिद्वार के तत्वावधान में प्रांतीय युवा चेतना शिविर आयोजित किया गया. प्रातः कालीन सत्र को शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं संपूर्ण भारत के जोन प्रभारी कालीचरण शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने उद्धार हेतु आत्मा की आवाज सुनकर चलें. प्रांतीय एवं जिलास्तरीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति क्रमशः मनीष कुमार एवं अमित कुमार ने की. अखिल विश्व गायत्री परिवार के सत्र प्रमुख डॉ. प्रणव पांड्या जी का मंगल प्रभाव हुआ. डॉ. पांड्या ने वर्तमान समय में युवाओं के व्यक्तित्व संवर्धन हेतु अपनी संकीर्णताओं एवं दुर्बलताओं को छोड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवाओं को दुर्बलताओं यथा मद्यपान, नशा इत्यादि का परित्याग कर सद्बुद्धि के सानिध्य में आना चाहिए. डॉ साहब ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बिहार को गौरव प्रदान करने हेतु हर कदम उठाने का आह्वान किया. मौके पर प्रान्तीय संयोजक डॉ. अरुण कुमार जायसवाल, शंतिकुंज प्रतिनिधि केपी दूबे आशीष कुमार, मनीष कुमार मौजूद थे. मंच संचालन पी दूबे के द्वारा किया गया. स्थानीय प्रतिनिधियों में अरविन्द प्रसाद हिमांशु, जगदीश फोगला, डॉ. अमोद कुमार, भोला गुप्ता, मंजू कुमारी, प्रभा कुमारी, यशोदा देवी, श्री नारायण छापरिया, श्याम खेड़िया, राजेन्द्र प्रसाद, प्रमोद केडिया सहित अन्य मौजूद थे.

– मनेन्द्र कुमार

छात्रवृत्ति का उपयोग पढ़ाई में करें

स्थानीय बलुआही स्थित बापू मध्य विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक के सामान्य छात्र-छात्राओं को 73,800 तथा बीसी-1 के छात्रों को 3,03,600 रुपये की छात्रवृत्ति की राशि बांटी गयी. इस अवसर पर नगर सभापति मनोहर कुमार यादव ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही राशि का उपयोग पठन पाठन के कार्यो में ही करें. मौके पर प्रधानाध्यापक चन्द्रमणि मिश्र विद्यालय शिक्षा समिति अध्यक्ष हेमाभारती, शिक्षक मनोज कुमार, विभा कुमारी, राजेन्द्र राजेश, कर्ण प्रिया, अमरकांत शरण, शिवराज यादव, रणवीर कुमार सहित अन्य उपस्थित थे.■

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

ठंढ का मौसम और परेशानियां
ariskon Pharma Pvt.Ltd. नव वर्ष की बधाई
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ.ओ.पी.शर्मा फिजिशियन,मुजफ्फरपुर

जाड़े का मौसम काफी कष्टदायक माना जाता है हालांकि इस मौसम का उपयोग सेहत बनाने के लिए भी किया जा सकता है इन दिनों हरी सब्जियां सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं ठंड से संबंधित कुछ बातें मुजफ्फरपुर के अनुभवी डॉ. ओ.पी. शर्मा जी से हुई इस दरम्यान उन्होंने लोगों को जाड़े के मौसम में इम्यूनिटि को मेन्टेन करने की सलाह दी और बताया कि गरम कपड़ा पहन कर निकलें, अपने को बाहरी ठण्ढ से बचायें और घर में भी खाने में गर्म चीजें लें जो लोग नॉनभेज खाते हैं वो इसे खायें। शाकाहारी लोग दूध के आलावा चव्यनप्राश, तिल, भोजन में लहसुन, प्याज, अदरक, घी, मूंग की दाल, आदि अवश्य लें। पानी हल्का गरम लें। यदि हल्का बुखार और दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह पर एनालजेसिक टेबलेट ले सकते हैं तथा नाक बहने व ठंढ से बचाव के लिए लिवोसिट्रीजिन लिया जा सकता है। इस मौसम में कई प्रकार की समस्यायें शुरू हो जाती हैं, खासकर जोड़ों से संबंधित समस्या। इस मौसम में जोड़ों का दर्द किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो सर्द मौसम का अधिक असर दिखेगा। इस मौसम में उम्रदराज लोगों को सबसे अधिक समस्या होती है, क्योंकि उनका बोन डेंसिटी कम हो जाता है। इसलिए सर्दी के मौसम में जोड़ों के दर्द को कम करने वाले उपाय आजमाने चाहिए। जैसे-जैसे तापमान कम होता जाता है, रक्तवाहिनियां सिकुड़ने लगती हैं और उस हिस्से में खून का तापमान कम होने लगता है। इसके कारण जोड़ सिकुड़ने लगते हैं और दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा ठंड में दिल के आसपास रक्त की गर्माहट बनाए रखने के लिए शरीर के अन्य अंगों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिसका परिणाम जोड़ों में दर्द है। अगर आप किसी भी तरह के अर्थराइटिस से ग्रस्त हैं तो कैल्शियम की कमी को दूर करें। सुबह की धूप गुनगुनी धूप जरूर लीजिए। इसमें विटामिन डी होता है जो कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से आराम दिलाता है।
■ प्रस्तुति: चित्रा भारती

URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
Levokon-AZ Levofloxacin 250 mg + Azithromycin 250 mg Tab
Siliplex L-Ornithine L-Aspartate 5 gm/10ml Infusion Lowers Ammonia level & improves liver function
OFFLOGYL-OS Ofloxacin+Ornindazole+Lactic Acid Bacillus + Saccharomyces Boulardii Tab
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of Ariskon Pharma

जमुई

कलंकित होने से बचा जमुई

जैन श्वेताम्बर सोसाइटी द्वारा खैरा थाने में चोरी से संबंधित मामला दर्ज कराया गया. जिसमें सात अज्ञात लोगों के घटना में शामिल होने की बात कही गयी. घटना की खबर जंगल की आग की तरह इतनी तेजी से फैली कि पूरे देश को इसने अपने आगोश में ले लिया. जैन समुदाय के लिए तो यह आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था, जिससे पूरा सम्प्रदाय अंदर से हिल गया.

तरुण मिश्रा

जिले की एक हालिया घटना ने जमुई की न सिर्फ छवि धूमिल की अपितु आस्था पर भी एक गहरा आघात लगा. इस रात में मूर्ति तस्करों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. जैन समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल भगवान महावीर की जन्मस्थली माना जाता है, पर अवस्थित भगवान महावीर की 26 सौ साल पुरानी कसौटी पत्थर से बनी अमूल्य मूर्ति को बंदूक की नोक पर तस्करों द्वारा ले जाया गया. जन्म स्थान के नाम से मशहूर खैरा थाना क्षेत्र के लछुआड़ के बीहड़ जंगलों एवं पहाड़ों के बीच में अवस्थित इस मूर्ति चोरी का मामला बहुत हाईप्रोफाइल था. लेकिन जैसे ही 06 दिसम्बर की अहले सुबह मूर्ति की बरामदगी हुई जैन समुदाय के साथ-साथ सभी लोगों को आस्था के पुनर्स्थापित होने का सुकून चेहरे पर साफ दिखलाई देने लगा. इसके साथ ही लगभग दस दिनों से चले आ रहे हाइवोल्टेज मामले का पटाक्षेप भी हो गया. मूर्ति चोरी की पूरी घटना पर गौर किया जाय तो 27 नवंबर की आधी रात से पहाड़ों के बीच स्थित जन्मकल्याणक मंदिर से महावीर की 26 सौ साल पुरानी ऐतिहासिक एवं कसौटी पत्थर से निर्मित तथा हीरा जड़ित नेत्रों वाली अमूल्य मूर्ति की चोरी अपराधियों ने कर ली. चोरी के उपरांत रात्रि प्रहरी ने इसकी सूचना लछुआड़ स्थित धर्मशाला के मैनेजर महेश्वर मिश्रा को दी. महेश्वर मिश्रा द्वारा इस घटना की तत्काल सूचना खैरा के थानाध्यक्ष तथा जमुई एसपी जयंतकांत को दी गयी. सूचना मिलते ही जिला कप्तान घटना स्थल पर पहुंच गये और पूरे क्षेत्र को सील करने का निर्देश दिया तथा स्वयं घटना स्थल पर पहुंच कर एसडीपीओ के साथ पूरे दल बल के साथ घटना के अनुसंधान में लग गये. जैन श्वेताम्बर सोसाइटी द्वारा खैरा थाने में चोरी से संबंधित मामला दर्ज कराया गया. जिसमें सात अज्ञात लोगों के घटना में शामिल होने की बात कही गयी. घटना की खबर जंगल की आग की तरह इतनी तेजी से फैली कि पूरे देश को इसने अपने आगोश में ले लिया. जैन समुदाय के लिए तो यह आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था, जिससे पूरा सम्प्रदाय अंदर से हिल गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर जोन के आईजी बच्चू सिंह मीणा घटना स्थल पर दूसरे दिन ही पहुंच जांच की गति को तीव्रता प्रदान करने में जुट गये. स्थानीय सांसद चिराग पासवान जैन समुदाय के एक शिष्ट मंडल के साथ देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उन्हें घटना से अवगत कराया.

चार दिनों तक मूर्ति बरामदगी में सफलता नहीं मिलने पर झारखंड के डीआईजी नवीन कुमार,मुंगेर डीआईजी शिवेश्वर शुक्ला एवं एसपी जयंतकांत ने एक संयुक्त बैठक में सर्च अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया. लेकिन 01 दिसम्बर को इस समय इस मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मूर्ति बरामदगी की जांच के अभियान को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की.

गृहमंत्री ने मामले को गंभीर बताया तथा मूर्ति बरामदगी का आश्वासन भी दिया. चार दिनों तक मूर्ति बरामदगी में सफलता नहीं मिलने पर झारखंड के डीआईजी नवीन कुमार,मुंगेर डीआईजी शिवेश्वर शुक्ला एवं एसपी जयंतकांत ने एक संयुक्त बैठक कर सर्च अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया. लेकिन 01 दिसम्बर को इस समय इस मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मूर्ति बरामदगी की जांच के अभियान को सीबीआई को सौपने की अनुशंसा की. अगले ही दिन सीबीआई डीआईजी ने घटना की पूरी जानकारी ली. इधर जिला पुलिस बल के साथ-साथ बिहार पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने दिन रात एक कर जंगलों के साथ-साथ तालाबों एवं होटलो में खाक छानते रहे लेकिन सफलता के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था. इसके साथ ही जन्म स्थान के आस-पास निवास करने वाली आदिवासी जनजातियों ने इस चोरी की घटना को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ते हुए सर्च अभियान में अपने आप को शामिल कर एक मिशाल पेश किया. चौतरफा बढ़ते दबिश एवं मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री के सीधे दखल के बाद अपराधियों को लगने लगा कि अब बच निकलना मुश्किल है और मूर्ति को फेंकने में ही तस्करों ने अपनी भलायी समझी. अंततः 06 दिसम्बर की अहले सुबह जब सिंकदरा प्रखंड के बिछवे गांव के तीन युवक मॉर्निग वॉक के लिए निकले तो उनकी नजर सड़क किनारे फेंकी गयी मूर्ति पर पड़ी. तत्काल इन युवकों ने इसकी सूचना स्थनीय लोगों और पुलिस को दी और दशवें दिन आस्था के इस सबसे बड़े हाईवोल्टेज चोरी के मामले का पटाक्षेप हो गया.

मूर्ति बरामदगी की सूचना मिलते ही जैन समुदाय में खुषी का ठिकाना ना रहा. साथ ही पुलिस महकमें ने राहत की सॉस ली. जॉच के क्रम में पुलिस को यह साक्ष्य मिला था की मुर्ति चोरी में आगरा के तस्करो का हाथ है. कहा जाता है कि इसी को आधार बनाकर पुलिस की एक टीम आगरा जाकर तस्करो पर दबिष बढाया. फलस्वरुप, दबाव में आकर मूर्ति को तस्करो ने स्वतः ही फेंक दिया. जो भी हो मूर्ति की बरामदगी को पुलिस अपनी एक बड़ी इपलब्धी मान रही है. मूर्ति बरामदगी के बाद लछुआड़ में प्रेस कांफ्रेस कर आईजी बच्चु सिंह मिणा ने कहा कि पुलिस के चौतरफा दबाव के कारण ही यह संभव हो पाया है. इन्होने कहा कि जल्द ही इस घटना में षामिल चोरो को गिरफतार कर मामले का इद्भेदन कर लिया जायेगा. मूर्ति बरामदगी की सूचना पाकर मुख्यमंत्री नीतीष कुमार ने इस अभियान में लगे सभी लोगो को धन्यवाद दिया. अंततः मूर्ति की बरामदगी के बाद भगवान महावीर की जन्मस्थली जो कभी क्षत्रियकुंड ग्राम के नाम से जाना जाता था, इजडने से बच गया. साथ ही अब इम्मीद जगी है कि इस घटना के बाद सरकार का ध्यान इस तरफ जायेगा, जिससे यह बेहतर तीर्थ स्थल के रुप में विकसित किया जा सकेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

ऐतिहासिक महल खंडहर में तब्दील

गीता कुमार

मुगलकाल में बनी बाबू बैरम सिंह का महल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है. जो स्पष्ट बयां कर रहा है कि जिले का ऐतिहासिक महल आज भी उपेक्षित है. यह महल खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर भरतखंड में स्थित है. यह महल अपने नाम के कारण तथा अपनी पौराणिकता के लिए प्रसिद्ध है. लेकिन इसके संरक्षण एवं जीर्णोद्धार की दिशा में प्रशासन और सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह महल वर्तमान में खंडहर में तब्दील हो गया है. महल अपने विशेष बनावट के कारण ही 52 कोठरी 53 द्वार के भी नाम से जाना जाता है. 52 कोठरी 53 द्वार के महल का संक्षिप्त इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है. मुगलकाल में ही तत्कालीन राजा बाबू बैरम सिंह के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था. स्थानीय समाज सेवी सह वरिष्ठ पत्रकार अनमोल सिंह एवं प्रभुनारायण पंडित के अनुसार इस महल के निर्माण में राख, चूना तथा सुरखी का प्रयोग किया गया था. महल के दरवाजे पर एक पत्थर का शिलापट्ट लगा था, जिस पर इस महल की निर्माण की तिथि अंकित थी. बताते है कि शिलापट्ट पर कारीगर द्वारा महल के कयामत तलक आबाद रहने की चर्चा की गई थी. कई अन्य सूत्रों की माने तो इस महल को बनाने वाले कारीगर बकराती खां नामक कारीगर थे. जिनके द्वारा अनेकों पौराणिक महल जैसे मुंगेर का किला, गोगरी का मस्जिद, भागलपुर जिला के नगरपारा के भव्य कुंए आदि का निर्माण किया गया था. महल के खंडहर होने के बाद अब तो इस शिलापट् की कोई निशानी भी नहीं रही. लेकिन आप अगर आज भी इस महल का भ्रमण करेंगे तो कुछ भागों में इस कारीगर के हाथों की नक्काशी किसी कोने में आशिंक रूप दिख जायेगी. जिसमें आप इसमें इकेरी की गई नक्काशी तथा कुछ फूल जैसी आकृति को देख कर आकर्षित हो जायेंगे.

महल के खंडहर होने के बाद अब तो इस शिलापट्ट की कोई निशानी भी नहीं रही. लेकिन आप अगर आज भी इस महल का भ्रमण करेंगे तो कुछ भागों में इस कारीगर के हाथों की नक्काशी किसी कोने में आशिंक रूप दिख जायेगी. जिसमें आप इसमें उकेरी की गई नक्काशी तथा कुछ फूल जैसी आकृति को देख कर आकर्षित हो जायेंगे. महल के बाहरी हिस्से में कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं. इस महल के ईंटो का आकार प्रकार भी आपको आकर्षित करेगा. क्योंकि इस महल में छोटी से छोटी तथा 2 फीट तक के ईंट का प्रयोग किया गया है.

महल के बाहरी हिस्से में कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं. इस महल के ईंटो का आकार प्रकार भी आपको आकर्षित करेगी. क्योंकि इस महल में छोटी से छोटी तथा 2 फीट तक के ईंट का प्रयोग किया गया है. वास्तव में आज यह ऐतिहासिक धरोहर लुप्त होने के कागार पर है. आज भी अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो इसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है तथा यह जिले का एक मात्र पर्यटन स्थल बन सकता है. जानकारी के अनुसार वर्षो पूर्व इस महल को लेकर एक प्रस्ताव भी पुरातत्व विभाग को भेजा गया था. परंतु इस ओर विभाग या सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई.

feedback@chauthiduniya.com

चम्पारण

जहां सैलाब आता है, तो बस्ती डूब जाती है...

अंतरराष्ट्रीय मुशायरा सह कवि सम्मेलन आयोजित

राकेश कुमार feedback@chauthiduniya.com

यूं ही नहीं पूर्वी चम्पारण को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है. 20 नवम्बर को दो दिवसीय मोतीझील महोत्सव का आयोजन हुआ. अभी मोतीझील महोत्सव की रंगीन यादों को जिलेवासी सहेज ही रहे थे कि 5 दिसम्बर को अखिल भारतीय मुशायरा सह कवि सम्मेलन का आयोजन नगर भवन के प्रांगण में सम्पन्न हुआ. यूं तो पूर्वी चम्पारण में सांस्कृतिक समारोहों की धूम सालों भर रहती है. चम्पारण सांस्कृतिक महोत्सव, चम्पारण महोत्सव, भोजपुरी महोत्सव, मोतीझील महोत्सव, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आदि कई बड़े मंच सजते हैं, जहां राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी कलात्मक प्रस्तुति दे चुके हैं. गजल के बादशाह जनाब गुलाम अली, चन्दन दास, सूफी गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन, भजन सम्राट अनूप जलोटा, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, गायक शब्बीर कुमार, विनोद राठौर आदि अनेक नामचीन कलाकार चम्पारण की सांस्कृतिक धरती पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. लगभग सभी ख्यातिलब्ध कवि और शायरों ने यहां भरपूर तालियां बटोरीं हैं.

चम्पारण की इसी सांस्कृतिक यात्रा की कड़ी में सर सैयद वेलफेयर फ्रंट के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय मुशायरा सह कवि सम्मेलन का आयोजन डॉ. राजेन्द्र नगर भवन के प्रांगण में किया गया. भव्य विशाल पंडाल में खचाखच भरे श्रोताओं के समक्ष मंच पर डॉ. कलीम कैसर, बिहार प्रार्थना गीत के रचयिता एमआर चिस्ती, फरहत एहसास, दर्जनों फिल्मों में गीत लिखने वाले शकील आजमी, नदीम फार्रुख, फलक सुल्तानपुरी, निकहत अमरोही, शाइस्ता जैसी नामचीन शायरों के साथ जाकिर हुसैन जाकिर, क्रेक बेतियाबी, गुलरेज शहजाद, तफजील अहमद, अख्तर सिद्दीकी, सबा अख्तर, एमएन अख्तर, डॉ. हातिम जावेद, कलीमुल्लाह कलीम, रूहुल हक हमदम जैसे ख्यातिलब्ध कवि व शायर विराजमान थे. सर्द हवाओं के बीच साहित्यकारों की पंक्तियां कभी आत्मचिंतन को मजबूर करतीं तो कभी शायरों के नज्मों ने इबादत और इश्क के रिश्तों का एहसास कराया. कवियों और शायरों ने सियासत की बहुरंगी विकृतियों पर भी खूब चोट किये. सबसे बड़ी बात ये रही कि मुशायरे में गंगा-जमुनी तहजीब का सुखद अनुभव श्रोताओं ने किया.

सियासत पर तंज कसते हुए सदरे मुशायरा डॉ. कलीम कैसर ने कहा-मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर, खुद तयमुम कर रहा है जो पजु के नाम पर/ ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर. वहीं फिल्मो को हीट गीतों से संवारने वाले शकील आजमी के शेर ने शमां बांध दिया. उन्होंने कहा कि-दर्द आराम बना जख्म को सीना आया, बड़ी मुश्किल से हमें जीना आया. सोहैल उस्मानी के शेर- सब उजाले हैं कैद महलों में, तुम उजाले कहां से लाओगे, ने समाज के विकृतियों पर कुठाराघात किया. बिहार गीत के रचयिता एमआर चिस्ती ने कलाम पढा कि- सुकूं हो धड़कनों के शोर से सांसों से फुर्सत हो/ जो मेरी रूह में रौशन तेरी शम्मे मुहब्बत हो. इश्क को इबादत बताते हुए शेख चम्पारणी ने कहा- जब तेरी आंखों की झीलों में तो मस्ती डूब जाती है/ जहां सैलाब आती है तो बस्ती डूब जाती है. आज के हाईटेक इश्क पर कटाक्ष करते हुए परवेज असरफ ने शेर पढ़ा कि- खुद को कसूरवार किया है तो रोईए/इस बेवफा से प्यार किया है तो रोईए.

समाज की विकृतियों और बेटियों के दर्द को बयां करते हुए निकहत अमरोही ने कहा- क्या करूं मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है/ जिस हथेली पर शादी की मेंहदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं. वहीं शाइस्ता ने मर्दो की फितरत को आईना दिखाते हुए कहा- चाहती हूं कुछ इसका रोक थाम हो जाए, वहशियों का हर पेशा अब तमाम हो जाए/ लड़कियां बुजुर्गो के पांव छूते डरती हैं, जाने कब कोई बूढ़ा आशाराम हो जाए. वहीं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए फलक सुल्तानपुरी ने कहा-दुश्मन से भी यारी है आज मुझे बीमारी है/नाज वो अदा के ऐसे तेवर प्यार हैं या मक्कारी है.. शेरों, नज्मों और गीतों के साथ रात जवां होती गई. तालियों की गड़गड़ाहट और कहकहों के बीच कब सुबह हुई किसी को पता हीं नहीं चला. मुशायरे की अध्यक्षता मोहिबुल हक ने किया जबकि संचालन नदीम फारूख ने किया. मुशायरा के दौरान हीं देश के कोने-कोने से आए हस्तियों ने उर्दू किताब दर्द मौसम का लोकार्पण किया. शायरों ने कहा कि यह पुस्तक उर्दू को और भी समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगी.■

महात्मा फूले की 126वीं पुण्यतिथि मनी

नसीम रब्बानी feedback@chauthiduniya.com

महात्मा फूले

मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के तत्वावधान में महुआ कोल्ड स्टोर स्थित कार्यालय के सभाकक्ष में 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, अछूतोद्धारक, नारी शिक्षा की जन्मदाता ज्योतिबा फूले की 126वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया. समारोह की अध्यक्षता नसीम रब्बानी एवं संचालन प्रो. सुधीर कुमार मालाकार ने की. समारोह को संबोधित करते हुये कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार सिंह, प्रो. अवधेश प्रसाद वर्मा, डॉ. संजय कुमार, डॉ. कुणाल मालाकार, रामइकबाल सहनी, शम्भू कुमार मालाकार, प्रो अभिषेक कुमार आदि ने महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महात्मा फूले ने शूद्र समझे जाने वाले श्रमिक समाज के लिए वर्ष 1868 में अपने घर का कुआं खोल दिया था. जब 1 जून 1873 को महात्मा फूले रचित गुलामगिरी पुस्तक का प्रकाशन हुआ तो रूढ़ीवादी व्यवस्था के पोषकों में खलबली मच गई. समाज को नयी दिशा देने के इरादे से 24 सितम्बर 1873 करे सत्यशोधक समाज की स्थापना की. जनप्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हुए समाज में फेले विषमता के खिलाफ बिगुल फूंका और नारियों को शिक्षित कर बालिकाओं के लिए बालिका पाठशाला की स्थापना की. इन्हीं समाजिक योगदान को देखते हुए 11 मई 1888 को एक विशाल आमसभा में इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई.

महात्मा फूले ने अपने अभियान को शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि कई पुस्तकों की रचना की. इन्होंने वर्ष 1863 में अपने घर में ही बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोला. इन दिनों विधवा विवाह की प्रथा पर रोक के कारण महिलाओं को काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी. इस दुर्दशा से बचाने के लिए अपने ही घर में आत्म सुरक्षा गृह का निर्माण कराया. विधवा महिलाओं को बाल काटने से रोकने के लिए इन्होंने नाइयों की हड़ताल भी संगठित कराई. वक्ताओं ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्त्री, शूद्र, अतिशूद्र के उत्पीड़न से बचाने के लिए समाज के सभी तबके के लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा अन्यथा समाज विखंडित हो जायेगा. महात्मा फूले की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब समाज के निचले पायदान पर बैठे लोगों का विकास होगा अन्यथा यह केवल औपचारिकता रह जायेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

बुद्ध के उपदेशों से ही विश्व शांति संभव : डॉ. फाहामा

सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आगे आना होगा और संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आतंकवाद के खात्मे के लिए युवाओं को प्रेरित करना होगा. उक्त बातें अमेरिका, भारत, थाईलैंड और लाओस में करीब एक सौ बौद्ध मठों की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु डॉ. फाहामा चन्दाफोन चक्कारों ने विशेष बातचीत में कही. बोधगया के कालचक्र मैदान में 11 वें अर्न्तराष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग में भाग लेने आये डॉ. फाहामा ने बोधगया स्थित बट लाओ इंटरनेशनल बौद्ध मठ में कहा कि पूरी दुनिया भर में गुमराह हो रहे युवकों को रास्ते पर लाने के लिए एक स्थायी कार्यक्रम चलाने की आवश्यता है. डॉ. फहामा ने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेश से ही विश्व में शांति लायी जा सकती है. वहीं चीवरदान करने के बाद विदेशी श्रद्धालुओं ने गरीबों के बीच गरम कपड़े व खाद्य सामग्री बांटे. इस कड़ी में बोधगया स्थित लाओस बौद्ध मठ परिसर में 130 गरीब परिवार की महिलाओं को कंबल व बच्चों को स्वेटर समेत खाद्य सामग्री दान दिये गये. दान लेने के लिए सैदपुर, हरली व मोटराटल समेत बोधगया के दूर-दराज गांवों की महिलाओं को बुलाया गया था. उक्त जानकारी बौद्धमठ के कर्मचारी संजय कुमार ने दी.

– सुनील सौरभ

एक नज़र

पुल निर्माण की मांग

जिले के अलौली प्रखंड के अन्तर्गत शिशवा ग्राम के समीप कमला नदी पर पुल बनाने की मांग तेज होने लगी है. इस संबंध में जिला जदयू की जिलाध्यक्ष साधना देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भेंट कर इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि अलौली प्रखंड में विकास की गाड़ी बढ़ाने के लिए फुलतोड़ा पुल की तरह ही शिशवा में पुल निर्माण करने के लिए कदम उठाये जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जायेगी. फरकिया के चप्पे-चप्पे में बिजली तथा पुल-पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत कराने की गुहार लगाई है.

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

सदर प्रखंड के हरदासचक ग्राम के मध्य विद्यालय में आर आर मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा अयोजित स्वतंत्रता सेनानी रामोतार सिंह के 8वें पुण्य तिथि समारोह के अवसर पर नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया.मौके पर किसान आयोग के अध्यक्ष सी पी सिन्हा ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी रामोतार शास्त्री और उनकी पत्नी के द्वारा अंग्रेजों के विरोध में जिस भूमिका का निर्वाहन किया गया उसे भुलाया नहीं जा सकता है. स्वत्रंता सेनानी माता पिता के पुत्र व पत्रकार चन्द्रशेखर मौके पर मौजूद थे. रालोसपा नेता पंकज कुशवाहा ने कहा कि उनके कृतित्व से हम प्रेरणा लेते हैं. युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सह जन अधिकार पार्टी के नागेन्द्र सिंह त्यागी ने कहा हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते. मौके पर बिन्देश्वर प्रसाद सिंह, कौशलेन्द्र प्रसाद वर्मा, डॉ. अरुण कुमार शांतनु, पंकज कुशवाहा, रमण कुमार सिंह, बिहार नगर ग्राम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सह वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार वर्मा, डॉ. रमण कुमार सिंह, डॉ. अरविन्द कुमार गुप्ता, मिडिया सॉफ्ट के सुधाकर सिंह आदि ने अपने विचार प्रकट किये. शिविर में आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा रोगियों की मुफ्त चिकित्सकीय जांच की गई और नि:शुल्क दवाई वितरित की गई. मौके पर अंशु, प्रिया, किरन, रानी सहित छात्र व शिक्षक मौजूद थे.■

भ्रष्टाचार का आरोप

वैशाली जिले के महुआ प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत भदवास है. पंचायत की तकरीबन सभी योजनायें यथा मनरेगा, बीआजीएफ, बारहवीं, तेरहवीं विकास योजना, कबीर अंत्येष्टि ,विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, सोलर लाइट, चापाकल, सड़क निर्माण, पुल-पुलिया का निर्माण, इन्दिरा आवास योजना आदि घोटालों की भेंट चढ़ गई हैं. उपरोक्त योजनाओं में चल रहे घोटालों के खिलाफ इसी पंचायत के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने महामहीम राष्ट्रपति को लिखे आवेदन में वर्तमान मुखिया सविता देवी की चर्चा करते हुए लिखा कि मुखिया बनने से पहले उनके पति साधारण लोग थे, पर आज गाड़ी ,बंगला सब कुछ हो गया. आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर ली है, जिसकी आयकर विभाग द्वारा जांच होनी चाहिए. ग्रामीण कैलाश राय, राजेश राय, अनंत साह, संजीव कुमार, शशि राय, नाथू चौधरी, गुड्डू, कमल राय, महिन्द्र राय आदी ने बताया कि यहां विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है केवल खानापूर्ति की गयी है. अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि पंचायत से संबंधित जानकारी पदाधिकारियों से मांग की है लेकीन पदाधिकारी उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने में आनाकानी कर रहे हैं. आने वाले समय मे देखना है कि महामहिम को लिखा गया आवेदन क्या गुल खिलाता है.■

–नसीम रब्बानी

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची
उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।
प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद
उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा
उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।
प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव
उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान
उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।
प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद
उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।
प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा
उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।
प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली
उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।
प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून
उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।
चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505
Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com
डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

इस नहर में कहीं-कहीं तो पांच-पांच फीट का सिल्ट का जमाव हो गया है. जबकि इन नहरों की गहराई 15 फीट है. बिहार विधान सभा चुनाव के पूर्व बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, कराकट के सांसद व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा, गया सांसद हरि मांझी, झारखण्ड पलामू के सांसद बीडी राम तथा चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना को गति देने के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मिले. इन सांसदों ने उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना पर वन मंत्रालय की ओर से लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग की.

बिहार-झारखण्ड की राजनीति मे फंसी

उत्तरी कोयल नहर परियोजना

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

बिहार और झारखण्ड के आधा दर्जन जिलों के लाखों किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली उत्तरी कोयल नहर परियोजना 45 वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है. 30 करोड़ की लागत वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना पर अब तक करीब आठ सौ करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन सवा लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई करने वाली इस परियोजना की नहर में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच सका है. पिछले चार दशक से यह राजनीति का केन्द्र बनी हुई है. इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले किसानों का दर्द उस समय से और बढ़ गया जब झारखण्ड बिहार से अलग हुआ. क्योंकि इस परियोजना से अधिकांश बिहार के किसानों को ही लाभ मिलना है. फलत: कुछ राजनीतिक कारणों से भी झारखण्ड सरकार ने इस परियोजना पर रुचि लेना बंद कर दिया. हालांकि इस परियोजना के पूरे हो जाने पर 24 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य था, जिससे झारखण्ड को ही फायदा होता. लेकिन आज यह परियोजना बिहार और झारखण्ड सरकारों के बीच राजनीतिक कारणों से अधर में लटकी हुई है. पिछले दिनों इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले बिहार-झारखंड के सम्बधित संसदीय क्षेत्र के सांसदों का एक शिष्टमंडल केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर इस परियोजना में तेजी लाने की अपील की थी.

1972 में पलामू जिले के उत्तरी कोयल नदी पर दो बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था विकसित करने की परियोजना बनाई गई थी. 1972 में इसे राज्य सरकार की मंजूरी मिली और प्राक्कलन राशि के रूप में 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई. 1975 में इस योजना का कार्य आरंभ हुआ. कोयल नदी पर पलामू जिले के मंडल के समीप कुटकु बांध का निर्माण होना था और इसके नीचे मोहम्मदगंज में बैराज का निर्माण करना था.

कुटकु बांध में 24 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र भी लगाया जाना था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण यह योजना सरकार के स्मृति पटल से ओझल होने लगा और इस परियोजना में लगे अधिकारियों की प्रवृत्ति लूट-खसोट तक ही सीमित होकर रह गई. नतीजा हुआ कि 1970 में 30 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुई इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना की लागत आज करीब दो हजार करोड़ हो गई है. अब तक इस योजना पर करीब साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये खर्च की जा चुकी हैं. लेकिन परिणाम शून्य है. इस योजना पर सबसे बड़ा ग्रहण तब लगा जबकि झारखण्ड बिहार से अलग हो गया. क्योंकि इस परियोजना के अन्तर्गत आने वाले बांध और डूब क्षेत्र झारखण्ड में है और लाभान्वित होने वाले क्षेत्र बिहार में है. हालांकि बाद में बिहार और झारखण्ड सरकारों के बीच इस परियोजना के लिए सचिव स्तर की वार्ता भी हुई. जिसमें तय हुआ कि झारखण्ड में पड़ने वाले बचे शेष कार्य के व्यय के अनुपात में लागत राशि का 13.38 फीसदी झारखण्ड सरकार वहन करेगी और 86.62 फीसदी बिहार सरकार. लेकिन इस फार्मूले पर भी इस परियोजना की बात आगे नही बढ़ पाई. 2007 में तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान व्याघ्र योजना के निदेशक ने टाइगर प्रोजेक्ट को कुटकु डैम से क्षति होने की बात कहते हुए डैम में जल संग्रहण पर रोक लगा दिया. वहीं दूसरी ओर उत्तरी कोयल नहर परियोजना के अन्तर्गत बने नहर की हालत अब खराब होती जा रही है. इस नहर में कहीं-कहीं तो पांच-पांच फीट का सिल्ट का जमाव हो गया है. जबकि इन नहरों की गहराई 15 फीट है. बिहार विधान सभा चुनाव के पूर्व बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, कराकट के सांसद व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा, गया सांसद हरि मांझी, झारखण्ड पलामू के सांसद बीडी राम तथा चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना को गति देने के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से मिले. इन सांसदों ने उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना पर वन मंत्रालय की ओर से लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग की. तब केन्द्रीय वन व पार्यावरण मंत्री ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया था. फिलहाल इस सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले गया, औरंगाबाद, पलामू जिले के लाखों किसान निराश हैं. इस सिंचाई योजना से करीब सवा लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की संभावना थी.■

ऐतिहासिक लक्ष्मणा नदी को है तारणहार की तलाश

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जमीनी कार्य को गति देना शुरू किया. जानकारों की मानें तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का आलम रहा कि उक्त अभियान में भारतीय क्षेत्र के अलावा कुछ नेपाल के सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी दी.

वाल्मीकि कुमार feedback@chauthiduniya.com

नेपाल के तराई से होकर भारतीय क्षेत्र में सीतामढ़ी के बीच से प्रवाहित होने वाली लक्ष्मणा नदी का प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व रहा है. नदी की धारा की दिशा में बदलाव के कारण इसका नक्शा बदलता रहा है. लेकिन इसकी महत्ता कभी नहीं बदली. जिले का चर्चित हलेश्वर स्थान शिवलिंग के संबंध में चर्चा है कि कभी देवी - देवता लक्ष्मणा नदी से लेकर मंदिर तक बने कंदरा मार्ग से महादेव का अभिषेक करने जाया करते थे. इस तथ्य का प्रमाण के तौर पर प्रचीन कंदरा हाल के दशक तक मौजूद था, जिसे हलेश्वर स्थान मंदिर के जिर्णोद्धार काल में तत्कालीन डीएम अरुण भूषण प्रसाद ने सुरक्षा कारणों से बंद करा दिया. पिछले तकरीबन एक दशक से इस नदी की स्थिति काफी दयनीय बनी है. दिशा परिवर्तन के कारण नदी की धारा से जल प्रवाह अवरुद्ध है. नतीजतन शहर के मध्य से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी महज एक नाला बन कर रह गयी है. शहर के कुल 28 वार्डो के नाले का पानी ही नदी के बीच जमा है. नतीजतन नदी का पानी काला पड़ गया है. अब तो पशुओं को भी लोग नदी का पानी पिलाने से परहेज करने लगे हैं. पर्व -त्योहार के मौके पर जहां लक्ष्मणा नदी के पावन तट पर हजारों की भीड़ हुआ करती थी, अब महज चंद लोग ही आ पा रहे हैं. सूर्योपासना का महापर्व छठ हो अथवा दुर्गा पूजा का अवसर. प्रशासनिक स्तर पर नदी के पानी की सफाई को लेकर कसरत तो की जाती है. परंतु इसके स्थायी निदान की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाया जाता है. नतीजा है कि शहरी क्षेत्र के अलावा आस-पास के क्षेत्र के लोग छठ पर्व भी अपने दरवाजे पर ही अब करने में भलाई समझने लगे हैं. दूसरी ओर साधु संत व आम लोगों ने भी नदी में स्नान करना छोड़ दिया है. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पिछले दिनों तो कई स्थानों पर श्रद्धालु जलकुंभी से भरी नदी की धारा की पूजा-अर्चना कर लौट गए.

बता दें कि नदी की जल धारा की उड़ाही को लेकर पूर्व में रुन्नीसैदपुर की तत्कालीन जदयू विधायक गुड्डी देवी ने विधान सभा में तारांकित प्रश्न के दौरान इक्त मामला को उठाने का कार्य किया था. उन्होंने नदी की जल धारा की उड़ाही को लेकर जब सवाल किया था तो सूबे के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना जवाब भेजा था. जिसमें बताया गया था कि नेपाल के फूलपरासी से भारत-नेपाल सीमा तक तकरीबन 8 किलो मीटर एवं भारतीय सीमा से सटे दुलारपुर ग्राम से पोसुआ पटनिया तक लगभग 15 किलो मीटर यानि कुल 23 किलो मीटर की लंबाई में नदी की धारा सिल्टेड है. जिसके कारण नदी अपनी धारा बदल कर अघवारा समूह की नदियों में मिल गयी है. यह भी बताया गया था कि भारतीय भू-भाग में नदी के धारा की उड़ाही से नदी में पानी का बहाव संभव नही है. नेपाली भू-भाग से नदी के धारा की उड़ाही कराने पर ही जल प्रवाह संभव है. मामला अंतराष्ट्रीय होने के कारण भारत-नेपाल जल प्लावन समिति में प्रक्रियाधीन है. नदी की दुर्दशा पर रोष का इजहार करते हुए पूर्व में सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में विजयादशमी के अवसर पर लखनदेई नदी में विरोध स्वरूप रावण दहन का भी आयोजन किया गया था. तब कई अन्य संगठनों ने भी आंदोलन में अपनी भागीदारी देकर सरकारी व प्रशासनिक तंत्र की निद्रा तोड़ने का प्रयास किया था. परंतु समय गुजरने के साथ ही आंदोलन तो पूर्व की भांति गुम हो ही गया. प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक चैन की सांस लेने लगे. जबकि नदी के काला पड़ चुका पानी से निकल रही असहनीय गंध अब शहर में संक्रामक रोगों के फैलाव का संकेत भी देने लगी है.

हाल के साल में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जमीनी कार्य को गति देना शुरू किया. जानकारों की मानें तो कार्यकर्ताओं की मेहनत का आलम रहा कि उक्त अभियान में भारतीय क्षेत्र के अलावा कुछ नेपाल के सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी भागीदारी दी. पूर्व में अभियान चलाने वाले लोक चेतना समिति के डॉ. बसंत कुमार मिश्रा, संघर्ष यात्रा के शशि शेखर, मनोज कुमार शक्ति, शाहीन परवीन, नरोत्तम व्यास व शत्रुघ्न साहू सरीखे कार्यकर्ताओं ने नदी की दुर्दशा के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं वर्तमान में पत्रकार सुबोध कुमार, इतिहासकार रामशरण अग्रवाल, साहित्यकार

आशा प्रभात, डॉ. आनंद किशोर, डॉ केएन गुप्ता, सज्जन हिसारिया, मनोज बैठा, डॉ. राज कुमार गुप्ता, जागेश्वर मुखिया, पूर्व प्रमुख संजय कुमार, कमर अख्तर, मो. ग्यासुद्दीन, नेपाल के जंगीलाल यादव व महेंद्र यादव समेत अन्य नदी की धारा में जल प्रवाह को लेकर लगातार प्रयासरत है. हाल ही में जिला पदाधिकारी राजीव रौषन के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक बैठक पर समस्या निदान की राह तलाशने को लेकर विचार विमर्श किया. बताया जाता है कि वर्तमान में नेपाल में जारी मधेसी आंदोलन के कारण उक्त दिषा में फिलहाल कार्य करना मुश्किल हो गया है. संभव है कि भारतीय क्षेत्र को तत्काल कार्य स्थल बना कर धारा को जीवंत बनाने का प्रयास किया जायेगा. दूसरी ओर पावन रही लक्ष्मणा नदी की एक अदद तारण हार की तलाश कब तक पूरी हो पाती है इस पर आम लोगों की नजर टिकी है. इतना तो तय है कि अगर शीघ्र इस दिशा में सार्थक पहल नहीं की गयी तो नदी के अस्तित्व को भी बचाना मुश्किल हो जायेगा. साथ ही इसके कुप्रभाव का खामियाजा भुगतने के लिए सभी को तैयार रहना होगा.■

मामला अंतराष्ट्रीय होने के कारण भारत-नेपाल जल प्लावन समिति में प्रक्रियाधीन है. नदी की दुर्दशा पर रोष का इजहार करते हुए पूर्व में सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में विजयादशमी के अवसर पर लखनदेई नदी में विरोध स्वरूप रावण दहन का भी आयोजन किया गया था. तब कई अन्य संगठनों ने भी आंदोलन में अपनी भागीदारी देकर सरकारी व प्रशासनिक तंत्र की निद्रा तोड़ने का प्रयास किया था. परंतु समय गुजरने के साथ ही आंदोलन तो पूर्व की भांति गुम हो ही गया.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

21 दिसंबर–27 दिसंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश के 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद भी राहत से वंचित

बाबू गलियारे में भटक रही राहत की फाइल

> उत्तर प्रदेश में सूखे की हालत को हम बुंदेलखंड के झरोखे से देखते चलें और इससे प्रदेशभर के किसानों की बदहाली का अंदाजा लगाते चलें. बुंदेलखंड का जब सर्वे कराया गया, तब यह तस्वीर उभर कर सामने आई कि आठ महीनों के दरम्यान 53 प्रतिशत परिवारों ने दाल नहीं खाई थी. बुंदेलखंड के 69 प्रतिशत लोगों ने दूध नहीं पिया था और हर पांचवां परिवार कम से कम एक दिन भूखे ही सोने पर विवश हुआ था. बुंदेलखंड के 38 प्रतिशत गांवों से भुखमरी से हुई मौतों की रिपोर्ट आई. मार्च महीने के बाद से 60 प्रतिशत परिवारों में गेहूं चावल की जगह मोटे अनाज और आलू का प्रयोग हुआ और हर छठे घर ने फिकारा (घास की रोटी) खाकर पेट भरा.

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की औपचारिकता तो पूरी कर दी, लेकिन सूखे से त्रस्त किसानों को त्वरित राहत देने का कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है. सूखा और राहत का मसला भी अन्य सरकारी फाइलों की तरह राज्य और केंद्र सरकार के बाबू–गलियारे में भटक रहा है. बुंदेलखंड की स्थिति और भी नाजुक हो रही है. योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान के जिस सर्वेक्षण के आधार पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने का मन बनाया, उस सर्वे रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, तो बुंदेलखंड की हालत पर रोना आएगा. सूखाग्रस्त घोषित करने की औपचारिकता एक राजनीतिक चलन या परम्परा जैसी होती जा रही है. घोषणा के बाद सरकार इसके प्रतिफलन में कोई रुचि नहीं दिखाती. पिछले साल भी उत्तर प्रदेश के 44 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे, लेकिन किसानों को क्या मिला, इसके बारे में प्रदेश ही क्या पूरे देश को इसकी जानकारी है.

उत्तर प्रदेश में सूखे की हालत को हम बुंदेलखंड के झरोखे से देखते चलें और इससे प्रदेशभर के किसानों की बदहाली का अंदाजा लगाते चलें. बुंदेलखंड का जब सर्वे कराया गया, तब यह तस्वीर उभर कर सामने आई कि आठ महीनों के दरम्यान 53 प्रतिशत परिवारों ने दाल नहीं खाई थी. बुंदेलखंड के 69 प्रतिशत लोगों ने दूध नहीं पिया था और हर पांचवां परिवार कम से कम एक दिन भूखे ही सोने पर विवश हुआ था. बुंदेलखंड के 38 प्रतिशत गांवों से भुखमरी से हुई मौतों की रिपोर्ट आई. मार्च महीने के बाद से 60 प्रतिशत परिवारों में गेहूं चावल की जगह मोटे अनाज और आलू का प्रयोग हुआ और हर छठे घर ने फिकारा (घास की रोटी) खाकर पेट भरा. अब तक 40 प्रतिशत परिवारों ने अपने पालतू पशु बेच डाले और 27 प्रतिशत लोगों ने अपनी जमीनें बेच डालीं या गिरवी रख दीं. 36 प्रतिशत गांवों में सैकड़ों गायें, भैंसें चारे की कमी के कारण लावारिस छोड़ दी गईं. स्वराज अभियान ने बुंदेलखंड की सभी 27 तहसीलों के 108 गांवों का सर्वेक्षण किया था. दशहरा और दिवाली के बीच हुए इस सर्वे में स्वराज अभियान और बुंदेलखंड आपदा राहत मंच के कार्यकर्ताओं ने गांव–गांव जाकर सूखे के असर का जायजा लिया था. योगेन्द्र यादव, अर्थशास्त्री ज्यांद्रेज, रीतिका खेड़ा और बुंदेलखंड की परमार्थ संस्था के संजय सिंह के निर्देशन में सर्वेक्षण हुआ.

सर्वेक्षण के मुताबिक बुंदेलखंड में खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो गई है. ज्वार बाजरा मूंग और सोयाबीन उगाने वाले 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने फसल बर्बादी की रपट दी. अरहर और उड़द में यह प्रतिशत कुछ कम था. केवल तिल की फसल ही कुछ बच पाई. वहां भी 61 प्रतिशत किसानों ने फसल बर्बादी का जिक्र किया. सूखे के चलते पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है. दो तिहाई गांव में पिछले साल की तुलना में घरेलू काम के पानी की कमी आई है, आधे से अधिक गांव में पानी पहले से अधिक प्रदूषित हुआ है. दो तिहाई गांव से पानी के लिए हिंसक झगड़े की खबर है. पानी का मुख्य स्त्रोत हैंड–पम्प है. लेकिन सरकारी हैंड–पम्पों में कोई एक तिहाई बेकार पड़े हैं.

सर्वेक्षण के सबसे चिंताजनक संकेत भुखमरी और कुपोषण से सम्बधित हैं. पिछले कुछ महीने के खान–पान के बारे में पूछने पर पता लगा कि एक औसत परिवार को महीने में सिर्फ 13 दिन सब्जी खाने को मिली, परिवार में बच्चों या बड़ों को दूध सिर्फ छह दिन नसीब हुआ और दाल सिर्फ चार दिन मिली. गरीब परिवारों में आधे से ज्यादा ने पूरे महीने में एक बार भी दाल नहीं खाई थी और 69 प्रतिशत ने दूध नहीं पिया था. गरीब परिवारों में 19 प्रतिशत को पिछले माह कम से कम एक दिन भूखे ही सोना पड़ा. कुपोषण और भुखमरी की स्थिति रबी की फसल खराब होने से बिगड़ी है. सिर्फ गरीब ही नहीं, लगभग सभी सामान्य परिवारों में भी दाल और दूध का उपयोग घट गया है. यहां के 79 प्रतिशत परिवार पिछले कुछ महीनों में कभी न कभी रोटी या चावल को सिर्फ नमक या चटनी के साथ खाने को मजबूर हुए हैं. 17 प्रतिशत परिवारों ने घास की रोटी (फिकारा) खाने की बात भी कही. सर्वे के 108 में से 41 गावों में भुखमरी या कुपोषण से मौत की रपट भी आई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. इस सर्वेक्षण में कई ऐसे भी त्रासद तथ्य सामने आए, जो लोगों का दिल दहलाने के लिए काफी है. एक तिहाई से अधिक परिवारों को खाना मांग कर खाना पड़ा. 22 प्रतिशत बच्चों को स्कूल से नाम कटवाना पड़ा, 27 प्रतिशत को ज़मीन और 24 प्रतिशत को जेवर बेचने या गिरवी रखने पड़े हैं. जानवरों के लिए तो भुखमरी और अकाल की स्थिति है. बुंदेलखंड में दुधारू जानवरों को छोड़ने की अन्ना प्रथा में अचानक बढ़ोत्तरी आई है. सर्वे में 48 प्रतिशत गावों में भुखमरी से 10 या अधिक जानवरों के मरने की खबर मिली. वहां 36 प्रतिशत गावों में कम से कम सौ गाय–भैंसों को चारे के अभाव में लावारिस छोड़ दिया गया. जानवरों के चारे में कमी की बात 77 प्रतिशत परिवारों ने कही, तो 88 प्रतिशत परिवारों ने दूध कम होने की रपट दी. मजबूरी में 40 प्रतिशत परिवारों को अपना पशु बेचना पड़ा है. पशुधन की कीमत भी काफी नीचे गिर गई है. हालात चिंताजनक हैं. एक औसत गरीब परिवार को पिछले आठ महीनों में मनरेगा से 10 दिन की मज़दूरी भी नहीं मिली है. सरकारी राशन की स्थिति भी असंतोषजनक है. गरीब परिवारों में आधे से भी कम (केवल 42 प्रतिशत के पास) बीपीएल या अंत्योदय कार्ड है. लब्बोलुबाव यह है कि सूखा विकराल रूप धारण करता जा रहा है. फसलों के नुकसान, पानी की कमी और रोज़गार के अवसरों की कमी का असर अब सीधे तौर पर इंसान और पशुओं के खाने पर दिखाई पड़ने लगा है. सर्वेक्षण ने बताया कि बुन्देलखंड के गरीब परिवारों में भुखमरी की नौबत आ सकती है. बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ा है. इस साल ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण रबी की फसल भी नष्ट हो गई थी. इस संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार और प्रशासन ने कुछ नहीं किया और किसानों तक राहत पहुंचाने में सरकार फेल साबित हुई.

प्रदेश के किसानों को अंदेशा है कि जिस तरह पिछली प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत दी गई, वैसा ही इस बार भी हुआ, तो किसानों के सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. उत्तर प्रदेश में लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है जब बारिश, ओलावृष्टि या सुखाड़ के चलते किसानों को फसल की बर्बादी देखनी पड़ी और भारी नुकसान उठाना पड़ा. केंद्रीय मौसम विभाग ने काफी पहले ही आधे देश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सोई रही, जबकि कई अन्य राज्यों ने पहले ही अपने प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत की गेंद केंद्र के पाले में डाल दी. नियमानुसार जब तक राज्य सरकार किसी इलाके को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करती और केंद्र नुकसान का जायजा नहीं ले लेता, तब तक वहां राहत कार्य शुरू नहीं हो सकते. इस देरी का खामियाजा उत्तर प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र सूखे का शिकार बना है. देश में इस बार सबसे ज्यादा सूखा उत्तर प्रदेश में ही पड़ा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

50 जिले सूखाग्रस्त घोषित, पर केंद्र से नहीं मांगी मदद

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 50 ज़िलों को सूखाग्रस्त तो घोषित कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मांगी. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की सूखे में जल्द राहत पहुंचाने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सूखे जैसी परिस्थितियां होने के बाद भी उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड जैसे राज्यों ने केंद्र से किसी राहत राशि की मांग नहीं की है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 18 नवंबर को यूपी के 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश ने घोषणा के बावजूद केंद्र को अभी तक कोई सूचना नहीं दी है. मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक ने समय पर सूचना दे दी थी, जिस पर उसे 1541 करोड़ रुपये की राहत राशि उपलब्ध कराई गई. इसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश ने भी सूखे से निपटने के लिए केंद्र की मदद मांगी, इसके बाद वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम भेजी गई थी. सरकारी प्रावधान है कि राज्य से रिपोर्ट आने के बाद केंद्र की कृषि, सिंचाई, खाद्य और वित्त विभागों की टीम प्रभावित जिलों में सूखे का आकलन करने आती है और सर्वेक्षण के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट देती है. उसके बाद ही केंद्र सरकार रिपोर्ट के आधार पर सहायता के बारे में कोई निर्णय लेती है. ■

सियासी आरोप-प्रत्यारोप में मरता तो किसान ही है!

पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया था. तब यूपी सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी थी, लेकिन तब भी राज्य और केंद्र के आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच किसानों की राहत फंसी रह गई थी. तब यूपी सरकार ने केंद्र से छह हजार करोड़ रुपये मांगे थे. पर, उत्तर प्रदेश सरकार की इस मांग पर केंद्र सरकार ने कहा था कि मांग भेजने में प्रदेश सरकार ने अत्यधिक देरी कर दी है. ऐसा कह कर केंद्र ने उत्तर प्रदेश सरकार की मांग को विलम्बित राग में डाल दिया था. केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर किसानों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था. केंद्र ने कहा था कि कृषि विकास के लिए राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से 565 करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया गया था, यूपी सरकार उसमें से मात्र 334 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई थी. ■

मूल पहचान और जनसंख्या अनुपात के साथ

पहली बार पंचायत प्रमुख बनेंगे उपेक्षित आदिवासी

शिव दास प्रजापति

उत्तर प्रदेश में गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईया, भुनिया जैसी आदिवासी जातियों के सैकड़ों लोग देश की आजादी के करीब 68 सालों में पहली बार मूल पहचान और आबादी के अनुपात में त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रमुख बनेंगे. जबकि कोल, कोरबा, मझवार, उरांव, मलार, बादी, कंवर, कंवराई, वनवासी सरीखी आदिम जातियों को अपनी मूल पहचान पर यह अधिकार हासिल करने के लिए अभी और संघर्ष करना होगा.

सूबे में गौतमबुद्धनगर जिले को छोड़कर सभी 74 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं. अगर सूबे की 59,163 ग्राम पंचायतों की बात करें, तो इनमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 336 ग्राम प्रधान पदों पर गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईया, भुनिया जैसी आदिवासी जातियों के हजारों लोग आजाद भारत में पहली बार अपनी मूल पहचान के साथ आरक्षित सीटों पर ताल ठोंक रहे हैं. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2010 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ग्राम प्रधान की केवल 76 सीटें आरक्षित थीं, जो भोटिया, भुक्सा, जऊसारी, रांजी और थारू आदिवासी जातियों की आबादी (0.03 प्रतिशत) के आधार पर तय की गई थीं. त्रिस्तरीय पंचायत-2015 में पहली बार उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल सभी जातियों की आबादी के आधार पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लॉक प्रमुख) और क्षेत्र पंचायत सदस्य का पद आरक्षित किया गया है. इस बार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ब्लॉक प्रमुख के पांच पद आरक्षित किए गए हैं, जो पहले एक था. इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य के 7,45,475 पदों पर हजारों की संख्या में आदिवासी अपने गांव के विकास की रूपरेखा तय करेंगे. सूबे के 821 विकास खंडों की बात करें, तो इनमें से पांच ब्लॉक प्रमुखों के पदों पर उक्त आदिवासी जातियों के लोग दांव खेल रहे हैं. करीब 77,576 क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) में से हजारों की संख्या में उक्त आदिवासी जातियों के लोग ब्लॉक प्रमुखों के चयन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय करेंगे. इनमें से 191 तो केवल सोनभद्र से हैं. यहां तो विकास खण्डों दुद्धी और बभनी के प्रमुखों का ताज उक्त जातियों में किन्हीं दो व्यक्तियों के सिर सजेगा. हालांकि सूबे की आबादी में करीब 0.568 प्रतिशत (जनगणना-2011 के अनुसार 11,34,273) हिस्सेदारी रखने वाला अनुसूचित जनजाति वर्ग के सिर पर अपनी मूल पहचान के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का ताज नहीं सज सकेगा, क्योंकि सूबे के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में से उनके लिए एक भी आरक्षित नहीं है. इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव और क्षेत्र के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सूबे के 3,112 जिला पंचायत सदस्य पदों में से दर्जनों पर इसी जाति वर्ग के लोग चुने गए हैं जिनमें सात अकेले सोनभद्र से हैं. आगामी 13 और 14 दिसंबर को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव के परिणामों की घोषणा के साथ जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चयन की कवायद शुरू हो जाएगी. इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों में सूबे की उक्त आदिवासी जातियों का प्रतिनिधित्व अपनी मूल पहचान के साथ सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसके अभाव में सोनभद्र के आदिवासी बहुल करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का गठन पिछले डेढ़ दशक से नहीं हो पा रहा था. इन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य हो गई थी.

जनगणना-2011: उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले पांच जिले

क्रमांक	जनपद	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
1.	सोनभद्र	3,85,018	20.67
2.	बलिया	1,10,114	3.40
3.	देवरिया	1,09,894	3.54
4.	कुशीनगर	80,269	2.25
5.	ललितपुर	71,610	5.86

दुद्धी विकास खंड का जाबर, नगवां विकास खंड का रामपुर, बेजनाथ, दरेव एवं पल्हारी ग्राम सभाएं इसका उदाहरण हैं. यहां 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त दावेदारी नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत सदस्यों की दो तिहाई सीटें खाली रह जाती थीं. इन ग्राम सभाओं का गठन नहीं हो पाता था, क्योंकि ग्राम सभा के गठन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या दो तिहाई होना जरूरी होता है. इन ग्राम सभाओं में जिला प्रशासन द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है. अब ये समस्याएं दूर हो जाएंगी.

उदाहरण के तौर पर नगवां विकासखंड का पल्हारी ग्राम सभा. 13 ग्राम पंचायत सदस्यों वाले पल्हारी ग्राम सभा में पंचायत चुनाव-2005 के दौरान कुल 1006 वोटर थे. इस गांव में अनुसूचित जाति का एक परिवार था. शेष अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के थे. अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 ग्राम पंचायत सदस्य के पद खाली थे, क्योंकि इस पर अनुसूचित जाति का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ सका था. ग्राम पंचायत सदस्यों के दो-तिहाई से अधिक पद खाली होने के कारण पल्हारी ग्राम सभा का गठन नहीं हो पाया. जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति विकास कार्यों को अंजाम दे रही थी. कुछ ऐसे ही हालात पंचायत चुनाव-2010 में भी वहां थे. इससे छुटकारा पाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ गैर राजनीतिक पार्टियां भी आदिवासियों की आवाज को सत्ता के नुमाइंदों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रही हैं. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2005 के दौरान भी आदिवासियों और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाजें मुखर की थी.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने उस समय आदिवासियों की इस आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए म्योरपुर विकासखंड के करहिया गांव में पंचायत चुनाव के दौरान समानान्तर बूथ लगाकर आदिवासियों से मतदान करवाया था. भाकपा(माले) के इस अभियान में 500 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया. वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान लगाए गए बूथ पर मात्र 13 वोट पड़े थे. अनुसूचित जाति के दो परिवारों (दयाद) के सदस्यों में से एक व्यक्ति नौ वोट पाकर ग्राम प्रधान चुना गया. शेष सदस्य निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए थे. आदिवासियों और भाकपा(माले) के इस अभियान ने राजनीतिक हलके में हडकंप मचाकर रख दी. इसके बाद भी केंद्र एवं राज्य की सरकार की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. इसके बाद भी सूबे की सरकार ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों, विधानमंडल और संसद में आदिवासियों की आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित कराने की पहल नहीं की.

आदिवासियों की गैर-सरकारी संस्था प्रदेशीय जनजाति विकास मंच और आदिवासी विकास समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों में उचित प्रतिनिधित्व के संवैधानिक

(शेष पृष्ठ 19 पर)

वोट-बैंक की राजनीति में उलझा आदिवासियों का मूल अधिकार

समाज के निचले पायदान पर जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों के संवैधानिक और मूलाधिकार को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा उदासीन रही हैं. उन्होंने उन्हें केवल वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें उनका हक देने में हमेशा पीछे रहीं हैं. इसमें कांग्रेस की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है. उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली विभिन्न आदिवासी जातियों कांग्रेस के शासनकाल में संसद से पास हुए अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) कानून-1967 के लागू होने के समय से ही खुद को ठगा महसूस कर रही हैं. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश के सबसे निचले तबके यानी आदिवासियों पर यह कानून जबरन थोप दिया था. इसकी वजह से वे आज तक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं. इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश की पांच आदिवासी जातियों (भोटिया, भुक्सा, जन्नसारी, रांजी और थारू) को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया, लेकिन कोल, कोरबा, मझवार, उरांव, मलार, बादी, कंवर, कंवराई, गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईया, भुनिया आदि आदिवासी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में ही रहने दिया गया. जबकि इन जातियों की सामाजिक स्थिति आज भी उक्त पांच आदिवासी जातियों के समान है. इन जातियों ने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी. उत्तर प्रदेश की सत्तासीन राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक की गणित के हिसाब से अपना-अपना जाल बुना और उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल की, लेकिन उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा. केंद्र की सत्ता काबिज भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने वर्ष 2002 में संसद में संविधान संशोधन का निर्णय लिया. इसमें उसके नुमाइंदों की सत्ता में बने रहने की लालच भी थी. तत्कालीन राजग सरकार ने उत्तर प्रदेश की गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईया, भुनिया आदिवासी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की कवायद शुरू की. इसी क्रम में उसने संसद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आज्ञा (सुधार) विधेयक-2002 पेश किया. संसद ने इसे पारित कर दिया. हालांकि सियासी पृष्ठभूमि में इस कानून में कुछ विशेष जिलों के आदिवासियों को ही शामिल किया गया था. इस वजह से आदिवासी बहुल चंदौली जिले के इन जातियों के लोग आज भी अनुसूचित जाति वर्ग में ही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सत्ता को पहली बार इस जिले से नक्सलवाद का लाल सलाम हिंसा के रूप में मिला. फिलहाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आज्ञा (सुधार) अधिनियम-2002 के संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे अधिसूचित कर दिया. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने 8 जनवरी 2003 को भारत सरकार का राजपत्र (भाग-2, खंड-1) जारी किया. इसके तहत गोंड़ (राजगोंड़, धूरिया, पठारी, नायक और ओझा) जाति को उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में अनुसूचित जाति वर्ग को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर दिया गया. साथ में खरवार, खैरवार को देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में, सहरिया को ललितपुर में, परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुईया, भुनिया को सोनभद्र में, पंखा, पनिका को सोनभद्र और मिर्जापुर में एवं चेरो को सोनभद्र और वाराणसी में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आज्ञा(सुधार) अधिनियम-2002 कानून ने एक बार फिर आदिवासी समुदाय के दुखते रग पर हाथ रख दिया. इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल हुआ आदिवासी समुदाय सत्ता में अपने भागीदारी के संवैधानिक अधिकार से ही वंचित हो गया. इस कानून के लागू होने से वे त्रिस्तरीय पंचायतों, विधानमंडलों और संसद में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व करने से ही वंचित हो गए, क्योंकि राज्य में उनकी आबादी बढ़ने के अनुपात में इन सदनों में उनके लिए सीटें आरक्षित नहीं की गईं. 3 मई, 2002 से 29 अगस्त, 2003 तक राज्य की सत्ता में तीसरी बार काबिज रही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी आदिवासियों के जनप्रतिनिधित्व अधिकार की अनदेखी की. मायावती अनुसूचित जाति वर्ग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल हुई आदिवासियों की संख्या का रैपिड सर्वे कराकर उनके लिए विभिन्न सदनों में आबादी के आधार पर सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार, परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग को भेज सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने इन विसंगतियों के साथ कानून को राज्य में लागू कर दिया. इससे एक बार फिर आदिवासियों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार कानूनी और सियासी पचड़े में उलझ गया. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की अगुआई में 29 अगस्त, 2003 को राज्य में सपा की सरकार बनी. तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री और दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से करीब 27 साल तक विधायक रहे विजय सिंह गोंड़ त्रिस्तरीय पंचायतों समेत विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने से वंचित हो गए. उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई. दूसरी तरफ आदिवासी बहुल सोनभद्र के आदिवासियों में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ी और वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कूंच कर गए, लेकिन 2004 में सत्ता में आई कांग्रेस की अगुआई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यानी यूपीए और 13 मई, 2007 में राज्य की सत्ता में आई मायावती सरकार ने उनकी आवाज को एक बार फिर नजर अंदाज कर दिया. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का आदिवासी समुदाय अपने हक के लिए जिला प्रशासन से लेकर उच्चतम न्यायालय तक अपनी आवाज पहुंचाता रहा. मौके की नजाकत को भांपते हुए पूर्व विधायक विजय सिंह गोंड़ ने कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया. उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि भी तैयार कर ली. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे विजय प्रताप की ओर से 2011 के आखिरी महीने में उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका संख्या-540/2011 दाखिल करवाई. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आदिवासियों के हक में रिपोर्ट दी. उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश को तलब किया. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 10 जनवरी, 2012 को आदिवासियों के हक में फैसला दिया. हालांकि उसने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने और सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया में तीन महीने का समय लगने की वजह से उस समय आदिवासियों के हक में सीटें आरक्षित करने से इंकार कर दिया. अब निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विधानसभा की दो सीटें दुद्धी और ओबरा आरक्षित कर दी हैं. ■

आदिवासी पहचान के लिए जूझ रही सूबे की कोल, कोरबा, मझवार, उरांव, मलार, बादी, कंवर, कंवराई, वनवासी सरीखी जातियों को अपनी मूल पहचान पर यह अधिकार हासिल करने के लिए अभी और संघर्ष करना होगा, क्योंकि राजनीतिक गुणा-भाग में जुटे सियासतदानों ने उन्हें अभी भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में बनाए रखा है, जबकि इन जातियों की सामाजिक स्थिति भी इन जिलों में अन्य जनजातियों के समान ही है. अगर हम इनके संवैधानिक अधिकारों पर गौर करें, तो कोल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, कोरबा बिहार, मध्य प्रदेश एवं पशिचम बंगाल में, कंवर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मझवार मध्य प्रदेश में, धांगड़ (उरांव) मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, बादी (बर्दा) गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में हैं.

उत्तराखंड विकास के पथ पर बढ़ रहा है : हरीश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से प्रदेश की समस्याओं और विभिन्न मुद्दों पर चौथी दुनिया के संवाददाता राजकुमार शर्मा ने बातचीत की. पेश है बातचीत के मुख्य अंश...

आपकी सरकार मातृशक्ति को किस तरह सम्मानित करना चाहती है?

प्रदेश के विकास में मातृशक्ति को सम्मानित करते हुए अगले दो वर्ष हमने मातृशक्ति को समर्पित किया है. देवभूमि के सामाजिक, आर्थिक ताने-बाने का आधार ही हमारी मातृशक्ति है. हमारा प्रयास है कि प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंसपेक्टर अवश्य हो. नंदा देवी सेंटर आफ एक्सिलेंस फॉर हैण्डलूम की स्थापना की जाएगी और हम अगले तीन माह में 20 हजार महिला उद्यमी तैयार करेंगे.

विपक्ष प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?

हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने का सौ प्रतिशत प्रयास कर रही है. राज्य की सुरक्षा, शान्ति और कुपोषण उन्मूलन में सभी उत्तरादायित्व हैं. शहरी क्षेत्रों में निर्धनों को भोजन की सुविधा के लिए इंदिरा अम्मा भोजनालय 20 रुपये में भर पेट भोजन की योजना शुरू की है और पूरी रात शहरी क्षेत्र में इसका लाभ निर्बलों को मिल रहा है. राज्य में पेशे के आधार पर पेंशन दी जा रही है. हमारी सरकार ने किसान, कलाकार, शिल्पकार, लोक कलाकारों, निर्माण कर्मी आदि के साथ बाजीमारी एवं जागरियों को पेंशन योजना में समाहित कर कारीगरों, कलाकारों और सृजनकारों को सम्मानित करने का प्रयास किया है.

राज्य की जनता को राज्य निर्माण का लाभ अभी तक नहीं मिला. इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है?

आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड दृढ़तापूर्वक विकास के पथ पर बढ़ रहा है. राज्य के वासियों के दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि श्री केदारनाथ सहित चारों धामों में यात्रा अपने पुराने स्वरूप में आ चुकी है. इस वर्ष 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सुगमता पूर्वक दर्शन का लाभ कमाया. हमारी सरकार सुरक्षित व सुगम उत्तराखंड का संदेश देश व दुनिया को देने में सफल हुई है.

ज्ञान एवं देवत्व के कारण उत्तराखंड को देवभूमि का गौरव प्राप्त है. इस गौरव को बरकरार रखने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है?

देवभूमि को गौरवान्वित करने के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयत्नशील है. राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. शिक्षा की श्रेष्ठता की हर कोशिश सरकार कर रही है. प्रत्येक ब्लॉक में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय के साथ ही पांच-पांच मंडल विद्यालय भी विकसित किए जाएंगे. उन्नत शिक्षा, खेती, हस्तकला एवं शिल्पकला संरक्षण देवभूमि की आर्थिक उन्नति के तीन महामंत्र हैं.

उत्तराखंड सास्कृतिक संदेश देने वाला राज्य है. संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

हरेला, झूमैलो एवं घी संक्रांत के आयोजन में जन सहभगिता ने हमारी सरकार को उत्साहित किया है. हमने उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में समन्वित व प्रभावी, कार्ययोजना पर अमल प्रारंभ किया है. देवभूमि की बहुरंगी संस्कृति, लोक उत्सवों एवं लोक कलाओं के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं.

राज्य के आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप राज्य का गठन नहीं हो पा रहा है.

हमारी सरकार पूरी तरह से राज्य के आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप और उत्तराखंड निमार्ण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है. आनंदोलनकारियों की चाहत है कि सर्वाधिक जोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर हो. पारंपरिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, बल्कि सरकार ने बोनस भी देने का निर्णय लिया है. उनकी मांग सरकार स्वयं पूरा कर रही है. पेठा, लौकी, कद्दू व मुमड़ा के लिए क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं. दूध पर प्रति लीटर 4 रुपये बोनस राशि देने का सकारात्मक परिणाम मिला है. मेरा पेड़, मेरा मन की योजना के तहत गांवों में चारा प्रजाति के वृक्ष लगाने को प्राथमिकता दी गई है. भीमल कड़ाली, भांग, रामबास आदि स्थानीय रूप से उत्पादित होने वाले पौधे के रेशों के लिए बोर्ड का गठन किया गया है. पहाड़ों में चकबंदी हमारे सरकार की उपलब्धी होगी.

लोगों का मानना है कि राज्य पर्यटन के मामले में पिछड़ रहा है. प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपके पास क्या योजना है?

परंपरागत मेलों, त्योहारों व संस्कृति को पर्यटन के साथ जोड़ा गया है. हम नए गंतव्यों को विकसित कर रहे हैं. ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. सुमन सरोवर जैसे स्थल नए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल होंगे. नंदा राजजात यात्रा, कावड़ यात्रा की भांति ही अर्द्धकुंभ का सफल आयोजन हमारी उपलब्धि होगी. ■

देवभूमि में आडवाणी अलग-थलग दिखे

उत्तराखंड के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका रही है. जब भी आडवाणी ने देवभूमि में कदम रखा, पूरी भाजपा उनका अभिनंदन करने के लिए उतावली दिखती थी. भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस समय गर्दिश में चल रहे सितारे ही हैं कि आडवाणी के देहरादून प्रवास के दौरान एक भी भाजपा का बड़ा नेता उनका हाल चाल तक लेने नहीं गया. आडवाणी ने खुद भी कभी ऐसी सियासी तनहाई की उम्मीद नहीं की होगी. उनके करीब देहरादून प्रवास के दौरान पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं दिखा. देहरादून में भाजपा के भीष्म पितामह व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अलग-थलग दिखे. बिहार चुनाव में हार के बाद भाजपा के चार वरिष्ठ नेताओं ने उनके नेतृत्व में हार की समीक्षा करने को कहा और हार के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की बात कही. वरिष्ठ नेताओं द्वारा समीक्षा की बात कहने के बाद मानो पार्टी में भूचाल आ गया. पूरी भाजपा अपने दिग्गजों द्वारा कही गई सच्चाई से पीछा छुड़ाती दिखी. बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पूरा मीडिया आडवाणी से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन आडवाणी ने मीडिया से यह कर पल्ला झाड़ लिया कि जाइए प्लीज हमें कुछ नहीं कहना है. अयोध्या के राम मंदिर के आन्दोलन के नायक की इस खामोसी ने जनता में इतने सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाजपा को यह चुप्पी आने वाले दिनों में भारी पड़ेगी. आडवाणी को इस स्थिति में एक मात्र सहारा परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द मुनी ही नजर आए. ■

-रेनू शर्मा

गांधी जी व डॉ. आम्बेडकर एक दूसरे के पूरक हैं : हरीश रावत

बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ऐसे महापुरुष थे, जिन्हें हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महसूस करते हैं. आर्थिक, सामाजिक, विधि सभी क्षेत्रों में आज भी लगता है, जैसे डॉ. आम्बेडकर हमारे साथ खड़े हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं. बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि संविधान के प्रति निष्ठा रखकर बाबा साहब द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास हर नागरिक को करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने घंटाघर स्थित बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के उन्नत व आधुनिक भारत में जब असहिष्णुता की बात हो रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय कुरितियों व रूढ़िवादिता के खिलाफ संघर्ष करने में बाबा साहब को कितना विरोध का सामना करना पड़ा होगा. लेकिन महात्मा गंधी, बाबा साहब आम्डेकर व पं. जवाहर लाल नेहरू ने मिलकर देश व समाज को रूढ़िवादिता से निकालकर एक नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया. गांधीजी व डॉ. आम्बेडकर एक दूसरे के पूरक थे. दोनों ने मिलकर मानवता को सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया. देश के महान संविधान के प्रति निष्ठा रखकर व असहिष्णुता व रूढ़िवादिता का विरोध करना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा. संविधान के सिद्धांतों की रक्षा करना आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है. पिछले 67 वर्षों में देश के विकास की प्रवाहित धारा की दिशा को बनाए रखना है. लेकिन प्रदेश के मुखिया रावत के बाबा साहब को महिमा मंडित करने के कुछ घंटे बाद ही देहरादून में घंटाघर स्थित डॉ. आम्बेडकर पार्क में डॉ. भीमराव आम्बेडकर के 60वें परिनिर्वाण दिवस पर बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में विश्व बौद्ध संघ के अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय विद्वान आर.बी.के बौद्ध ने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है. यह आरोप लगाकर आर.बी.के बौद्ध ने रावत के कथन पर पानी फेर दिया. ■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

पहली बार पंचायत प्रमुख बनेंगे उपेक्षित आदिवासी

पृष्ठ 18 का शेष

अधिकार की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका संख्या-46821/2010 दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनील अंबानी और काशी नाथ पांडे की पीठ ने 16 सितंबर, 2010 को दिए फैसले में साफ कहा है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल जाति समुदाय के लोगों का आबादी के अनुपात में विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार उनका संवैधानिक आधार है, जो उन्हें मिलना चाहिए. पीठ ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आज्ञा(सुधार) अधिनियम-2002 लागू होने के बाद राज्य में आदिवासियों की जनगणना नहीं हुई है. पीठ ने साफ कहा कि 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल जातियों की जनगणना अलग-अलग कराई गई थी और इसका विवरण विकासखंड और जिला स्तर पर भी मौजूद है. इसकी सहायता से अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई जातियों की आबादी को पता किया जा सकता है. पीठ ने आदिवासियों के हक में फैसला देते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों में सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के कारण पंचायत चुनाव-2010 में उच्च न्यायालय का आदेश लागू नहीं हो पाया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने जनगणना-2011 के आंकड़ो के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2015 में अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी के आधार पर उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी हैं.

वहीं आदिवासी पहचान के लिए जूझ रही सूबे की कोल, कोरबा, मझवार, उरांव, मलार, बादी, कंवर, कंवराई, वनवासी सरीखी जातियों को अपनी मूल पहचान पर यह अधिकार हासिल करने के लिए अभी और संघर्ष करना होगा, क्योंकि राजनीतिक गुणा-भाग में जुटे सियासतदानों ने उन्हें अभी भी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में बनाए रखा है, जबकि इन जातियों की सामाजिक स्थिति भी इन जिलों में अन्य जनजातियों के समान ही है. अगर हम इनके संवैधानिक अधिकारों पर गौर करें, तो कोल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, कोरबा बिहार, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में, कंवर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मझवार मध्य प्रदेश में, धांगड़ (उरांव) मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, बादी (बर्दा) गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में हैं. उत्तर प्रदेश में भी इन जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति अन्य प्रदेशों में निवास करने वाली आदिवासी जातियों के समान ही है, जो समय-समय पर सर्वेक्षणों और मीडिया रिपोर्टों में सामने आता रहता है. ■

सपा सरकार की पहल भी काम नहीं आई

उत्तर प्रदेश में अगस्त, 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी. उसने पहली बार राज्य के आदिवासी जिलों में विभागीय सर्वेक्षण कराया था. इसमें सामने आया कि राज्य में आदिवासियों की संख्या 2001 की जनगणना के 1,07,963 से बढ़कर 6,65,325 हो गई थी. हालांकि उसका यह सर्वेक्षण गोंड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड़, खरवार, खैरवार, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, चेरो, भुईया, भुनिया जैसी आदिवासी जातियों के काम नहीं आई. जनगणना-2011 के अनुसार अब यह आबादी 11,34,273 हो गई है, जो राज्य की आबादी का 0.57 प्रतिशत के करीब है. इस आधार पर राज्य की विधानसभा में दो सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गई हैं. इनमें सोनभद्र की आदिवासी बहुल दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीटें शामिल हैं. अपनी मूल पहचान पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा. अगर जिलेवार बात करें, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सोनभद्र में 3,85,018, मिर्जापुर में 20,132, वाराणसी में 28,617, चंदौली में 41,725, बलिया में 1,10,114, देवरिया में 1,09,894, कुशीनगर में 80,269 और ललितपुर में 71,610 है. सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जिले की आबादी का 20.67 प्रतिशत है, जो राज्य में किसी भी जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या से अधिक है. सोनभद्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या घटकर 22.63 प्रतिशत हो गई है. जनगणना-2001 के अनुसार यह 6,13,497 थी, जो जिले की आबादी का 41.92 प्रतिशत थी. विभागीय सर्वेक्षण-2003-04 के अनुसार सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 3,78,442 थी.

उत्तर प्रदेश शासन विभागीय जनगणना-2003

उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-111, भा0स0/26.03.2003-3(सा)/2003, दिनांक-03.07.2003 में अधिसूचित जनपद-सोनभद्र में अनुसूचित जनजातियों की सूची

क्रमांक	जाति	जनसंख्या
1	गोंड़	1,30,662
2	खरवार	73,212
3	चेरो	60,578
4	बैगा	32,212
5	पनिका	26,806
6	अगरिया	18,383
7	राजगोंड़	14,518
8	भुईयां	14,218
9	खैरवार	2,513
10	पठारी	2,374
11	पहरिया	1,367
12	पंखा	1,324
13	भुनिया	275
14	धुरिया	0
15	नायक	0
16	ओझा	0
योग		3,78,442

रक्षा हितों की अनदेखी कर यूपी में हो रही है हवाई अड्डे की राजनीति

अखिलेश की जिद पर वायुसेना की ना

अंशु दीनमणि

देश के लगभग 93 हवाई अड्डे भारी घाटे की चपेट में हैं. इनमें लखनऊ का हवाई अड्डा भी शामिल है. नागर विमानन मंत्रालय की सूचना के अनुसार इन हवाई अडडों को प्रचालन की कमी के कारण यह नुकसान उठाना पड़ रहा है. घाटे में चल रहे हवाई अड्डे के सुचारु रूप से चलाने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई अन्य हवाईअड्डों को सक्रिय करने पर आग्रही हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं. अखिलेश यादव हवाई अड्डों की राजनीति के लिए देश के रक्षा हित की भी तिलांजलि देने पर तुले हैं. आगरा के नजदीक हिरनगांव में हवाई अड्डे की स्थापना की जिद पर अड़ी राज्य सरकार को आगरा स्थित वायुसेना के अति संवेदनशील हवाई अड्डे की कोई फिक्र नहीं हो रही.

लखनऊ हवाईअड्डे का घाटा 64 करोड़ है. पिछले तीन साल में लखनऊ हवाई अड्डे को सौ करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है. घाटे में चल रहे हवाई अड्डों को लाभ में चलाने की योजना पर काम किया जाना जरूरी है. इसके लिए इन अड्डों पर उड़ान के साथ-साथ कार्गो गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक है. विमानों की अपेक्षित आवाजाही नहीं होने और उस अनुरूप यातायात संचालित नहीं होने से नुकसान हो रहा है. ऐसी विषम स्थितियों में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा के निकट हिरनगांव में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ग्रेटर नोएडा के जेवर हवाई अड्डे की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं. अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आगरा के निकट फिरोजाबाद जिले के हिरनगांव में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ग्रेटर नोएडा के जेवर में हवाई अड्डे की स्थापना से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्रतापूर्वक समाधान कराने का अनुरोध किया है. अखिलेश का मानना है कि इससे अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी आगरा में प्रति वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों को सीधे अन्तरराष्ट्रीय वायुसेवा की सुविधा मिल सकेगी.

अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में बताया है कि आगरा आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों को अन्तरराष्ट्रीय वायु सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आगरा में हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए आगरा के निकट जनपद फिरोजाबाद में हिरनगांव स्थल का चयन भी किया जा चुका है. हिरनगांव में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं. इन आपत्तियों के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा परीक्षण करते हुए यह सुझाव दिया गया कि इस परियोजना के तहत यदि आगरा में एयरफोर्स के वर्तमान खेरिया एयरपोर्ट के समानान्तर रन-वे बनाया जाए तो रक्षा मंत्रालय की आपत्ति का निराकरण हो सकता है. किन्तु रक्षा मंत्रालय द्वारा इस वैकल्पिक सुझाव पर भी आपत्ति की गई. इन आपत्तियों में एक आपत्ति यह भी है कि स्वारा में एरोस्टेट यूनिट की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि हवाई अड्डे हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट है.

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि एरोस्टेट यूनिट अभी तक स्थापित नहीं हुई है और इसके लिए अभी तक भूमि का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है. इन तथ्यों के आलोक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रकरण के समाधान हेतु रक्षा मंत्रालय को समुचित निर्देश देने का अनुरोध किया था. रक्षा मंत्री ने 26 मई 2015 के पत्र द्वारा हिरनगांव साइट पर रक्षा मंत्रालय की आपत्ति को उचित बताते हुए आगरा में मौजूदा एयरपोर्ट पर सिविल इन्क्लेव का विकल्प सुझाया है. अखिलेश ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के मद्देनजर उनके द्वारा प्रधानमंत्री को प्रेषित 7 जुलाई 2015 के अपने एक अन्य पत्र द्वारा विकल्प के रूप में अन्य दो साइट, जनपद इटावा का सैफई एयरपोर्ट तथा जनपद आगरा की तहसील बाह के भदरौली नामक स्थान का प्रस्ताव भेजा गया था. इसमें यह अनुरोध किया गया था कि इन प्रस्तावों का परीक्षण केंद्रीय रक्षा मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संयुक्त रूप से करा लिया जाए और उपयुक्त साइट के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जाए. इस पत्र के जवाब में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने यह अवगत कराया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थलों का एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (प्री-फीजिबिलिटी स्टडी) कराता है, जिसके लिए सूचनाएं तथा परामर्श प्रभार 11 लाख 66 हजार 105 रुपये आवेदक द्वारा जमा किया जाना होता है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित स्थल का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कंसल्टेन्ट की संयुक्त टीम द्वारा पहले ही किया जा चुका है. जिससे स्पष्ट है कि भारत सरकार के संबन्धित मंत्रालयों द्वारा प्रकरण में तत्परता बरते जाने से राज्य सरकार की इस परियोजना का शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वयन हो सकेगा और आगरा के निकट हवाई अड्डे की स्थापना से अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आने वाले देसी एवं विदेशी पर्यटकों को सीधे आगरा में अन्तरराष्ट्रीय वायुसेवा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ग्रेटर नोएडा में जेवर नामक स्थान पर सार्वजनिक-निजी सहभागिता के आधार पर एक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसके लिए सभी आवश्यक क्लीयरेन्स भी प्राप्त हो गई थी. इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा केन्द्रीय नागर विमानन सचिव को लिखे गए पत्र में सम्पूर्ण स्थिति का विस्तार से वर्णन है. राज्य सरकार इस परियोजना के अनुसार जेवर में भी एक उच्च स्तरीय हवाई अड्डा बनाना चाहती है. ■

अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में बताया है कि आगरा आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों को अन्तरराष्ट्रीय वायु सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आगरा में हवाई अड्डे की स्थापना का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए आगरा के निकट जनपद फिरोजाबाद में हिरनगांव स्थल का चयन भी किया जा चुका है. हिरनगांव में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं.

लखनऊ हवाईअड्डे का घाटा 64 करोड़ है. पिछले तीन साल में लखनऊ हवाई अड्डे को सौ करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है. घाटे में चल रहे हवाई अड्डों को लाभ में चलाने की योजना पर काम किया जाना जरूरी है. इसके लिए इन अड्डों पर उड़ान के साथ-साथ कार्गो गतिविधियों को बढ़ाना आवश्यक है. विमानों की अपेक्षित आवाजाही नहीं होने और उस अनुरूप यातायात संचालित नहीं होने से नुकसान हो रहा है.

हवाई अड्डे के नाम पर धंधा करने वालों को झटका

फिरोजाबाद जिले के हिरनगांव में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वायुसेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से कई धंधेबाजों के सपने टूट गए. हवाई अड्डे की सियासत करने वालों को भी झटका लगा है. हिरनगांव में हवाई अड्डा बनने की घोषणा होते ही वहां धंधेबाजों ने अपने धंधे का रोड-मैप बनाना शुरू कर दिया था. राज्य सरकार की मंजूरी के बाद जब सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई, तब यकीन किया जाने लगा कि हिरनगांव में एयरपोर्ट बनना सुनिश्चित है. बस, एयरपोर्ट पर तमाम राजनीति शुरू हो गई. सपा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश की. सपा के कई प्रमुख मंचों से कहा गया कि सपा की वजह से ही जनपद को एयरपोर्ट मिल रहा है. श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ में कांग्रेस भी सक्रिय हो गई थी. कांग्रेस ने कहा था कि मामला केंद्र सरकार से जुड़ा था और कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने हिरनगांव में एयरपोर्ट मंजूर कराया था. कांग्रेस के दावे के बरक्स समाजवादी पार्टी कहती रही कि सपा सांसद रामगोपाल यादव के प्रयासों से हिरनगांव में एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिली थी. लेकिन मंजूरी तो मिली ही नहीं थी. वायुसेना और रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के बाद हवाई अड्डे का निर्माण लटक गया और राजनीतिक दलों को झटका लग गया. सपा इस झटके से अधिक आक्रांत है, लिहाजा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनका शासन-तंत्र केंद्र को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहा है. एयरपोर्ट के लिए जमीन की घोषणा होते ही जमीन की खरीद-फरोख्त का धंधा करने वालों ने आसपास के किसानों से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया था. एयरपोर्ट का प्रारूप तय नहीं हुआ था, लेकिन जमीन में निवेश करने वाले लोग किसानों को अपनी आलीशान कोठियों में दावत पर बुलाने लगे थे. कई किसानों को खेतों का सौदा कर एडवांस रकम तक दे दी गई थी. रक्षा मंत्रालय की आपत्ति ने निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है. ■

कसया मसला पर पेच

कुशीनगर के कसया में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण का मसला फंस गया है. अब यहां हवाई अड्डे के लिए चार सौ एकड़ और जमीन चाहिए. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आठ सदस्यीय टीम ने पिछले दिनों हवाईअड्डे व अधिग्रहीत भूमि के मानचित्र का निरीक्षण किया. विशेषज्ञ टीम ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए मानक के अनुसार और 400 एकड़ भूमि की जरूरत जताई है. टीम ने बताया है कि अधिग्रहीत भूमि टेढ़ी-मेढ़ी है, जबकि हवाईअड्डे के लिए आयताकार भूमि चाहिए ताकि रन-वे को नियोजित ढंग से और मानक के अनुसार बनाने में सुविधा रहे. टीम ने बताया कि मानक के हिसाब से 3.5 किलोमीटर लम्बा रन-वे बनना है. इसको लेकर लंबाई तो पर्याप्त है, लेकिन चौड़ाई कहीं-कहीं बहुत कम है. विस्तृत चर्चा के बाद टीम ने यह भी कहा कि जरूरत तो और सौ एकड़ की है, लेकिन अगर 250 एकड़ भूमि भी मिल जाए, तो काम चल सकता है. इसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी. अधिग्रहण के बजाए किसानों से जमीन सीधे खरीदी जाएगी. जिलाधिकारी ने काश्तकारों से बात कर अधिग्रहण के बजाए उनसे सीधे भूमि खरीदने का मन बनाया है. लेखपाल को निर्देश दिया गया है कि एक-एक गांव की सूची बनाएं ताकि उसे शासन को भेजा जा सके. कसया हवाई अड्डे के लिए प्राधिकरण की टीम ने जिन जगहों पर चौड़ाई कम होने और अतिरिक्त जमीन की जरूरत बताई है उनमें मिश्रौली, नरायनपुर, नरकटिया खुर्द, कुरमौटा, शाहपुर, विशुनपुर विंदवलिया, बेलवा दुर्गाराय, बेलवा रामजस के किसानों की जमीन शामिल है. यहां बनने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अधिसूचना जारी कर 11 गांवों के काश्तकारों से 404.35 एकड़ भूमि ली गई थी. कुछ काश्तकारों ने अपनी मर्जी से 47.24 एकड़ भूमि दी थी. इसके अलावा 21.61 एकड़ भूमि सभी गांवों की ग्राम सभाओं की है, जबकि पहले से बनी हवाईपट्टी की भूमि 111.45 एकड़ में है. यानी कुल मिलाकर 584.65 एकड़ भूमि अब तक ली जा चुकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com